



आरत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 65]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 1979/फाल्गुन 18, 1900

No. 65]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 1979/PHALGUNA 18, 1900

इस भाग में अधिक पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक पूर्वत तथा साइकारता भंग्रालय

(वाणिज्य विभाग)

प्रायात आपात नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 17—आईटीसी/पीएन/79

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1979

विषय:—1978-79 के लिए उच्च सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अंतर्गत निजी खेत्र और सार्वजनिक खेत्र प्रायातात्त्व के लिए साइसेंस जारी करने के संबंध में नियम तथा शर्तें

मिसिस्ल सं. आईटीसी/39/13/76.—1978-79 के लिये उच्च सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अंतर्गत वित्त युक्त किए गए प्रायात साइसेंसों को जारी करने के संबंध में लागू होने वाले नियम तथा शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिणाम 1 तथा 2 में दी गई हैं जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है।

वाणिज्य भंग्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 17 आईटीसी ० सो० (पी०एन) / 79
वित्तांक 9-3-1979 के लिए परिणाम-1

उच्च सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अंतर्गत सार्वजनिक खेत्र प्रायातात्त्व के लिए साइसेंस जारी करने के लिए शर्तें

खण्ड—1 सामान्य

1(1) नीवरलैण्डस इन्वेस्टिरिंग्स बैंक वीर प्रार्थिकिलिंग्स सेन्ट्रल एन०वी० द्वारा प्रदान किए गए 1977-78 के लिये उच्च सामान्य प्रयोजन क्रेडिट को विकाशसील देशों के लिये खोल दिया गया है। तबनुसार इस क्रेडिट के प्रधीन वित्तयुक्त किए जाने वाले माल एवं पद्ध बहुत एवं डस्से सम्बन्ध आनुवागिक सेवाएं नीवरलैण्डस से प्रायात की जा सकती हैं। और परिणाम 'क' के रूप में "नीवरलैण्ड द्वारा द्विपक्षी विकास छूट के अन्तर्गत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिये भार्गदान" सूची में सम्मिलित सभी देश (प्राकृतिक-1) इस क्रेडिट के अन्तर्गत "पात्र खोल देश" होंगे। क्रेडिट के संबंध में वितरण की अन्तिम तिथि 31-12-1981 होगी।

1(2) किस्तु पात्र से इसर खोल देशों से रसायन के संबंध में 10% की सीमा तक और अन्य प्रायातात्त्व के संबंध में 20 प्रतिशत की सीमा तक के संघटकों को इस क्रेडिट के अंतर्गत वितरण किए जाने के लिये विचार किया जा सकता है।

1(3) इस क्रेडिट के अन्तर्गत वितरण के लिये पात्र खोल देशों से उपर्युक्त खण्ड 1(2) में संकेतित सीमा से अधिक संभरण को संपूर्ण बनाने के लिये पात्र से भिन्न देशों से माल और सेवाओं के सीमित संभरणों पर भी विचार किया जा सकता है। इसके लिये नीवरलैण्डस की सरकार का विधिविषय अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

खण्ड 2—प्रायात साइसेंस जारी करना

2(1) प्रायात साइसेंस 12 मास की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिये नागर-सीमा-भाड़ा के क्षेत्र पर जारी किया जायेगा। वैध अवधि में वृद्धि के लिये साइसेंसधारी को चाहिये कि वह वैध अवधि के भीतर ही

न्यूबंद्र लाइसेंस प्राधिकारी में संपर्क स्थापित करे जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग से परामर्श लेगा।

(2) पक्षके आदेश नीदरलैण्ड में सुनुवार संभरकों या अनुबन्ध 1 में उल्लिखित देशों का लागत बीमा भाड़ा/लागत तथा भाड़ा के आधार पर अवधि दिए जाने चाहिये और आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 4 मास की भीतर ही आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिये। यदि पक्षके आवेदन देने का नियंत्रण निर्धारित चार मास की अवधि के भीतर नहीं हो पाता है तो लाइसेंस-धारी को आविधि कि वह जैसा भी मामला हो मुश्व नियंत्रक आयात नियात को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारियों को इसका कारण बताते हुए कि क्यों नहीं प्रारंभिक वैध अवधि के भीतर ही आदेश देने का काम पूरा हो सका इसके श्रेष्ठिय एवं आयात के साथ आवेदन देने की अवधि में वृद्धि के लिए आवेदन पर विभाग प्रत्येक मामले में पादना के आधार पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा जो और चार मास की अवधि की वृद्धि दे सकते हैं। नेकिन यदि आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से 8 मास से अधिक की वृद्धि की मांग की जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपत्राव रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा अर्थ कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) वित्त मंत्रालय को भेजे जाने चाहिये।

(3) लाइसेंस पर (उच्च सामान्य प्रयोजन क्रेडिट) अंकित होगा और यह उस सार्वजनिक सूचना की संज्ञा का संकेत करेगा जिसके अन्तर्गत यह लाइसेंस जारी की जाती है। प्रथम तथा द्वितीय प्रत्यय के लिये लाइसेंस कोड "एस"/"एमएन" होते हैं। इस लाइसेंस कोड का उल्लेख सभी पोतलबान प्रेसों में होना चाहिये और साथ ही साथ रूपया जमा करते समय दिव्यं वैक को प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित प्रपत्र "एस" में इसका उल्लेख होना चाहिये।

(4) ऐसे ही आयातक आयात लाइसेंस प्राप्त करता है उसे चाहिये कि वह इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी के साथ वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) को एक रिपोर्ट भेजें:—

(1) आयात लाइसेंस की संख्या और विवाक

(2) मूल्य

(3) यदि कोई हो तो आयात लाइसेंस में संकेतित मुद्रा विनिमय दर

(4) वह तारीख जिस तक आर्थिक कार्य विभाग को संविदा की प्रतिया में जाने वाला जाएगा।

उच्च—3 संविदा को पूर्ण करना

(1) इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तबान के लिये पात्र संविदा का अनुत्तम मूल्य भी एप्प-25 000 होगा।

(2) आयात लाइसेंस के मध्ये एक संविदा की जानी चाहिये। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा करने के लिये अनुमति दी जायेगी जिसके लिये आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख के तुरन्त बाद ही वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिये।

(3) माल के आयात के लिये संविदा और नीदरलैण्ड से सेवाओं और पात्र स्त्री देशों का नियन्त्रण अनुबन्ध-1 में यथा उल्लिखित माल और सेवाओं की प्राप्ति के लिये मार्ग दर्शन को व्यापार में रखते हुए किया जाना चाहिये।

(4) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर माल और सेवाएं आपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली के माध्यम से प्राप्त की जाएगी:—

(क) जहाँ नीदरलैण्ड आयातों के लिये प्रस्तुताव या केवल एक माल छोत है; या

(ख) जहाँ आयातों का मूल्य भी एक एप्प 1.25 मिलियन से कम है; या

(ग) जहाँ ऐसी क्रियाविधि लागू नहीं है या उपयुक्त नहीं है।

इस मामले में नीदरलैण्ड सरकार और भारत सरकार के बीच कागद किसी और अधिक उचित क्रियाविधि आधार पर संभरण के लिये संविदा पूर्ण हो जाने से पूर्व ही नियन्त्रण रूप में तय हो जाना चाहिये।

(5) निम्नलिखित मामलों में आपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली का सहारा लेना भी आवश्यक नहीं होगा:—

(क) जहाँ क्रेता के पास अपने उपकरण के पर्याप्त मानकीकरण की बनाए रखने के लिये युक्तियुक्त कागण है।

(ख) उन मामलों में जहाँ विषयाधीन अधिप्राप्ति की प्रकृति के कारण योग्य संभरकों की संख्या सीमित है और क्रेता की मार्किट जानकारी ऐसी है कि उससे यह आशा की जा गकती है कि वह योग्य संभरकों को जानता हो।

(ग) जहाँ भारतीय आयातकों और विदेशी संभरकों के बीच चल रहे काँपान सम्बन्ध और नीदरलैण्ड और/या विकासशील देशों में उपलब्ध और समरूप संभरकों के क्षेत्र को व्यापार में रखते हुए काँपान यह भवित्वा है कि आयात केवल नीदरलैण्ड से ही प्रभावी होने चाहिए। ऐसे मामलों में माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन (अनुबन्ध-1) की कठिका 31 से 39 में नियन्त्रित अधिप्राप्ति का नियम अपनाया जाना चाहिए।

(6) निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में क्रेता किसी भी एकमात्र संभरक से सीधे ही माल व्यापार सकता है:—

(1) वाणिज्यिक आयातक द्वारा अधिप्राप्ति में पंजीकृत ब्रांड नाम की वह पृष्ठवस्तु शामिल होती है जो आयातक द्वारा पुनः बेचने के लिए है और जिसके लिए आयातक संभरक का नियमतः अधिकृत वितरक है या व्यापारी है और जिसके लिए संभरक एकमात्र वितरक है;

(2) वाणिज्यिक आयातक द्वारा अधिप्राप्ति में वह पृष्ठवस्तु शामिल होती है जो विनिर्माण प्रक्रियागत करने या अन्तिम उत्पाद के सज्जीकरण और पुनः बिक्री के लिए प्राप्त की जाती है और जिसके लिए आयातक संभरक का नियमतः अधिकृत वितरक है या व्यापारी है और जिसके लिए संभरक विनिर्माणकर्ता है;

(3) विशेष डिजाइन या तकनीकी आवश्यकताओं के कारण पुरुजों की अवलोकनीय की सुनिश्चय करते हेतु अधिप्राप्ति केवल एक स्रोत से की जा सकती है;

(4) आयातक एक ऐसा विनिर्माणकर्ता है जिसके उपकरण और कठोर माल का फार्मूला ऐसे कठोर माल की, विशेष किसी के साथ अधिक से अधिक उत्पाद के लिए बनाए गए हैं जो केवल एक ही ब्रांड में प्राप्त किए जा सकते हैं,

(5) आयातक आपचारिक अंतर्राष्ट्रीय बोली के अन्तर्गत मूल रूप से की गई अधिप्राप्ति की जाहाजा आहता है या फिर से उसे प्राप्त करना चाहता है व्यापते की मूल अधिप्राप्ति की तुलना में प्रनुप्रक अधिप्राप्ति कम है, और कुछ अवधार पर ही की जाती है और जब मूल अधिप्राप्ति के मम्बन्ध में नियमण कार्य अभी चल रहा है या मूल अधिप्राप्ति के तुरन्त बाद ही की जाती है;

(6) सौदे का मूल्य भी एप्प 1.25 मिलियन से कम है।

(7) परामर्शदाता फर्मों के बाजार के लिए आपचारिक प्रतियोगी बोली क्रियाविधि की प्रावधारणा नहीं है। नेकिन, भारतीय फर्मों द्वारा परामर्शदाता फर्मों को सुझावों के लिए नियमण भेजने से पूर्व ही ऐसी काँपी फर्मों की एक सूची वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग

(उच्चयू ह-3 अनुभाग) को भेजी जानी चाहिए। इसके बाद सूची नीदरलैण्ड की सरकार को भेजी जाएगी जो इसे स्वीकृति दे सकती है या परामर्शदाता को संबद्ध की रह कर सकती है और नोटरलैण्ड में परामर्शदाती बोर्ड की जानकारी के आधार पर इस मूल्य को बढ़ाने के लिए सुनाय दे सकती है।

3(8) जहाँ ग्रौपचारिक खुली यन्त्रराष्ट्रीय बोली के आधार पर माल की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव किए जाते हैं तो आयातक को चाहिए कि वह जैसे ही निविदा नोटिस भारतीय व्यापार पत्रिका या भारतीय निर्यात खुलेटिस में विज्ञापन के लिए भेजे जाएं उसी समय इनको तीन प्रतियों को वित्त संवालय, आर्थिक कार्य विभाग (उच्चयू ह-3 अनुभाग), तरी विली की अवगत कराने हुए भारत में नीदरलैण्ड के राजदूतावास की भेज दें।

3(9) खण्ड 2(2) में उल्लिखित “पुणित भारतीय” गई का पर्यंत है भारतीय लाइसेंस धारी द्वारा विवेशी संभरक को दिया गया वह ग्राहक जो बाद वाते के पुष्टिकरण अदिग्न द्वारा विवित् समर्पित हो या क्य संविदा जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विवित् हस्ताभित होता है। विवेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं पर आदेश और/या गेंगे भारतीय अभिकर्ताओं के पुष्टिकरण आवेदन स्वीकार्य नहीं है।

3(10) यदि संविदा इच संभरक के गाय तो गई तो तांत्रिका के लागत-स्वीकार-भाड़ा/लागत एवं भाड़ा मूल्य को इच गिल्डर में व्यक्त करना चाहिए और यदि संविदा पाल और देशों के संभरकों के साथ की गई हो तो उनकी मुद्रा में व्यक्त करना चाहिए।

3(11) संविदा में भुगतान की अवधिता नकद आधार पर होनी चाहिए अर्थात् पोतलदान दस्तावेजों को प्रदून करने पर विदेशी संभरकों, भारतीय आयातकों को किसी भी प्राप्तार का संबंध-पुरिधा उपलब्ध करने की स्वीकृत नहीं देंगे।

3(12) संविदा के मूल्य में मन्मिलित भारतीय अभिकार्ता के कमीशन की धनराशि का विशेष स्थान अंकित किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रूपण में किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा में प्रेषण स्वीकार्य नहीं होगा। नेकित गेंगे भुगतान लाइसेंस मूल्य के भाग के रूप में होंगे और इसमिल लाइसेंस के लिए वर्षान फिर जाएंगे।

3(13) क्य आवेश और संभरक के पुष्टिकरण आदेश के बत अप्रेजी में ही होने चाहिए।

3(14) संविदा में निम्ननिखित उत्तमताओं को विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिए।—

(1) संविदा भारत सरकार के अनुमोदन के प्रयोग है (यदि संविदा का मूल्य इच गिल्डर्स में 50,000 या इससे कम हो) और यह भारत सरकार तथा नीदरलैण्ड सरकार दोनों के अनुमोदन के अधीन है (यदि संविदा का मूल्य इच गिल्डर्स 50,000 से अधिक हो जाता है)।

(2) यह संविदा इच सामान्य प्रयोजन एंडिट के लिए लाइसेंस घोटों के अंतर्गत दी गई भुगतान क्रियावित्र द्वारा संचालित होगी और इस सम्बन्ध में भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के बावह ही यह प्रभावी होगी।

(3) “माल इच मूल्य/विनिर्माण के हैं” (नीदरलैण्ड में संभरकों के मामले में)

या

“माल मूल्य/विनिर्माण के हैं”
(पाल औत देशों के संभरकों के मामले में)।

(4) नीदरलैण्ड से आयात किए जाने वाले माल के लिए संभरकों को नीदरलैण्डस पूर्णी विवेशक बैंक को उस जिले के नीदर-

लैण्ड व्याजित्य मण्डन द्वारा जिनमें संभरक स्थानित है जाये किया गया/प्रमाणित किया हुआ इस बारे में एक प्रमाण-पत्र जो प्रतियों में देना पड़ेगा यह मान नाइरलैण्डम मूल का है। यह प्रमाण-पत्र भुगतान प्राप्ति करने समय प्रथम पाल नदात दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है प्रमाण-पत्र का एक नमूना अनुबन्ध-3 में दिया गया है। पाल लोन देशों के संभरकों के मामले में संभरकों को “माल और सेवाओं को अधिप्राप्ति के लिए मार्गवर्णन (अनुबन्ध-I) में दिया गया उद्गम में दिए गए उद्गम नियमों के अनुभाव एन.प्राइ.ओ. को माल के उद्गम का प्रमाण-पत्र देना पड़ेगा”।

3(15) जहाँ प्रवागत निषादन गार्टी के अधिकृत हो वहाँ संभरकों से बैंक गार्टी को प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए।

खण्ड—4 भारत सरकार/नीदरलैण्ड पूर्णी विवेशक बैंक द्वारा संविदा का अनुमोदन

4(1) संविदा पूर्ण होने के तुरन्त बाद ही आयातकों की आयात लाइसेंस की एक फोटो प्रति के साथ संविदा/संभरण आदेश की 5 फोटो या प्रमाणित प्रतियों वाजित्य संभानव, आर्थिक कार्य विभाग (उच्चयू ह-3 अनुभाग) को भेजने चाहिए। पाल लोत देशों के संभरकों के साथ साथ पूर्ण की गई संविदाओं के मामले में उनको 9 प्रतियों में जो जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आयातक के लिए प्रत्यन्धन-2 में अनिवार्य सूचना भी भेजना आवश्यक है।

4(2) जब संभरक संविदा ग्रौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय बोली या ग्रौपचारिक खुलिन्दा अंतर्राष्ट्रीय बोली पर आधारित हो तब निम्न-लिखित सूचना भी प्रस्तुत की जानी चाहिए—

(1) उस प्रकाशन का नाम जिसमें निविदा सूचना विज्ञप्ति की गई थी।

(2) उन पाटियों के नाम जिन्होंने पुलिसाल के मध्ये दाम बताए हैं।

(3) विशिष्ट प्रस्ताव को बुनने के लिए कारण और यह भी बताया जाए कि यह संविदा न्यूनतम तकनीकी उप्रूप्त बोरो थी।

4(3) यह संविदा दस्तावेज, प्राविधिक तथा जारी करने के लिए प्राविदेश, आयात लाइसेंस और बैंक गार्टी सही पाठ जाने हैं तो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग संविदा की प्रतियों को देंगे में भारत के राजदूतावास के माध्यम से इच प्राविधिकारियों को अनुमोदन के लिए भेजेंगा।

4(4) (क) 50,000 इच गिल्डर या इससे कम मूल्य की संविदाओं के सम्बन्ध में इच प्राविधिकारियों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के अनुमोदन के बारे में भारतीय आयातक को उनकी संविदा संभरण आदेश की प्रतियों डब राइफारियों को भेजना समय बता विद्या जाएगा।

4(4) (ख) 50,000 इच गिल्डर में अधिक संविदाओं के लिए, जैसे ही इच क्रेडिट के अन्तर्गत इच प्राविधिकारियों द्वारा संविदा के वित्तावास के लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, आयातक को यह सूचित कर दिया जाएगा कि उनकी संविदा प्रभावी हो गई है।

खण्ड—5 संभरकों को भुगतान

(क) भीवरलैण्ड के संभरकों को भुगतान

5(1) विकासशील देशों के लिए नीदरलैण्ड पूर्जानिवेशक बैंक, यदि हेंग को एक प्राविधिकार-पत्र (अनुबन्ध-7) के रूप में हेंग में भारत के राजदूतावास के माध्यम से पोतलदान दस्तावेज के मध्ये संभरकों के लिए भुगतान को प्राधिकृत करने हुए जारी किया जाएगा और संविदा आदि की प्रतियों के साथउत्ते इच प्राविधिकारियों को प्रवेषित किया जाएगा।

5(2) प्राधिकारपत्र की वैधता का सुनिश्चय संविदा में निर्दिष्ट वितरण प्रमुखों को ध्यान में रखने हुए किया जाएगा। किमी भी मामले में प्राधिकार पत्र, आयात लाइसेंस की वैधता के बाबत ऐसी होगा।

5(3) अंकि क्रेडिट के अंतर्गत सामान्यतः इच बैंक द्वारा संभरकों की भुगतान पोतलदान वस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के महे ही किए जाने हैं अतः इस क्रेडिट के अंतर्गत वितरण किए गए आयातों के लिए, रियायती घब्धि की सुविधा नागृ नहीं होगी।

5(4) संभरकों को पोतलदान /भुगतान प्राधिकार पत्र की वैधता घब्धि के भीतर पूरा न किया जाने के मामले में आयातक को वित मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभागों) के साथ प्राधिकारपत्र में उपर्युक्त वृद्धि के लिए समर्पक स्थापित करना चाहिए। यदि भारी गई वृद्धि घब्धि मूल आयात लाइसेंस की वैधता घब्धि से घब्धिक हो तो पुनः वैध आयात लाइसेंस की फोटो प्रति और बैंक से वह पत्र जिसमें बैंक गारंटी की वैधता घब्धि दी गई है, आवेदन-पत्र के साथ भेजी जानी चाहिए।

5(5) यदि प्राधिकार पत्र की वैधता घब्धि में वृद्धि के लिए आवेदन, प्राधिकार पत्र की वैधता नियि से 6 महीने की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हो जाती तो प्राधिकार-पत्र में प्रश्न्युक्त रोब धनराशि वापिस कर दी जाएगी और प्राधिकार पत्र अपने आप खत्म हो गया समझा जाएगा।

5(6) मूल परकार्य पोतलदान वस्तावेज नियराव रूप से नीदर-लैण्ड पूरी नियेषक बैंक द्वारा भारत में सम्बन्धित आयातक के बैंक को भेजे जाएंगे। वह बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी एक बैंक की आख्याती जिससे वह सुनिश्चय करने के बाबत ही सम्बन्धित आयातक को परकार्य वस्तावेज रिहा करने आवश्यक हो गया समझा जाएगा।

(1) सार्वजनिक सूचना सं. 8-प्राई० टी० सी० (पी० एम०)/76 दिनांक, 17 जनवरी, 1976 में यथा नियारित और मूल्य नियन्त्रक, आयात-नियारित की सार्वजनिक सूचनाओं में समय-समय पर यथा प्रधिसूचित या रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के मुद्रा-विनियम नियन्त्रण परिषदों के माध्यम से गणना की जाने वाली प्रक्रियत दर पर इच गिल्डर में संभरकों की भुगतान के समतुल्य रूप।

(2) विकासशील देशों के लिए नीवरलैण्ड पूर्जीगत निवेश बैंक एवं बैंक, वि हेंग द्वारा संभरकों को वास्तविक भुगतान की तारीख से आयातक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, टीस हुआरी, दिल्ली या रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली में समतुल्य रूपए के वास्तविक निवेश की तिथि तक नियित जमा की जाने वाली अपेक्षित धनराशि के लिए देवें उपर्युक्त (1) सार्वजनिक सूचना सं. 48-प्राई० टी० सी० (पी० एन०)/76 दिनांक 16 जून, 1976 के अनुसार प्रथम 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर और 30 दिनों की घब्धि से घब्धिक के लिए 15% वार्षिक दर के हिसाब से आज।

5(7) यह सुनिश्चय करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित भारतीय बैंक की होगी कि आयातक को आयात वस्तावेज सौंपने से पूर्व ही देय धनराशि सरकार के लेखे में ठीक प्रकार से जमा करा दी गई है। लाइसेंसधारी को यह भी सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि बैंकों से वस्तावेजों की सुपुर्दी लेने से पूर्व ही देय धनराशि ठीक प्रकार से सरकारी लेखे में जमा करा दी जाती है।

5(8) सार्वजनिक देश के आयातकों (केन्द्रीय सरकार के विभागों सहित) को अपेक्षित रूपया नियेष केबल विवेणी मुद्रा-विनियम के प्राधिकृत आयारियों के माध्यम से कराना चाहिए और सार्वजनिक सूचना सं. 184 प्राई० सी० (पी० एम०) 68 दिनांक 30 अगस्त, 1968 में यथा अपेक्षित लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति भी उनके द्वारा पृष्ठाकृत करवा

लेनी चाहिए। अपेक्षित प्रपत्र "एस" सम्बन्धित बैंक द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, बम्बई को भेज दिया जाएगा।

5(9) खण्ड 5(6) में उल्लिखित धनराशि का स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, टीस हुआरी आख्या, दिल्ली या रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के पास केन्द्रीय सरकार के लेखे में नियेष के लिए नियन्त्रित नियोगी प्राप्ति के अंतर्गत जमा की जानी चाहिए:—

"के—डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सेज डिपोजिट नाटियरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स

—→ 843—सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फॉर परमेजिम एट्सेट्रा एक्सेंट्रेशन एडवान्सेज एडवेंचर इच जनरल पर्सनल फैशिट 1978-79"

5(10) उपर्युक्त उल्लिखित रूपया नियेष की सूचना वित मंत्रालय नई दिल्ली आर्थिक कार्य विभाग, यूसीओ बैंक बिल्डिंग, पालियामेण्ट स्ट्रीट नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए और इसके याथ सार्वजनिक सूचना सं. 74-प्राई० टी० सी० (पी० एन०)/74 दिनांक 31 मई, 1974 और सं. 103-प्राई० टी० सी० (पी० ए०)/76 दिनांक 12-10-76 में नियारित प्रपत्र में प्राप्त किए गए मूल खाजाना खलान को भी भेजना चाहिए। प्राधिकार पत्र सं. 0 के सम्बन्ध में सूचना, विवेशी मुद्रा की वह धनराशि जिसके लिए रूपया नियोग किया गया है, उच संभरक को भुगतान की नियि, बाज़ को धनराशि और वह घब्धि जिसके लिए इसकी गणना की गई है, नियरावाद रूप से राजकीय बालान में सकेनित की जानी चाहिए।

(ल) पात्र खोत देशों से संभरकों को भुगतान

5(11) आयातक पत्र के प्रावेदनपत्र में यथा सकेनित संभरक के नाम में पात्र द्वारा देश में संभरक के बैंक के लिए साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत करने समय हुए एक प्राधिकार पत्र (अनुवन्ध-5 के रूप में) वित मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) द्वारा खोला जाएगा। उपर्युक्त प्राधिकार पत्र की प्रति के नाथ संविधा की प्रतियो भी होगी में भारत के राजदूतावास द्वारा इच प्राधिकारियों को प्रेयित की जाएगी।

5(12) पूर्व को कडिकाओं में उल्लिखित प्राधिकार पत्र की पात्रती के बाद आयातक का बैंक उक्त प्राधिकार पत्र के जारी होने की नारीश में 30 दिनों के भोतर और वैध आयात लाइसेंस के मद्दे अपने बैंकर के माध्यम से संभरक के नाम में एक साखपत्र खोलेगा इस दंबने में सूचना सहायता देखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, यूसीओ बैंक बिल्डिंग, पालियामेण्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजी जाएगी।

5(13) संभरक की भुगतान किए जाने के बाद संभरक का बैंक महायता देखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यूसीओ बैंक बिल्डिंग, पालियामेण्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को संभरक द्वारा विधिवत् पृष्ठाकृत प्रमाणपत्र के माथ इस सम्बन्ध में पोतलदान वस्तावेज के अपरकार्य सेट और बीजक की दो प्रतियों को भेजेगा। बाद बाले से भुगतान प्राप्त हो गए हैं।

5(14) संभरकों का बैंक संभरक के माल के उद्गम देश के सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र या एक सबूत (दो प्रतियों में) इस सम्बन्ध में प्राप्त करेगा कि वह माल और सेवाओं की घब्धिप्राप्ति के लिए मार्त वस्तावेज के नियमों के अनुसार है और उसे महायता देखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यूसीओ बैंक बिल्डिंग, पालियामेण्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजा।

5(15) आयातक को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैंक प्रभारों को छोड़कर बीजक/माल के नवान के मद्दे उनके द्वारा संभरक को किए गए प्रेषण के एक प्रमाणपत्र को सहायता देखा एवं सेवा परीक्षा नियंत्रक, वित मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यूसीओ बैंक बिल्डिंग, पालियामेण्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजे। आयातक को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैंक प्रभारों को छोड़कर बीजक/माल के लकान के मद्दे उनके द्वारा रियायती घब्धि की सहायता देखा एवं

ग्रन्थ वस्त्र—1

नीदरलैण्डस द्वारा द्विपक्षीय विकास अर्थ के अन्तर्गत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन

क सामान्य

1. ये मार्गदर्शन द्विपक्षीय अर्थ के अन्तर्गत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति को शामिल करते हैं जो कि भास्त्रकीय नीदरलैण्ड विकास महायाता कार्यक्रम का एक भाग है। ये अर्थ विकासणील देशों के लिए उपयोगी हैं। पात्र स्रोत देशों की सूची परिषिष्ठ 'क' के रूप में संलग्न है। इस सूची में प्राप्तवार्ता देश इसमें जामिल हैं। नीदरलैण्डस की सरकार पात्र स्रोत देशों खंड संभरण की कमी को पूरा करने के लिए पात्र स्रोत संबरण देशों से बाहर और वीमा कीमतों सहित माल और सेवाओं के वीमित संभरण के लिए व्यक्तिगत आधार पर गहमत हो सकती है।

2. नीदरलैण्डस का सरकार देशके लिए अवश्य ही संतुष्ट हो जाना चाहिए कि अर्थ गें प्राप्त लाभ का उपयोग, अर्थ व्यवस्था, कार्य-क्षमता, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निपक्षाना और पात्र स्रोत देशों के बीच विना किसी भेदभाव को ध्यान में रखते हुए और इन मार्ग दर्शनों में बताई गई अधिप्राप्ति क्रियान्वयिताओं के अनुमार किया जाना है।

3. कठिका 16 और 17 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए जिससे यह पता चलता हो कि किसी एक विशेष देश के एक विशेष संभरण का या मंभरकों का पक्ष लिया जा रहा है।

4. माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए अर्थ द्वारा अपनाए जाने वाले उद्गम के नियम और मियोजन इन मार्गदर्शनों के साथ परिषिष्ठ "क" के रूप में संलग्न कर दिए गए हैं।

5. ऐसे मामले में जहाँ अर्णी पर अधिप्राप्ति का सीधा प्रभाव नहीं पहला है तो वह ऐसी व्यवस्थाएं करेगा जिसे यह सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक है कि उनीददार इन मार्गदर्शनों का अनुपालन करता है।

6(1) अर्णी निम्नलिखित मामलों को छोड़कर औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय बोली के माध्यम से माल और सेवाएं प्राप्त करेगा :—

(क) जहाँ नीदरलैण्डस परम्परागत या आयाती के लिए केवल एकमात्र बोल है।

(ख) जहाँ आयाती का भूल्य डी० एफ० एन० 1.25 मिलियन से कम है।

(ग) जहाँ इस प्रकार की क्रियाविधि लागू नहीं होती या उपयुक्त नहीं है। इस मामले में नीदरलैण्डस सरकार और अर्णी देश के बीच करार किसी अन्य उचित क्रिया विधि से संभरकों को उनकी बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने में पूर्व ही पूरा तर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का करार राजकीय नीदरलैण्डस गजट्रानाथास के माध्यम से अर्णी द्वारा दो जाने वाली सभी गम्भीर जानकारी के आधार पर किया जाना है।

6(2) जहाँ आयाती आयात को और किसी संभरकों के बीच कायम वर्तमान संबंध और नीदरलैण्डस और/या विकासणील देशों में उपलब्ध और अधिकान गम्भीरों के अवसर के प्रकार में अर्णी समझता है कि आयात केवल नीदरलैण्डस से ही प्रभावी किए जाने चाहिए तो खरीदार, केवल नीदरलैण्डस के लिए तोली को सीमित रखने के लिए या नीदरलैण्डस और साथ ही साथ पात्र स्रोत देशों से बोलियों प्राप्त करने के लिए विकल्प रखेगा। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 31-33 के साथ मार्गदर्शन का अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 34-38 के साथ अनुच्छेद 30 लागू है।

7. ये मार्गदर्शन और साथ ही साथ उद्गम के नियम और पात्र स्रोत देशों की सूची नीदरलैण्डस की संशोधनाधीन है।

लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू.सी.ओ. वैक विलिंग, पालियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें। आयातक को यह भी सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि लदान वस्तवावेज का एक परकार्य सेट और वीजक की दो प्रतियों के साथ संभरक द्वारा भुगतान की पावती के सम्बन्ध में विधिवत् पृष्ठाकृत प्रमाणपत्र अतुर खण्ड 5(13) और 5(14) में उल्लिखित उद्गम प्रमाणपत्र माल के लदान के 15 दिनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, महायाता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेज दिए जाते हैं।

5(16) आयातक द्वारा साइरन्स के मध्ये भुगतान आयात लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति के आधार पर किए जाएंगे।

5(17) सामान्यतः सभी लदान/संभरकों के लिए भुगतान उपर्युक्त उल्लिखित प्राधिकार पत्र के जारी होने से 20 मास की अवधि के भीतर पूर्ण कर दिए जाने चाहिए। ऐसे मामलों में जहाँ लदान/संभरकों के लिए भुगतानों को 20 मास की अवधि के भीतर पूर्ण करने की संभवता न हो तो आयातक को चाहिए कि यह निरापद्धति लूप से लदान/संभरकों के लिए भुगतान को पूरा करने के लिए उपर्युक्त अवधि सीमा की समाप्ति कम से कम एक मास पूर्व ही वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (डब्ल्यू.ई-3 अनुभाग) से मम्पर्क स्थापित करें। इस प्रकार के आवेदन के साथ यु: वैध आयात लाइसेंस की एक कोटी प्रति भी भेजी जानी चाहिए जिसमें मांगी गई अवधि खुदी भी शामिल हो। यदि इस प्रकार का आवेदन निष्पारित प्रबंधि से पूर्व ही प्राप्त नहीं होता है तो संविधा के अप्रयुक्त देश को प्रम्परित किया गया समझा जाएगा।

5(18) आयातक की ओर से आर्थिक कार्य विभाग को शीघ्र ही प्रतिपूर्ति वस्तवावेज भेजने में किसी भी क्षुटी पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और मुख्य नियंत्रक, आयात-नियाति की आयातक के नाम में जारी किए गए सभी लाइसेंस को स्थगित करने के लिए कहा जा सकता है। यदि आयातक खुक करता रहे तो उसका मामला मुख्य नियंत्रक, आयात-नियाति की कार्यी सूची में लियने के लिए भेजा जा सकता है।

5(19) प्रतिपूर्ति वस्तवावेज की पावती के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, नीदरलैण्ड पूर्जीगत वैक पात्र स्रोत देशों से संभरकों की भुगतान की नई धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करेगा। नीदरलैण्डस पूर्जीगत वैक प्रतिपूर्ति की तारीख को नीदरलैण्ड में प्रकलित मुद्रा वर पर नीदरलैण्ड ग्रिनडर में समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

प्रण 6—विविध

6(1) आयातक को चाहिए कि यह लाइसेंस के उपयोग की दशति हुए अनुबन्ध-9 के रूप में वैमासिक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू.ई-3 अनुभाग) को भेजें।

6(2) ऐसे जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरक के बीच यदि कोई क्षगड़ा उठता है तो भारत सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं होती। संभरक को भुगतान प्रभावी किए जाने से पूर्व ही उसके द्वारा पूर्ण की जाने वाली शर्तें आयातक द्वारा साफ रूप से अनुबन्ध-II में बता दी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो क्षगड़े के विपालन से सम्बन्धित एक व्यवस्था भी संविधा में शामिल की जाए।

6(3) लाइसेंसधारी आयात लाइसेंस या इसमें गम्भीर अप्राप्ति की एक या सर्वी मामलों पर तथा उच्च मामान्य प्रयोजन केंटिंग के अन्तर्गत सभी प्रकार के आयातों को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियोजनों, अनुच्छेदों और आवेदनों का सुरक्षा गानक करेगा।

6(4) उपर्युक्त केंटिंग में दी गई खतों का उल्लंघन पर अतिक्रमण करने पर आयात तथा नियाति (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कर्तव्यार्थ की जाएगी।

(क) ग्रौपचारिक बोली अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए क्रिया-विधि

8. योगी के लिए आमंत्रण जारी करने समय अद्यी (या अद्यी की ओर से खरीददार) निम्नलिखित दो प्रकाशनों में से कम से कम एक में बोली का विज्ञापन देना:-

भारतीय व्यापार पत्रिका

भारतीय नियन्त्रित सेवा बुलेटिन

आयातक भारतीय व्यापार पत्रिका या भारतीय सेवा बुलेटिन में यथा नियन्त्रित नोटिस की तीन प्रतियाँ भारत स्थित नीदरलैण्डम के राजवृत्तावाम को भेजेगा।

9. प्रतियोगिता को व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय मंचिवाएं जिनके लिए जब कभी संभव हो बोलियां आमंत्रित की जाती हैं वह इन्हीं बड़ी होनी चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर बोलियों को प्राप्तिष्ठित कर सके। दूसरी तरफ यह कि यदि तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से एक परियोजना को विशेष प्रकार की संविदाओं में विभाजित करना संभव हो और इस प्रकार के विभाजन से अद्यी को लाभ ही और या इससे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बीमी और भी विशाल बन जाए तो परियोजना विभाजित का जानी चाहिए। अधियांत्रिक, उपकरण और निर्माण कार्य (गामान्यतः “टर्न की कार्डेस्ट” के रूप में जाने जाते हैं) के लिए एकल मंचिवाओं की ओर जो जा सकती है यदि वे उपलब्ध तकनीकी एवं आर्थिक मूल्यवादों के भीतर अद्यी देश के लिए सम्पूर्ण लाभ अपेक्षण करती है।

10. विशेष रूप से सिविल कार्यों की संविदाओं के लिए ग्रौपचारिक पूर्व योग्यता की बोला की जा सकती है। यदि पूर्व योग्यता की बोला की जाती है तो यह इन बातों को ध्यान में रखने हुए पूर्णतः सन्तोषजनक निपादन की धरता पर आधारित होनी चाहिए (1) इसी प्रकार के कार्य में कार्म का पूर्व अनुभव (2) कार्यालय, उपकरण एवं संयंत्र के संबंध में इसकी अमता और (3) इसकी आर्थिक स्थिति और सबलता।

पूर्व योग्यता क्रियाविधि का विज्ञापन कांडिका 8 में उल्लिखित क्रियाविधि के अनुसार किया जाएगा। पूर्वयोग्यता के लिए विचार किए जाने वाले इनकूल टेकेडारों के लिए संक्षिप्त विशिष्टिकरण उपलब्ध कराएं जाएं। जब पूर्वयोग्यता दाख हो जाती है तो वे सभी कर्म जो पूर्वयोग्यता की शर्तों को पूरा करती हैं बोली के लिए अनुमत दें।

11. योगी के दस्तावेज उन भाषाओं में से किसी एक भाषा में हैंवार कर जाएंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय पत्र व्यवहार में मान्यताप्राप्त की जाती है और जब तक कानूनी तौर पर रोक नहीं लगा दिया जाता इस बात का उल्लेख करेंगी उन भाषा दस्तावेज के मूल पाठ में शाख रहेगी।

12. विशिष्टिकरण में किए जाने वाले कार्य संभरण किए जाने वाले माल और सेवाओं तथा सुपुर्वी या मंस्यापन की जगह के लिए जहां तक संभव हो नाक और सुलाल स्पष्ट में बताया जाएगा। ड्राइंग विशिष्टिकरण के विषय के अनुकूल होगी, जहां वे अनुकूल नहीं होगी तो उसका मूल पाठ लाख होगा। विशिष्टिकरण में मूल्यांकन के मिडाल और बोलियों की तुलना का उल्लेख करेंगे जो नव लेख में लिए जाएंगे जब मूल्यांकन किए जाते हैं और बोलियों की तुलना की जाती है। विशिष्टिकरण में इस प्रकार से क्रिया जाना चाहिए जिससे कि स्वतंत्र और सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की स्वीकृति एवं प्रोत्साहन मिल सके।

किसी प्रकार की अनियन्त्रित जानकारी स्पष्टिकरण या गलतियों में सुधार और विशिष्टिकरणों में परिवर्तन तथा बोली के लिए आमंत्रण में उनको शीघ्र शीघ्र प्रवर्गन करा दिया जाएगा जिन्होंने मूल बोली दस्तावेजों के लिए अनुरोध किया था।

13. यदि इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल होने प्राप्तिष्ठित हो, तो विशिष्टिकरण में यह बताया जाएगा कि वे माल जो अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृतमानकों

को पूरा करते हैं जिनमें उल्लिखित मानकों के अन्तराष्ट्रीय मानकों की मात्रा की गई हो तो वे भी स्वीकृत किए जाएंगे।

14. यदि विशेष कालदृष्टि पुर्जों की अपेक्षा की जाती है या यह निष्पत्ति किया जाता है कि कुछ अनियार्थी गुणकर्ता वो बनाए रखने के लिए एक विशेष मात्रा के मानकीकरण की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निपादन और धरता पर आधारित होंगे और उनमें केवल तभी पंजीकृत मार्क, नाम, सूची, संघर्ष या विशेष विनियमित के उत्पादन निर्धारित होने चाहिए। अप्रिम मामले में विशिष्टिकरण में विकल्प की उन सामान के प्रस्तावों के लिए स्वीकृति दी जाएगी जिसमें मिलती जुलती विशिष्टताएं हैं और जिनका विभाजन और क्रान्तियों कम से कम उन विशिष्टिकरण स्तर के बराबर है।

15. बोली के लिए आमंत्रण में पात्र स्रोत देशों का उल्लेख किया जाएगा और उनमें उद्यगम के लागू नियमों को बनाया जाएगा।

16. कोटेशन की जांच मात्र स्रोत देशों के संभरकों के बीच पूर्णतः वराबरी की शर्तों के आधार पर की जाएगी इनमें माल और उपकरण के लिए सीमा शुल्क ईरिफ और अन्य करों और इसी प्रकार के प्रभावी करों की नियन्त्रक कीमतों पर कोटेशन के मूल्यांकन भी शामिल हैं जैकिन, अद्यी वेश, माल और सेवाओं के संभरण के लिए बोली के मूल्यांकन और भी मिलान करने के लिए जिसमें परिवहन कीमतें शामिल नहीं हैं, स्थानीय माल और सेवाओं के लिए और उन अन्य पात्र स्रोत देशों के उत्पादों के लिए वरीयता की गुजाइश देने के लिए जो स्रोत में ही या जो इस प्रकार के वर्ग स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए, अन्य पात्र स्रोत देशों में उत्पाद होने वाले माल और सेवाओं के लिए प्राधिकृत हैं। वरीयता की यह गुजाइश/न्यूलाम मूल्यांकित विदेशी बोली के लागत सीमा भाषा पर 15% या बोलीकर के देश में सीमा शुल्क करों के वर्तमान स्तर, इनमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

17. विशेष मामलों में अद्यी नीदरलैण्ड सरकार और अद्यी देश के बीच आपसी परामर्श करके, कठिका 16 में उल्लिखित वरीयता की गुजाइश के अतिरिक्त नीट के अनुकूल स्थानीय और वेत्तीय विनियमित करायों के लिए वरीयता की सीमित गुजाइश को प्रदान कर सकता है। वरीयता के स्तर का निर्धारण करने समय राष्ट्रीय दर्जा या क्षेत्रीय स्वाम्य और प्रबन्ध तथा अद्यी देश के वर्तमान स्तर के वर्तमान स्तर, इनमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

18. बोली दस्तावेज में कोई भी गहरान वरीयताएं प्रदर्शित की जाएंगी और बोली के मूल्यांकन और तुलना में जिस तरीके से उह लागू किया जाएगा उसे भी बनाया जाएगा।

19. बोलीकारों को पर्याप्त समय दिया जाएगा जिसमें वे अपनी बोलियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

20. बोलियों को प्राप्त करने और बोली को बोलने के लिए अंतिम नारीख, समय और स्थान बोली के लिए नियंत्रणों में घोषित किया जाएगा और सभी बोलियां नियंत्रित समय पर जनता के भास्तव बोली जाएंगी। नियंत्रित समय के बावजूद बोलने वाली बोलियों को बिना बोले ही लौटा दिया जाएगा। बोलीकार का नाम, प्रत्येक बोली या आवेदित या स्वीकृति वाली कोई विकल्प बोली हो तो उसका मूल्य उंची आवाज में पढ़ा जाएगा और उनका रिकार्ड रख दिया जाएगा।

21. किसी बोलीकार को बोलियों लूलने के बाद अपनी बोली में परिवर्तन करने के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी। केवल योगी के सूल में परिवर्तन से मिल स्पष्टिकरण बोलीकार किए जा सकते हैं। जल्दी किसी भी बोलीकार को अपनी बोली में स्पष्टिकरण के लिए कहा जाएगा तभी वह सकता है किन्तु किसी भी बोलीकार को बोली के मूल में या अपनी बोली के मूल्य में परिवर्तन के लिए नहीं कहेगा।

22. कानून द्वारा यदा अपेक्षित को छोड़कर जांच से सम्बद्ध कोई भी सूचना, स्पष्टिकरण और बोली के मूल्यांकन तथा परिनिर्णय गे सम्बद्ध

सिफारैण, बोलियों के मार्जनिक रूप से खुलने के बाद सफल बोलीकार के लिए संविदा के परिनिर्णय को शोषित करने से पूर्व किसी भी उम्मीद अधिकता को नहीं भेजी जाएगी जो और से या नीदर सैण्ड्स की सरकार की ओर से इन क्रियाविधियों के घोषकारिक रूप से सम्बन्ध नहीं है।

23. बोलियों के खुलने के बाद खरीददार इस बात का सुनिश्चय करने के लिए इन बोलियों की जांच करेगा कि क्या बोलियों के परिकल्पन में महत्वपूर्ण गलनियों की गई हैं, क्या बोलियों बोली दस्तावेज़ की आवश्यकताओं के पूर्णता घनकृत तो हैं, क्या अपेक्षित गारंटीयों और जमानतों की अवधियां की गई हैं, क्या दस्तावेज़ सही रूप से हस्ताक्षरित कर दिए गए हैं और क्या दस्तावेज़ प्रत्यक्ष रूप से सही हैं। यदि कोई बोली बास्तविक रूप में विशिष्टकरण के अनुकूल नहीं होती है या उसमें अस्वीकृत शर्तें हैं या अन्यथा इन में बोली दस्तावेज़ के अनुकूल नहीं हो तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तब आर्थिक दृष्टि से विस्तृत निर्धारण के साथ तकनीकी विशेषण किया जाएगा जिससे प्रत्येक अनुकूल बोली का मूल्यांकन किया जा सके और बोलियों को मिलाने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

24. बोली के लिए निन्द्रण में बताया जाए कि खरीददार को ऐसी सभी बोलियों को गढ़ करने का अधिकार है जब कोई बोली विशिष्टकरण के प्रयोजन के अनुकूल नहीं है और जब प्रतियोगियों के अभाव का प्रमाण मिलता है या निन्द बोलियों उन पूर्ण अनुमानित अनराशि की कीमत से अधिक होती हैं जो इस तरह की कार्रवाई को उचित बताने के लिए प्रयत्नित है। यदि भी बोलियों गढ़ कर दी जाती हैं तो जूरी नीदरलैण्ड्स सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ऐसी स्थितियों के कारणों को और निम्न बोली और अनुमानित कीमत के अन्तर के कारणों को जानने के लिए एक या एक से अधिक घूनतम बोलीकारों के साथ सोदा कर सकता है विशिष्टकरण में परिवर्तन को परावर्तित करने वाली तय की गई बोलीदारों जिनसे परियोजना की अनुभावित कीमत में कमी हो सकती है उन्हें स्वीकार किया जा सकता है वर्षाते कि परिवर्तन परियोजना के स्वरूप को बास्तविक रूप में नहीं बदलते। जहां परिवर्तन बास्तविक है वहा पुनः बोली उचित हो सकती है। इसे हर बार नीदरलैण्ड्स की सरकार द्वारा अनुमोदित करना होगा।

25. बोलियों के मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में बताए गए नियम और उसों के अनुसार और बोलियों की प्रस्तुत करने की प्रतिम तारीख से पूर्व इससे सम्बद्ध किसी भी आशोधन के अनुसार होने चाहिए। घूमतम भूल्यांकित बोली की स्पष्टि करने के प्रयोजनार्थ कीमत से विषय तथ्यों जैसे निर्माण कार्य या भ्रम्य कार्य को पूरा करने के लिए समय उपकरण की कार्य असता और विश्वसनीयता, इसकी सुरुदंगी को समय और सेवा और फालतू पुर्जी की उपलब्धता को भी ध्यान में लिया जाएगा और जहां तक सम्भव हो सकेगा मुद्रा में व्यक्त किया जाएगा वे मुद्रा जिन में बोली कीमत का भगान किया जाएगा उनका भूल्यांकन केवल बोली के मिलान के प्रयोजनार्थ सरकारी भाषण द्वारा प्रकाशित मुद्रा की दरों के आधार पर और बोली की अंतिम तारीख को इस प्रकार के सौदों के लिए लागू दरों के आधार पर किया जाएगा।

26. संविदा का परिनिर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाएगा जिसकी बोली पूर्व की कंडिकाओं में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए घूमतम भूल्यांकित बोली निरिक्षण की गई हो।

27. अनुमोद करने पर नीदरलैण्ड्स की सरकार की अधिप्राप्ति के सभी पहलुओं पर अपनी टिप्पणी और सिफारिश प्रदान करने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा। संविदा का परिनिर्णय होने के बाद सीरटलैण्ड्स की

(ग) श्रीपञ्चारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय बोलों से मिश्र अधिप्राप्ति की क्रियाविधि 28. कंडिका 29 और 30 में उल्लिखित मामलों में कंडिका 31—39 में उल्लिखित अधिप्राप्ति के नियम कंडिका 6 के अनुसार लागू हो सकते हैं। मामलोंका उचित

29. जहां खरीददार के पास अपने उपकरण के उचित मानकीकरण को बनाए रखने के लिए विश्वसनीय कारण है।

योग्य संभरकों की सीमित संख्या

30. उन मामलों में जहां विषयाधीन अधिप्राप्ति की प्रहृति के कारण योग्य संभरकों की संख्या सीमित है और खरीददार की माकिट जानकारी ऐसी है कि उससे आशा की जा सकती है कि योग्य संभरकों के बारे में जाने।

31. श्रीपञ्चारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय बोली

सामान्य खुली अन्तर्राष्ट्रीय बोली के अन्तर्गत खरीददार उन सीमित संख्या के (पूर्व) योग्य संभरकों से बोलियों आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत है जो विषयाधीन अधिप्राप्ति की विशेष प्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य समझे जाते हैं।

ऐसे मामलों में अग्री को यह सुनिश्चय कर देना चाहिए कि किसी भी संभावित योग्य संभरक को छोड़ नहीं दिया गया है। जब श्री और ऐसे वे वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) भारत सरकार से पात्र स्रोत देशों के सम्भावित संभरकों के बारे में जानकारी मांगी जाएगी, तभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी जिससे कि वे उचित आधार पर भाग लेने में समर्थ हो सकें।

32. संभरकों का चुनाव केवल उनकी योग्यताओं के आधार पर किया जाना है और जहां तक सम्भव हो वे नीदरलैण्ड्स सहित अनेक पात्र स्रोत देशों से चुने जाने हैं।

33. कंडिका 8 में उल्लिखित से मिश्र श्रीपञ्चारिक अन्तर्राष्ट्रीय बोली की सभी अवधिस्थार पूर्ण रूप से लागू की जानी हैं।

34. श्रीपञ्चारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति

यदि श्रीपञ्चारिक प्रतियोगिता बोली की क्रियाविधियों के माध्यम से अधिप्राप्ति नहीं होती है तो यह सम्प्रोग्यजनक वाणिज्यिक नीति के अनुसार और पात्र लोग देशों के बीच बिना किसी भेद भाव के प्राप्त करनी चाहिए।

35. आयानक को अन्नीचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति के इच्छित उपयोग का विस्तृत और समयोनित प्रबार करना चाहिए। पात्र स्रोत देशों से संभरक जब भी ऐसी सूचना मांगें तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) भारत सरकार उन की व्यायोनित आधार पर भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए सभी आवश्यक सूचना देंगी।

36. वरों और प्रस्तावों को तैयारी के लिए अनुभित समय शामिल की गई संविदाओं के समरूप द्वारा नियन्त्रित किया जाएगा। साधन सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की अनुमति देने के लिए समय और वित्त दोनों की अनुसूचिया पर्याप्त नहीं होती।

37. कुछ विशेष मामलों में नीदरलैण्ड्स सरकार से मूल्यभाव और स्पष्टि किए गए थे इसके पूर्ण व्यौरे मिश्रित किए गए भाग, शामिल किए गए संभरकों और प्राप्त मूल्य दरों के सम्बन्ध में विशेषाओं से सूचना मांग सकती है।

38. श्रीपञ्चारिक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए पूर्ण सम्भव सीमा तक यथोनित मार्गदर्शन लागू होना चाहिए।

39. एक मात्र संभरक

निन्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में केवल किसी एकमात्र संभरक से सीधे ही क्य करने की अनुमति दी जाती है:—

- होती है जो आयातक द्वारा पुनः बिश्री के लिए हो, जिसके लिए आयातक संभरक का नियमित प्रधिकृत वितरक या व्यापारी हो और जिसके लिए संभरक एकमात्र वितरक या विनियोगी हो।
- (2) एक व्यापिक्यक आयातक द्वारा वह प्रधिप्राप्ति जिसमें वह पर्यवस्थु शामिल है जो विनियोग संसाधन या भूमिका और उप अन्तिम उत्पाद के पुनः बिक्री के लिए अधिप्राप्त की जाती है जिसके लिए आयातक संभरक का नियमित रूप से प्रधिकृत वितरक या व्यापारी हो और जिसके लिए संभरक विनियोगी हो।
- (3) पुर्जों की विनियोगीता का सुनिश्चय करने के लिए या विशेष विजाहन या तकनीकी आवश्यकताओं के कारण अधिप्राप्ति के बाल एक ही स्रोत से पूर्ण की जा सकती है।
- (4) क्रेता अहं विनियोगी हो जिसका साज-सामाज और कठ्ठी सामग्री का कार्मला कच्छों सामग्री की उप विशेष किसी के जिस भवित्वतम उपयोग के लिए बनाया गया हो जो केवल एक ही स्रोत से प्राप्त की जा सकती हो।
- (5) यदि संभरक औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय बोली के प्रधीन मूल रूप में प्राप्त की गई प्रधिप्राप्ति को बढ़ाना या दूहराना चाहता हो वर्षते कि संभरक प्रधिप्राप्ति मूल प्रधिप्राप्ति के मुकाबले में छोटी हो, केवल कुछ ही प्रबसरों पर पूर्ण की जाती हो और यदि यह मूल प्रधिप्राप्ति से संबंधित नियोग कार्य उस समय भी चल रहा हो या मूल प्रधिप्राप्ति पूर्ण करने के थोड़े ही समय बाक पूर्ण की जाती हो।
- (6) यदि सौदे का मूल्य बी० एक० एल० 1.25 मिलियन से कम हो।

(ब) परामर्शकों के उपयोग के लिए मार्गदर्शन

40. परामर्श देने वाली नियोजित संस्थाएँ इस उद्देश्य के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए कि उनका परामर्श दिजाइन, विशिष्टिकरण और उनके द्वारा तैयार किए गए बोली के दस्तावेज राष्ट्रीय, व्यापिक्यक या आंशिक पक्षपात से मुक्त हों और वे प्रतियोगिता के आधार पर अनुपालन वार सकती हों। स्थानीय परामर्शदाता संस्थाओं पर विचार करते ममत्र राष्ट्रीय स्वामित्व का स्तर प्रबन्ध और कार्मिक सत्य धैर्यकरण जैसी जातों पर उचित ध्यान देना चाहिए।

41. परामर्शदाता संस्थाओं के ज्यन के लिए औपचारिक प्रतियोगिता बोली की क्याविधि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, ज्यन की प्रक्रिया में ऋणी को उन प्रत्याशित संस्थाओं की वयोवृत्ति संलग्न पर विचार करना चाहिए जिनमें कई पाल स्रोत देनों से समर्थन और स्वतन्त्र सैवाएँ प्राप्त करने की आशा की जा सकती हो। यह सूची निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूपों पर आधारित होगी:-

- (1) कार्य की समान किसीमें संस्था का पहला मनुभव।
- (2) कर्मचारियों, साज-सामाज और संग्रह के सम्बन्ध में इस संस्था की क्षमता।
- (3) इसकी वित्तीय स्थिति और भवित्व।

यह बांधनीय है कि प्रस्तावों के लिए निम्नलिखित भेजने से पहले ऋणी प्रथांशित संस्थाओं की सूची नीदरलैण्डस सरकार को प्रस्तुत करें। नीदरलैण्डस सरकार की परामर्शी की अपन की भास्त्रीकार करने का प्रधिकार है, इसके अतिरिक्त वह नीदरलैण्डस में परामर्शदाता अंतर्वेदन में अपनी जानकारी के आधार पर यह भुक्तान दे सकती है कि इस सूची में वृद्धि की जाती है।

(क) तिकायते

42. खरीदवार बोली के सम्बन्ध में बोलियों को प्रस्तुत करने और संबिलाओं के प्रदान करने के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली विकायतों को सुनने और उनकी जांच करने की व्यवस्था करेगा।

43. औपचारिक बोली क्षियाविधि के अन्तर्गत की गई व्यरीद के मामले में बोली समाप्त होने की विधि से पूर्व किए गए प्रतिबन्ध पर्यवस्थु विशिष्टिकरण या आमंत्रण की प्रतिवर्ध अवधि के सम्बन्ध में विषयवस्थ की किसी भी विकायत का समाधान बोलियों के खुलने से पूर्व ही किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो नीदरलैण्डस सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ही उचित अवधि के लिए बोली के लिए अनिम विधि स्वीकृत की जाए।

44. जब विकायत सम्बद्ध संभरकों में से किसी एक के द्वारा की गई हो तो विकायत के विषय में सम्बन्धित और इस पर योगी गई कार्रवाई से सम्बन्धित दस्तावेज नीदरलैण्डस सरकार द्वारा और ऋणी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध होंगे।

परिशिष्ट—क

विकायत सम्बद्ध संभरकों देने को संयुक्त वित्तीय व्यवस्था के लिए पाल स्रोत देनों की सूची

क. नीदरलैण्ड	गिरीषिया
ख. अफ्रीका	आइजोरी कास्ट
उत्तरी साहारा	कीनिया
अस्त्रीरिया	लिशोवी
लीबिया अरब गणराज्य	लाइंगीरिया
मोरक्को	मालागसी गणराज्य
तूनीसिया	मलावी
मिश्र	माली
बजियो साहारा	मारितेमिया
बोट्सवाना	मारिसस
बुर्झिं	नाइजीर
कैमोरून	नाइजीरिया
केप वर्दी द्वीप समूह	रियूनियन
मध्य अफ्रीका गणराज्य	ल्यान्डा
चाद	सेनेगाल
कोमोरो द्वीप समूह	सेनेगेज
कांगो (जम्बार्बा गणराज्य)	मिश्रा लेओन
जरी गणराज्य	मोमालिया
दहोमी	टर, फार और इमास
इयोपिया	सैट हैलेन और ईवेन्डेमिज
गेडोन	सूडान
गिम्बाया	स्वाजीलैण्ड
घाना	बन्जारिया
गिरी	टोगो
ग्रपर बोल्टा	उगाण्डा
जामिया	बलिया
जमेरिका	ग्रेंडीना
उत्तरी एश भूमि	मोमीविया
बहुमान	ग्रांडील
वारवेडों	चिनी
वरमुदा	कोलम्पिया
कोस्टा रिका	इवान्डोर
ब्यूटा	काकलैण्ड द्वीप समूह
	गुयाना
	गिरी (एक० घार०)

१ डौर्मिनेशन (गणराज्य)	पागगूडे
ई-१ मैलबोड़ेर	फीरू
गुड्डीपैप	मूरीनाम
गुश्चाटेमाला	युरूबै
हैटी	वीनेज़युला
होन्दुरागज (ब्र.)	एशिया
होन्डराम (बी०आर.)	मध्य-पूर्वी
जमैका	बेहरीन
माटिकि	ईरान
मैस्किको	ईराक
नीदरलैण्डस अन्टर्नीज़	इजराइल
निकारागुआ	जोहॉन
पनामा	कुवृत
मैट पैरी एट मिक्युलोन	लेबनान
ट्रिनिडाद एट टोबोगों	ओमन
बैस्ट इण्डिया (बी०आर.)	कत्तार
सऊदी अरब	तिमोर
यमन (जनवादी प्रजातंत्र गणराज्य)	वियतनाम (गणराज्य)
संयुक्त प्रवं गणराज्य	वियतनाम (प्रजातंत्र गणराज्य)
भारिया (अरब गणराज्य)	सामुद्रिक
यमन (अरब गणराज्य)	फिझी
बैकिणी	गिलबस्टैं पर्व एलिस द्वीप समूह
अफगानिस्तान	फैंट पोलिनेशिया
बंगला देश	न्यू कॉलोनिया
भूटान	न्यू हिन्दराइडज (बीआर एज एफ आर)
बर्मा	पेसेफिक द्वीप समूह (यूएस)
भारत	पैरी न्यू गिनी
मालदीव	सोलोमन द्वीप समूह
नेपाल	टोगा
पाविम्बान	वासिंज और फुगुना
श्री लंका	परिचमी सामोआ
सुदूर पूर्व	यूरोप
ब्रनी	टर्की
खीर गणराज्य	पुर्तगाल
हूग-कांग	
इण्डोनेशिया	
कोरिया (गणराज्य)	
कोरिया (जनवादी प्रजातंत्र गणराज्य)	
माओम	
मको	
मलेशिया	
फिलीपिन्स	
सिंगापुर	
थाइलैण्ड	

उद्गम के नियम**परिशिष्ट "क"**

- उद्गम के इन नियमों की वियाधीन मर्द स्रोत देशों में उत्पादित माल और सेवाएं होंगी।
- माल के मामले में नीदरलैण्डस के उद्गम का निर्धारण इस क्षेत्र में उस विद्यान के अधीन होगा जोकि यूरोपीय समुदाय में लागू है।
- पैरा-2 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण नीदरलैण्ड के वाणिज्य मंडल द्वारा जारी किए गए उद्गम के प्रमाणपत्र के साथ भेजा जाएगा।
- माल के मामले में, विकासशील देशों के उद्गम का निर्धारण उस उद्गम नियम के अधीन होगा जो अधिमान्यता सामान्य प्रणाली की रूपरेखा में यूरोपीय नमुदाय द्वारा स्थापित की गई हो।

- पैरा 4 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण विकासशील देशों के प्रणालीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रपत्र "ए" (जो अधिमान्यता की सामान्य प्रणाली के उपयोग में साया जाता है) उद्गम के प्रमाणपत्र द्वारा भेजेगा।
- सेवाओं के मामले में (प्रथम् भाग-दर्शन का पैरा I) उद्गम का निर्धारण नीदरलैण्डस सरकार और अर्थ लेने वाले देशों के बीच आपसी परामर्श के तदर्थ आधार पर किया जाएगा।
- ऐसे मामलों में जहाँ उद्गम के नियमों में वास्तव में कोई समस्या नैदा हो जाती है या अर्थ लेने वाले देश को गम्भीर अर्थिक घटा हो जाता है (उदाहरणार्थ बहुत से सम्भावी संभरणों पर जबरदस्त प्रतिबन्ध) तो नियमों से छुटकारा पाने की स्वीकृति दी जा सकती है किन्तु वह केवल नीदरलैण्डस सरकार एवं अर्थ लेने वाले देश के बीच आपसी परामर्श के बाद दी जा सकती है।

ग्रन्थांश-II

- (ए) भारतीय आयातक का नाम और पता और/या जहाँ आवश्यक हो परियोजना अधिकारी का नाम और पता।
- (बी) संभरक का नाम और पता। यदि संभरक पात्र स्रोत देश के हैं तो उस मामले में निम्नलिखित सूचनाएं भी भेजी जानी चाहिए:—
- (1) राष्ट्रिकता
 - (2) पात्र स्रोत देशों के द्वारा रखे गए प्रयोरों का प्रतिशत।
 - (सी) (1) आयात साइरेस की संख्या और दिनांक
 - (2) भूस्थ
 - (डी) (1) नीदरलैण्डस/पात्र स्रोत देश में संभरक के बैंक का नाम और पता।
- * (2) भारत में आयातक का बैंक (यह वह बैंक होगा जिसने बैंक गारंटी दी है)।
- ** (3) भारत में आयातक का बैंक जो कि आयातक के लिए पोतलदान वस्तावेज रिहा करने से पहले भारत के सेवकों में रूपए जमा कराने के लिए उत्तरदायी होता।
- (ई) इच गिल्डरस में या पात्र स्रोत देश के मुद्रा में संविदा भावेश का भूल्य।
- (एफ) अधिप्राप्ति की विधि, क्या यह सीधे खरीद पर आधारित है या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय बोली पर या चयन कार्मूला अन्तर्राष्ट्रीय बोली के आधार पर जिस भाषाले में यह संकेत किया जाना चाहिए कि क्या संविदा यदि कोई हो तो उन कारणों के साथ न्यूनतम तकनीकी उपयुक्त प्रस्ताव के आधार पर की गई है।
- (जी) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण
- (एच) माल का उद्गम यदि कोई हो तो गैर पात्र स्रोत देशों से आयातित नंबरटकों का प्रतिशत।
- (आई) सुपुर्दगी को पूरा करने की संभावित तिथि
- (जै) भुगतान की शर्त और संभावित वह तिथि जिस विन इस संविदा के अन्तर्गत भुगतान के लिए पड़ेगी।
- (के) पोतलदान वस्तावेजों की विस्तृत सूची जैसे अवतरण विल, बीजक, उद्गम प्रमाणपत्र आदि (जैसे विकासशील देशों के लिए नीदरलैण्ड पूंजी निवेश बैंक या पात्र स्रोत देश में संभरकों के बैंक को जाहिए कि संभरकों का भुगतान करने से पहले अपेक्षित प्रत्येक वस्तावेज की प्रतियों के साथ मांग करें।

*निजी बोल के लिए

**सार्वजनिक बोल के लिए

- (एन) यदि संविदा में शामिल हैं तो भारतीय एजेंट का वह कमीशन (ठीक-ठीक धनराजी गंगेश्वर की जानी है) जिसे प्राथिकार पद जारी करने मध्य संविदा के मूल्य में से बटाना पड़ेगा। इस प्रकार का कमीशन का भुगतान भारतीय एजेंटों की रुपए में आयातकों द्वारा सीधे ही किया जाएगा।

(एम) वह मूल्य जिसके लिए प्राथिकार पद अपेक्षित है।

(एन) यैक गारटी की संभाया, दिनांक और मूल्य इसमें उस प्रथाधि का भी संकेत हो जिस तक यह यैध है।

(ओ) यदि कोई हो, तो विशेष अनुबोध।

अनुबन्ध III

३८ क्रेडिट

संविदा प्रमाण-पत्र

मंथिदा के ब्यौरे

भारतीय आयात साइंसेस की संख्या

1. संविदा की संख्या एवं दिनांक
2. खरीदवार की संख्या एवं दिनांक की संमर्शन किए जाने वाली माल एवं सेवाओं के ब्यौरे (यदि बहुत सी मर्दों का संभरण किया जाना है तो प्रमाणात्मक में विस्तृत सूची लगाई जानी चाहिए)।
3. खरीदवार को चक्रार्थ जाने योग्य कुल संविदा कीमत (लागत वीमा भाड़ा लागत एवं भाड़ा या जहाज पर निःशुल्क का भक्त वीजिए) डी.एफ.आई. यदि माल का संभरण किया जाना है तो निम्नलिखित खण्डों की पूर्ति प्रवर्शय भी जानी चाहिए।
4. नीदरलैंड्स में उत्पत्ति नहीं किए गए माल का जहाज पर निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत किन्तु वह उप माल की खरीद संभरण द्वारा मीधे ही विवेषों से की गई है अर्थात् विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित कञ्जे माल या संधरकों का प्रतिशत,

 - (क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य
 - (ख) मर्दों का विवरण एवं संक्षिप्त विशिष्टिकरण

5. यदि सेवाओं का संभरण किया जाना है तो निम्नलिखित खण्ड के भी पूर्ति की जानी चाहिए।
6. किए जाने वाले किसी काम का प्रनुमानित मूल्य या

 - (क) आपकी फर्में (साईट इंजीनियर प्रभारत आदि)
 - (ख) स्थानीय संभरक द्वारा खरीदार के देश में निष्पादित की गई सेवा का उल्लेख कीजिए।

7. उपर्युक्त कंडिका 4 और 5 के सम्बन्ध में यथा आवश्यक प्रहृत टिप्पणियां
8. मैं घोषणा करता हूँ कि संभरक द्वारा या मीधे उल्लिखित द्वारा नीदरलैंड में नियुक्त किया गया हूँ और इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे अधिकार है। एस.द्वारा बचत वेता हूँ कि उपर्युक्त कंडिका 4 और 5 में उल्लिखित माल एवं सेवाओं से जिन श्री किसी भी ऐसे माल या सेवा का इस मविदा के निष्पादन में संभरण द्वारा संभरण नहीं किया जाएगा जो नीदरलैंड में मूल के नहीं हैं।

हस्ताक्षरित
आद्या
संधरक का नाम और पता

दिनांक
नीवरडैण्डस वाणिज्यिक मण्डल

अनुवान-IV

मंगल-एफ (14) छठ्यू-ई- 3 / 77

भारत सरकार

यित्त मंत्रालय

आधिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

यिकासशीक देशों के लिए दि नीदरलैण्ड इन्वेस्टमेंट बैंक
दि हैग,
नीदरलैण्डस ।

लाला नीवरलैण्डम गिलडर्स के ख़रें के लिए समझौता

प्रिय महोदय गण,

प्राधिकार पक्ष संघर्षा भारत को आपके बैंक द्वारा विए गए ऋण में से भारत के सर्वश्री और हालैण्ड के सर्वश्री के बीच वित्त युद्ध किए जाने वाले सौदे के मम्बन्स में अपने प्राज के आवेदनपत्र के प्रसंग में हम एतद्वद्वारा निवेदन करते हैं और उपर्युक्त संविदा की शर्तों के अनुमान, एन. एफ. एल. (—डब्ल्यूडब्ल्यूर) मालां की धनराणि हालैण्ड में संभरक को चुकाने के लिए आपको बिना गर्न और बिना परिवर्तन के प्राधिकृत करने हैं। यह निवेदन किया जाता है कि डब्ल्यूसंभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक, पोनसदान और अन् वस्तविज (आधातक के बैंक) को सीधे दिए जाएं।

संभरकों की विकाससील देशों के लिए नीदरलैण्ड्स पूजी निवेश बैंक को उस जिले के जिसमें नियातिक स्थित है, नीदरलैण्ड्स व्यापार मण्डल द्वारा जारी किए गए प्रमाणित किए गए प्रमाणपत्र की इस सम्बन्ध में वो प्रतियोगी प्रस्तुत करना आवश्यक है कि प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत आने वाले माल नीदरलैण्ड्स मूल के हैं।

कृपया नामे डालने की सूचना भारत सरकार, विल मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (आर्थिक सहायता बोर्ड शास्त्रा) जीवन द्वाप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली को अग्रसारित करें। यह प्राधिकार पत्र
..... तक बैठ रहेगा।

कुमे भारत का राष्ट्रपति
()

प्रतिष्ठिति (भायाक्षक के रैंक को)

उन्हें केवल यह सुनिश्चित करने के पश्चात् ही आयातक को दस्तावेजों का अप्रकाश्य सेट रिहा करता चाहिए कि आयातक ने निम्नलिखित धनराशि जमा कर दी है :—

(1) मुख्य नियंत्रक, आयात-नियाति की सार्वजनिक सूचना संस्था-8 प्राई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 17-1-1976 में यथा निर्धारित और सरकार द्वारा भगवा-ममत्य पर मुख्य नियंत्रक, आयात-नियाति की सार्वजनिक सूचना संस्था-8 को माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के भूद्वा नियंत्रण परिषद्वारा के माध्यम से श्रधिसूचित तरीके में गणना की जाने वाली विनिमय की चाल मिश्रित दर पर उच्च गिरदूर में सम्भवरक को समतुल्य रूपए का भगतान,

(2) उपर्युक्त में (1) द्वारा प्रदाकी जाने वाली अपेक्षित धनराशि पर सार्वजनिक सूचना भंडार-46 आर्ह टी मी(पी एन)/76 विनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9% की दर पर और 30 दिनों से अधिक होने पर 15% की दर पर गणना किया है आगे जिसकी गणना विकासांगत देशों के लिए नीदरलैण्ड इन्वेस्टमेंट बैंक, एन० बी० वि० हैंग, द्वारा सम्प्रेरक को वास्तविक भगतान की तिथि से भारतीय स्टेट बैंक सीएस हासारी दिल्ली या भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में आयातक द्वारा सम्प्रेरक दफ्तर के वास्तविक भगतान की तिथि तक की जाएगी।

ग्रन्तवचन्द्र—5

संबोध-एफ-4()उच्च-ई-3/

भारत भरकार

वाणिज्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली

विषय :— नामान्य प्रयोजन इच्छिट के अन्तर्गत की गई संविदा-प्रतिपूर्ति प्रिय महांदेव,

सर्वं विद्युति
 (भारतीय आयातक ने
 (समाप्ति
) के सूच्य के लिए के मामान्य प्रयोजन उच्च इच्छिट के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंस संलग्न
 दिनांक के मध्ये लागत बीमा भाष्य/सामग्री एवं भावे की
 () धनराशि के लिए
 के सम्बरण के लिए सर्वथी
 (विदेशी मंत्रक)

के गाथ संविदा की है। गंविदा का
 एक प्रति मंत्रगत है।

2. ऊपर के रुपए की धनराशि में से भारतीय एजेंट के कमीशन के रूप में धनराशि भारतीय मुद्रा में प्रदान की जाती है। विदेशी मुद्रा में सम्बरण की प्रदान की जाने वाली धनराशि प्रथमतः मुक्त विदेशी मुद्रा स्नातों में से प्रथमतः की जाएगी जिसका बाद में धनराशि तक उच्च सामान्य प्रयोजन क्रेडिट में से प्रति पूर्ण की जानी है।

3. आपको उत के बैंकरों प्रवर्त्ति सर्वथी के माध्यम से सर्वथी के नाम में इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर और बैंक विदेशी लाइसेंस के मध्ये सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रण, यू० सी० ओ० बैंक विलिंग, मंत्रद मार्ग, नई दिल्ली को भेजें।

4. मुद्रा-विनियम नियंत्रण मैत्रील के खण्ड-7 पैरा 10 के अनुसार आपको यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि साथपत्र की समाप्ति तिथि सम्बन्धित आयत लाइसेंस में यथा उल्लिखित पोललदान के लिए अन्तिम तिथि के पेतालिस (45) दिनों से ज्यादा नहीं है।

5. साथपत्र में यह भी प्रावधान होगा कि सर्वेशी

(विदेशी मंत्रक)

अपरकाल्य पोलनदान द्वारा जारी की एक सेट और बीजक की हो प्रतियाँ जो इच्छिट संबरण द्वारा इस प्रमाण-पत्र द्वारा पृष्ठाकित हो कि भुगतान उनके द्वारा प्राप्त हो गया है, सीधे ही महायना लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यूरोपीय बैंक विलिंग, मंत्रद मार्ग, नई दिल्ली को भेजें।

जिम जिले में नियन्त्रित है उम जिले के नीदरलैंड व्यापार मण्डस के माथ पत्र के अन्तर्गत आने वाले माल के नीदरलैंडस मूल के होने के सम्बन्ध में जारी किए गए प्रमाणित किए गए इस साथपत्र के अन्तर्गत आने वाले माल उद्गम के सम्बन्ध में उचित समर्थ प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र की दो प्रतियाँ भी वे प्राप्त करेंगे और नियंत्रक, सहायता लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करेंगे।

6. आप को, यदि कोई हो तो बैंक खचों को छोड़कर बीजक/माल के पांत लदाने के मध्ये यात्रा के द्वारा सर्वथी को किए गए प्रेषण का एवं प्रमाणपत्र भी सहायता लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक विलिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली का भेजता होगा।

7. कृपया इस पत्र की पात्रता भेजें।

मतदीय,

*जो नाम नहीं हो उसे बाट दें।

संविदा की प्रति के साथ प्रति इनको प्रेषित :—

भारतीय रिजर्व बैंक, भुगतान विभाग, बम्बई-1

2 प्रति निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित :—

(1) (भारतीय आयातक)

यह सुनिश्चय कर लिया जाए कि सर्वेशी

(विदेशी बैंकर)

ने नियंत्रक, भुगतान लेखा एवं लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक विलिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली को भुगतान बीजक सहित पोललदान और अन्य दस्तावेजों (अपरकाल्य) का एक सेट बीजक की दो प्रतियाँ जिस पर भूमिका द्वारा यह प्रमाणपत्र विधिवत् पृष्ठाकित हो कि उसके द्वारा भुगतान प्राप्त हो गया है और माल के उद्गम के बारे में प्रमाणपत्र की दो प्रतियाँ नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग यू० सी० ओ० बैंक विलिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली को भेज दी जाए।

(2) सर्वेशी

(विदेशी बैंकर)

आप से यह अनुरोध है कि प्रस्तेक असायगी पर भुगतान बीजक सहित पोललदान और अन्य दस्तावेजों (अपरकाल्य) का एक सेट बीजक की दो प्रतियाँ जिस पर भूमिका द्वारा यह प्रमाणपत्र विधिवत् पृष्ठाकित हो कि उसके द्वारा भुगतान प्राप्त हो गया है और माल के उद्गम के बारे में प्रमाणपत्र की दो प्रतियाँ नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग यू० सी० ओ० बैंक विलिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली को भेज दी जाए।

(3) नियंत्रक, सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक विलिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

ग्रन्तवचन्द्र—6

इच्छिट (सामान्य उद्देश्य) क्रेडिट के अन्तर्गत उपयोग के सम्बन्ध में वैमानिक रिपोर्ट को प्रदर्शित करने वाला विवरण

1. आयातक का नाम

2. आयात लाइसेंस की संख्या तथा दिनांक

3. आयात लाइसेंस का मूल्य

4. दिग् गण अद्वितीयों का मूल्य

5. प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक

6. प्राधिकार पत्र की धनराशि

7. प्राधिकार पत्र की धनराशि

8. वैमानिक के द्वारा उपयोग की गई धनराशि

इच्छिट

9. उपयोग की गई कुल धनराशि

इच्छिट

10. तरकारी जाति में जमा की गई कुल धनराशि

रुपय

11. आगामी वैमानिकों के द्वारा उपयोग की जाने वाली

भूमान

12. प्रम्पयणी, पर्दि कोई हो

वाणिज्य मंत्रालय की सावधानिक सूचना

म० : १७-प्राई ई सी० (पा० ए०) / ७९

दिनांक ९-२-१९७५ के तिए परियाप्ट-II

इच्छिट गामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अन्तर्गत निझी भेत्र आयाती के तिए लाइसेंस जारी करने के लिए शाते [

खण्ड-1 सामान्य

नीदरलैंड महानी रियर्स बैंक वार आर्टिकलिंगस लेन्डन एम० बी० द्वारा प्रदान किए गए 1977-78 के लिए इच मासान्य प्रयोजन क्रेडिट को विकासशील देशों के लिए खोल दिया गया है। तबनुसार इस क्रेडिट के अधीन वित्तनुक्त किए जाने वाले माल एवं पर्याप्त बत्तुएँ एवं इससे संबंधित आनुप्रयोगिक सेवाएँ नीदरलैंड से आयात की जा सकती हैं और परिशिष्ट 'क' के रूप में नीदरलैंड द्वारा दिवक्षी विकास उत्तर के अंतर्गत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए "मार्ग दर्शन" सूची में समिलित सभी देश (अनुबंध-1) इस क्रेडिट के अंतर्गत "पात्र स्वीकृत देश" होंगे। दोनों साथ कारों अर्थात् ही एक एन 1, 20 मिलियन और ही एल एन 54 मिलियन में प्रतिपूर्ति की अंतिम नियम 31-1-2-1980 होगी,

2. किन्तु पात्र से इतर स्रोत देशों से रसायन के संबंध में 10% की सीमा तक और अन्य आयातों के संबंध में 20% की सीमा तक के संघटकों को इस क्रेडिट के प्रत्यंगत वित्तदान किए जाने के लिए विचार किया जा सकता है। यदि कोई हो तो इस संबंध में विशिष्ट आवेदन संविदापूर्ण होने से पूर्व ही वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) डब्ल्यूई-III अनुभाग को किए जाने चाहिए।

3. इस क्रेडिट के प्रत्यंगत वित्तदान के लिए पात्र स्रोत देशों से उपर्युक्त खंड 1(2) में संकेतित सीमा से अधिक संभरण को संपूर्ण बनाने के लिए पात्र से भिन्न स्रोत देशों से माल और सेवाओं के सीमित संभरणों पर भी विचार किया जा सकता है। इसके लिए नीदरलैंड की सरकार का विधिष्ठ अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

खण्ड-2 आयात लाइसेंस जारी करना

2(1) आयात लाइसेंस 12 मास की प्रारम्भिक वैध प्रवधि के लिए लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर जारी किया जाएगा। वैध प्रवधि में वृद्धि के लिए लाइसेंस-धारी को जाहिए कि वे वैध प्रवधि के भीतर ही संबंध लाइसेंस प्राधिकारी से संपर्क स्थापित करे जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग से परामर्श लेगा।

2(2) पहले आदेश नीदरलैंड के गम्ब्रपार संभरकों को या अनुबंध-I में उल्लिखित देशों को लागत बीमा भाड़ा/लागत तथा भाड़ा के आधार पर अवश्य दिए जाने चाहिए और आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 4 मास के भीतर ही आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यूई-3 अनुभाग) को भेज दिये जाने चाहिए। यदि पहले आदेश देने का नियंत्रण निर्धारित चार मास की प्रवधि के भीतर नहीं हो पाता है तो लाइसेंस धारी को जाहिए कि वह जैसा भी मामला हो, मुख्य नियंत्रक, आयात-नियात की या अन्य लाइसेंस प्राधिकारियों को इसका कारण बताते हुए कि अर्थों नहीं प्रारम्भिक वैध प्रवधि के भीतर ही आदेश देने का काम पूरा हो सका, इसके अधिकारी एवं आयात के साथ आदेश देने की प्रवधि में वृद्धि की मांग करने के लिए प्रस्ताव रखे। आदेश देने की ऐसी प्रवधि में वृद्धि के लिए आवेदन पर विचार प्रत्येक मामले में पाक्षका के आधार पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा जो और आर मास की प्रवधि वृद्धि दे सकते हैं। लेकिन, पर्याप्त आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से 8 मास से अधिक की वृद्धि की मांग की जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपेक्ष रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यूई-3 अनुभाग), वित्त मंत्रालय को भेजे जाने चाहिए।

2(3) लाइसेंस पर "डब्ल्यू सामान्य प्रयोजन क्रेडिट" प्रक्रियत होगा और यह उस सार्वजनिक सूचना की सं० का संकेत करेगा जिसके अंतर्गत 'यह लाइसेंस तर्ते जारी की जाती है। प्रथम तथा वित्तीय प्रश्नय के लिए लाइसेंस कोड "एस"/"एनएन" होंगे। इस लाइसेंस कोड का उल्लेख सभी पोतल-दान प्रलेखों में होना चाहिए और साथ ही साथ राया जमा करते समय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित प्रपत्र "एस" में भी इसका उल्लेख होना चाहिए।

2(4) ऐसे ही आयातक आयात लाइसेंस प्राप्त करता है उसे चाहिए कि वह इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी के साथ वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यूई-3 अनुभाग) को एक रिपोर्ट भेजे :—

(1) आयात लाइसेंस की संख्या और वित्तक

(2) मूल्य

- (3) यदि कोई हो तो आयात लाइसेंस में संकेतिक भुग्ता विनियम दर
- (4) वह नारीख जिस तक आर्थिक कार्य विभाग को संविदा की प्रतियोगी जेने की संभावना है।

खण्ड-3 क्रेडिट को पूर्ण करना

3(1) इस क्रेडिट के अंतर्गत वित्तदान के लिए पात्र संविदा का न्यूनतम मूल्य छी एल एफ 25,000 रुपये होगा।

3(2) आयात लाइसेंस के मद्द केवल एक संविदा की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा करने के लिए अनुमति दी जाएगी जिसके लिए लाइसेंस जारी होने की तारीख के तुरन्त बाद ही वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

3(3) माल के आयात के लिए संविदा और नीदरलैंड से सेवाओं और पात्र स्रोत देशों का निष्पत्त्य अनुबंध-I में वथा उल्लिखित माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

3(4) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर माल और सेवाओं प्रौपचारिक खुले अंतर्राष्ट्रीय बोली के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी :—

(क) जहां नीदरलैंड आयातों के लिए परामर्शदाता या केवल एक मात्र स्रोत है, या

(ख) जहां आयातों का मूल्य छी एल एफ 1, 25 मिलियन से कम का है, या

(ग) जहां ऐसी कियाविधि लाग नहीं है पर उपयुक्त नहीं है इस मामले में नीदरलैंड सरकार और भारत सरकार के बीच करार किसी और अधिक उचित कियाविधि के आधार पर संमरण के लिए संविदा पूर्ण हो जाने से पूर्व ही निश्चित रूप से तथ हो जाना चाहिए।

3(5) निम्नलिखित मामलों में प्रौपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली का सहारा लेना भी आवश्यक नहीं होगा :—

(क) जहां केवल पात्र अपने उपकरण के पर्याप्त मानकीकरण फो बनाए रखने के लिए युक्तियुक्त कारण है।

(ख) उन मामलों में जहां विषयाधीन अधिप्राप्ति की प्रकृति के कारण सीमा संभरकों की संख्या सीमित है और क्रेडिट जानकारी देनी है कि उससे वह आया की जा सकती है कि वह योग्य संभरकों को जानता है।

(ग) जहां भारतीय आयातकों और विदेशी संभरकों के बीच चल रहे वर्तमान संबंध और नीदरलैंड और या विकासशील देशों में उपलब्ध और समर्पण संभरकों के अंतर्गत हुए कर्जदार यह समस्ता है कि आयात केवल नीदरलैंड से ही प्रभावी होने चाहिए। ऐसे मामलों में माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन अनुबंध-I वी कंडिका 31 से 39 में निहित अधिप्राप्ति का नियम अपनाया जाना चाहिए।

3(6) निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में केवल किसी भी एकमात्र संभरक से सीधे ही माल खरीद सकता है :—

(1) वाणिज्यिक आयातक द्वारा अधिप्राप्ति में पंजीकृत खण्डनाम की वह पर्याप्त बस्तु शामिल होती है जो आयातक द्वारा पुण: बेचने के लिए है और जिसके लिए आयातक संभरक का नियमतः प्राधिकृत वितरक है या व्यापारी है और जिसके लिए संभरक एकमात्र वितरक है या विनिर्माणकर्ता है।

(2) वाणिज्यिक आयातक द्वारा अधिप्राप्ति में वह पर्याप्त बस्तु शामिल होती है जो विनिर्माण संसाधन या अन्तिम उत्पाद के सज्जीकरण और पुण: बिक्री के लिए प्राप्त और जिसके लिए आयातक संभरक का नियमतः प्राधिकृत वितरक है या व्यापारी है और जिसके लिए संभरक विनिर्माणकर्ता है।

- (3) विशेष दिजाइन या तकनीकी आवश्यकताओं के कारण मूल रूप की अदला अदला का मुनिश्चय करने देते अधिप्राप्ति केवल एक स्रोत से की जा सकती है।
- (4) आयातक एक ऐसा विनिर्माणकर्ता है जिसके उपकरण और कच्चे माल का फार्मूला ऐसे कच्चे माल की, विशेष किस्म के साथ अधिक से अधिक उपयोग के लिए बनाए गए हैं जो केवल एक ही स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं।
- (5) आयातक औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय बोली के अंतर्गत मूल रूप से की गई अधिप्राप्ति को बढ़ाना चाहता है या फिर से उसे प्राप्त करना चाहता है वर्तमान की मूल अधिप्राप्ति की तुलना में अनुपरक अधिप्राप्ति कम है, और कुछ अवसर पर ही की जाती है और जब मूल अधिप्राप्ति के संबंध में निर्माण कार्य अपनी चर रहा है या भूल अधिप्राप्ति के तुरन्त बावही की जाती है।
- (6) सौदे का मूल्य ये एक एल 1.25 मिलियन से कम है।
- 3(7) परामर्शदाता फर्मों के चुनाव के लिए औपचारिक प्रतियोगी बीली क्रियाविधि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारतीय फर्मों द्वारा परामर्शदाता फर्मों को सुझावों के लिए निर्माण भेजने से पूर्व ही ऐसी भावी फर्मों की एक सूची विस्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) को भेजी जानी चाहिए। इसके बाद सूची नीदरलैंड की सरकार खो सेजी जाएगी जो इसे स्वीकृति दे सकती है या परामर्शदाता की पसन्द को रद्द कर सकती है और नीदरलैंड से परामर्शदायी क्षेत्र की जामकारी के आधार पर इस सूची को बढ़ाने के लिए सुझाव दे सकती है।
- 3(8) जहाँ औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली के आधार पर माल की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव किए जाते हैं तो आयातक को आहिए कि वह जैसे ही निविदा नोटिस भारतीय व्यापार पक्षिका या भारतीय निर्यात बुलेटिन में विज्ञापन के लिए भेजे उसी समय इनकी दीन प्रतियों को विस्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) नई दिल्ली को अवगत कराते हुए भारत में नीदरलैंड के राजहूत को भेज दें।
- 3(9) खंड 2(2) में उल्लिखित “पुष्टि आदेश” भर्त का अर्थ है भारतीय लाइसेंस धारी द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया वह आदेश जो बाद बाले के पुष्टिकरण आदेश द्वारा विधिवत् समर्पित हो या क्य संविदा जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा समर्पित हो या क्य-संविदा जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो। विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं के पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।
- 3(10) यदि संविदा उच्च संभरक के साथ की गई तो संविदा के लागत-बीमा-भाड़ा/लागत एवं भाड़ा मूल्य को, उच्च गिल्डर में व्यक्त करना चाहिए और यदि संविदा पाक स्रोत देशों के संभरकों के साथ की गई हो तो उनकी मुद्रा में व्यक्त करना चाहिए।
- 3(11) संविदा में भुगतान की व्यवस्था नकद/उधार पर होनी चाहिए अथवा पोस्ट-नवान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर। विदेशी संभरकों भारतीय आयातकों की किसी भी प्रकार की साख-सुविदा उपलब्ध करने की स्वीकृति नहीं देंगे।
- 3(12) संविदा के मूल्य में सम्मलित भारतीय अभिकर्ता के कमीशन की धनराशि को विशेष रूप से अंकित किया जाना चाहिए। इस संबंध में किसी प्रकार भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा में प्रेषण स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के भाग के रूप में होंगे और इसलिए लाइसेंस के लिए वसूल किए जाएंगे।
- (3) क्य आदेश और संभरक के पुष्टिकरण आदेश केवल अंत्रीम में ही होनी चाहिए।
- (4) संविदा में निम्नलिखित व्यवस्थाओं को विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिए :—
- (1) संविदा भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है (यदि संविदा का मूल्य उच्च गिल्डर में 50,000 या इससे कम हो) और यह भारत सरकार तथा नीदरलैंड सरकार दोनों के अनुमोदन के अधीन है (यदि संविदा का मूल्य उच्च गिल्डर 50,000 से अधिक हो जाता है)।
 - (2) यह संविदा उच्च सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के लिए लाइसेंस देशों के अंतर्गत वी गई भुगतान क्रियाविधि द्वारा संचालित होनी चाहिए और इस संबंध में भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के बावही यह प्रभावी होनी।
 - (3) “माल उच्च मूल्य/विनिर्माण के हैं” (नीदरलैंड में संभरकों के मामले में)
- या
- “माल— मूल्य/विनिर्माण के हैं” (पाक स्रोत देशों के संभरकों के मामले में)
- (4) नीदरलैंडस से आयात किए जाने वाले माल के लिए संभरकों को नीदरलैंडस पूंजी निवेशक बैंक को उस जिले के नीदरलैंड व्याणिज्य मंडल द्वारा जिसमें संभरक स्थापित है जारी किया गया/प्रमाणित किया दुआ इस बारे में एक प्रमाणपत्र वी प्रतियों में देना पड़ेगा कि माल नीदरलैंड मूल का है। वह प्रमाणपत्र भुगतान करते समय अन्य पोतलादान दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रमाणपत्र दस्तावेजों साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रमाण पत्र का एक नमूना अनुबंध-5 में दिया गया है।
- पाक स्रोत देशों के संभरकों के मामले में संभरकों को “माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन (अनुबंध-1)” में लिए गए उद्घाट नियमों के अनुसार एन० आई०ओ० को माल के उद्घाट का प्रमाण देना पड़ेगा।
- 3(15) जहाँ प्रथागत निष्पादन गारंटी अपेक्षित हो वहाँ संभरकों से बैंक गारंटी/गारन्टी को प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए।
- खंड : 4 भारत सरकार नीदरलैंड पूंजी निवेशक बैंक द्वारा संविदा का अनुबंध
- (1) (क) संविदापूर्ण होने के दुरन्त बावही आयातकों को आयात लाइसेंस की एक फोटो प्रति के साथ संविदा/संभरण आदेश की 5 फोटो या प्रमाणित प्रतियों व्याणिज्य मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) को भेजनी चाहिए। पाक स्रोत देशों के संभरकों के साथ पूर्ण की गई संविदाओं के मामलों में उसकी 8 प्रतियों भेजी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आयातक के लिए अनुबंध-2 में उल्लिखित सूचना भी भेजना आवश्यक है।
 - (ख) उच्च संभरकों के भाव पूर्ण की गई संविदाओं के मामले में आयातकों को स्टाप्स समाहर्ता द्वारा विधिवत् न्याय नियमों विरुद्ध प्रपत्र में अनुबंध-4 अनुमोदित बैंक से एक बैंक गारंटी भेजनी चाहिए। बैंक गारन्टी संविदा की धनराशि के समतुल्य रूपए को दणदणि दुए व्याज और अन्य प्रभारों सहित उम धनराशि के लिए होनी चाहिए जिसके लिए प्राक्तिकार पत्र मांगा गया है परिवर्तन की बर आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि और प्रबलित राजस्व और बैंकिंग विभाग द्वारा अधिसूचित विनियम दर होनी।

4(2) जब संभरक संविदा आपकारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली या आपकारिक चुनिता अंतर्राष्ट्रीय बोली पर आधारित हो तब निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए :—

- (1) उस प्रकाशन का नाम जिसमें निविदा सूचना विशेष की गई थी ।
- (2) उन पाठ्यों के नाम जिन्होंने निविदा पूछताछ के महे दाम बढ़ाए हैं ।
- (3) विशेष प्रस्ताव को चुनने के लिए कारण और यह भी बताया जाए कि आया कि यह न्यूनतम तकनीकी उपयुक्त बोली थी ।

4(3) यदि संविदा दस्तावेज प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन, आयात लाइसेंस और बैंक गारंटी सही पाए जाते हैं तो तिन मेंब्रालय, आधिक कार्य विभाग संविदा की प्रतियों को हेंग में भारत के राजसूतावास के माध्यम से डच प्राधिकारियों को अनुमोदन के लिए भेजेगा।

4(4) 50,000 डच गिल्डर या इससे कम मूल्य की संविदाओं के संबंध में डच प्राधिकारियों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के अनुमोदन के बारे में भारतीय आयातक को उनकी संविदा/संभरण आदेश की प्रतियों डच प्राधिकारियों को भेजते समय बताया जाएगा। 50,000 डच गिल्डर से अधिक की संविदाओं के लिए, जैसे ही डच क्रेडिट के अंतर्गत इच प्राधिकारियों द्वारा संविदा के वित्त दान के लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाता है जैसे ही आयातक को यह सूचित कर दिया जाएगा कि उनकी संविदा प्रभावी हो गई है।

खंड 3 संभरकों को भुगतान क नीदरलैंड के संभरकों भुगतान

5(1) विकासगील देशों के लिए नीदरलैंड पूजी निवेशक बैंक बैंक विं हेंग को एक प्राधिकार पत्र (अनुबंध-5 के रूप में) हेंग में भारत के राजसूतावास के माध्यम से पोतलदान दस्तावेज के महे संभरकों के लिए भुगतान को प्राधिकृत करते हुए जारी किया जाएगा और संविदा आदि की प्रतियों के साथ उसे डच प्राधिकारियों को प्रदेशित किया जाएगा।

5(2) प्राधिकार पत्र की वैधता का सुनिश्चय संविदा में निर्विट वितरण अनुसूची को घ्यान में रखते हुए किया जाएगा। किसी भी मामले में प्राधिकारपत्र, आयात लाइसेंस की वैधता के बाद वैध नहीं होगा।

5(3) चूकि क्रेडिट के अंतर्गत सामान्य संभरकों को भुगतान पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के महे ही किए जाते हैं अतः इस क्रेडिट के अंतर्गत वित्तदान किए गए आयातों के लिए रियायती अवधि की सुविधा लागू नहीं होगी।

5(4) संभरकों का पोतलदान/भुगतान प्राधिकारपत्र की वैधता अवधि के भीतर पूरा न किया जाने के मामले में, आयातक को विन मंत्रालय, आधिक कार्य विभाग (इल्यु ई-3 अनुभाग) के शाश्वत प्राधिकार पत्र की समाप्ति अवधि से बहुत पहले ही प्राधिकारपत्र में उपयुक्त बृद्धि के लिए, गम्भक स्थापित करना चाहिए। यदि मार्गी गई बृद्धि प्रथम सूत आयात लाइसेंस की वैधता से अधिक हो तो पुनर्वेद्ध भूत आयात लाइसेंस की वैधता से अधिक हो तो पुनर्वेद्ध सूत आयात लाइसेंस की वैधता अवधि वज्री जारी की वैधता अवधि वज्री दी गई है, आवेदनपत्र ये गाथ भेजी जानी चाहिए।

5(5) यदि प्राधिकारपत्र की वैधता अवधि में बृद्धि के लिए आवेदन, प्राधिकार पत्र की वैधता तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हो जाती तो प्राधिकार पत्र में अवयुक्त शेष धनराशि वापिस कर दी गई समझी जाएगी और प्राधिकार पत्र शामें आपका अवधि वज्री गया समझा जाएगा।

5(6) मूल पराकारम्य पोतलदान दस्तावेज निरपवाद रूप से नीदरलैंड पूजी निवेशक बैंक द्वारा भारत में संभवित आयातक के बैंक को भेजे जाएंगे जिसे यह सुनिश्चय करते के बाद ही संभवित आयातक का परकारम्य

दस्तावेज रिहा करने वाहिएं कि आयातक ने निम्नलिखित को जमा कर दिया है :—

- (1) सार्वजनिक सूचना मं० 8-आई०टी०सी० (पी०एन०)/76 दिनांक 17 जनवरी, 1976 में यथा निर्धारित आयात मूल्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रित की सार्वजनिक सूचनाओं में राजस्व-मूल्य पर यथा प्रधिसूचित या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुद्रा विनियम नियंत्रण पत्रिकाओं के माध्यम से गणना की जाने वाली प्रचलित मिश्रित दर पर डच गिल्डर में मंदरकों को भुगतान के सम्बन्ध लगा।
- (2) दिकासगील देशों के लिए नीदरलैंड पूजी गम्भ निवेश बैंक एन० सी०, दिव्य हेंग द्वारा मंदरकों को वास्तविक भुगतान की तारीख से आयातक द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया नीस हजारी, दिल्ली या रिजर्व बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली में समनुल्य रूपये के वास्तविक निक्षेप की निधि तक निष्पत्त गया की जाने वाली अपेक्षित धनराशि के लिए वैध उपर्युक्त (1) सार्वजनिक सूचना मं० 46 आई०टी०सी० (पी०एन०)/76 दिनांक 16 जून, 1976 के अनुदार प्रथम 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर प्रयोग 30 दिनों की अवधि में अधिक के लिए 15% वार्षिक दर के हिसाब से व्याज।

5(7) यह सुनिश्चय करने की विमेंद्ररारी संबंधित भारतीय बैंक की हांगी कि आयातक को आयात दस्तावेज सौचना से पूर्ण हो देय धनराशि गरकार के लेख में डीक प्रकार से जमा करा दी गई है। लाइसेंसधारी की यह भी सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि बैंकों से दस्तावेजों को सुपुर्दगी लेने से पूर्ण हो देय धनराशि डीक प्रकार से सरकारी लेख में जमा करा दी जाए है।

5(8) आयातकों की अपेक्षित रूपया निक्षेप के ब्रह्म प्रदेशी मुद्रा विनियम के प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से करना चाहिए और सार्वजनिक सूचना नं 184-आई०टी० सी० (पी०एन०)/68 दिनांक 30 अगस्त, 1968 में यथा अपेक्षित लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति भी उनके द्वारा पूर्णांकित करवा लेना चाहिए। अपेक्षित प्रपत्र "एम" गवंधित वैद द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया वैर्षी के लिए व्याज जाएगा।

5(9) खंड 5(6) में उल्लिखित धनराशि को स्टेट बैंक आफ इंडिया, नीन हजारी शाखा, दिल्ली या रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली के पाल केन्द्रीय नस्कार के लेख में निक्षेप के 9% निम्नलिखित विवरणीय के अंतर्गत जमा की जानी चाहिए :—

"के—चिपोंजिट्स एड एस्ट्रोमेज डिपोंजिट लाट विमिर्ग इलेस्ट-843-मिविल डिपोंजिट्स डिपोंजिट्स फ०२ पानेजिस एट्सेंट्रो—एस्ट्रेजिस एट्सेंट्रो—अंडर डच जनल परपज क्रिट 1978-79".

5(10) उपर्युक्त उल्लिखित रूपये निक्षेप की सूचना विवरणीय माध्यम से अवधि विभाग, य०० स०० ओ० बैंक बिल्डिंग पानियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए और इसके माथ सार्वजनिक सूचना सं०७४-आई०टी० सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 31 मई 1974 और 103 आई०टी० सी० (पी०एन०)/74 विवाक 2-10-1976 में निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किए गए मूल द्वाजाना घालान को भी भेजना चाहिए। प्राधिकार एवं सं० के सम्बन्ध में सूचना, विवेणी मद्रा की वह धनराशि जिसके लिए निक्षेप किया गया है, डच संभरकों को भुगतान की तिथि, व्याज की धनराशि और वह प्रवधि जिसके लिए इसकी गणना की गई है, तिरपवाद रूपये में राजकोप्र चालान में योकेति दुकी जानी चाहिए।

प्रतिपूर्ति क्रिया-विधि :

5(11) उन आयात लाइसेंसों के मामले में जहाँ उनका मूल्य 1 लाख रूपये से कम है, आयातक को प्रतिपूर्ति क्रिया विधि को छूने

की छोटी होयी बगरें की निष्पादन आविष्कार के लिए कोई भी भुगतान रोका जाना चाहिए नहीं है। इस प्रणाली के अंतर्यात आयातकों को बैंक वापर संस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है विन्यु उनकी संविदा में यह निर्दिष्ट होता आहिए कि कि भूतान की विधि प्रतिपूर्ति प्रणाली द्वारा होती है। आयातकों द्वारा उनके संविदा के अनुमोदन प्राप्त होने पर खोलना होगा। इस प्रयोजन के लिए आयातक द्वारा यथानिविष्ट नीदरलैंड में संभरक के बैंक के लिए साक्षपत्र खोलने के लिए प्राधिकत करते हुए आयातक के बैंक को एक प्राधिकारपत्र (अनुबन्ध-6) विन मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (छठव्यू. ई-3 अनुभाग) द्वारा जारी किया जाएगा। आयातक द्वारा साक्षपत्र के महे भुगतान आयात साइरेस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति के आधार पर किया जाएगा। आयातक द्वारा साक्षपत्र के महे भुगतान आयात साइरेस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति के आधार पर किया जाएगा। सामान्यता संभरकों को सभी पोतलदान/भुगतान उपर्युक्त प्राधिकार पत्र के जारी होने से 20 महीनों के भीतर पूरा कर दिए जाने चाहिए। संभरकों को पोतलदान/भुगतान वीम महीने की अवधि के भीतर पूरा न किए जाने के सामने से आयातकों को चाहिए कि वह निरपाद रूप से संभरकों को पोतलदान/भुगतान को पूरा करने के लिए, समय की सीमा बढ़ि के लिए, इस निर्धारित अवधि के समान होने से कम से कम एक महीना पूर्व ही विन मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग छठव्यू. ई-3 अनुभाग से समर्क स्थापित करें। यह आवेदन, मार्ग गई अवधि बढ़ि को शामिल करते हुए पुनर्बंधित आयात साइरेस की फोटो पति द्वारा समर्थित होना चाहिए। यदि ऐसा आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो उनकी संविदा में प्रत्येक शेष धनराशि वापिस कर दी गई समझी जाएगी। आयातक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियवक, आर्थिक कार्य विभाग, पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली -1 को माल के पोतलदान के 15 दिनों के भीतर ही संभरक को किए गए भुगतान के सम्बन्ध में अपने बैंक से एक प्रमाणपत्र और उच्च संभरक से इस बारे में एक प्रमाणपत्र के साथ बीजक की दो प्रतियों को भेजेगा कि “उपर्युक्त उच्च गिल्डर की धनराशि जो बीजक मूल्य बामाल के पोतलदान के 100% के बराबर है “उसे प्राप्त कर दिया है। यह यही भी सुनिश्चय करेगा कि संभरक द्वारा बंड 3(14)(4) में उल्लिखित माल के उद्गम माल के बारे में प्रार्थनाएँ की दो प्रतियां सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियवक को माल के पोतलदान के 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर भेज दी जाती है। आयातकों की ओर से आर्थिक कार्य विभाग को जल्दी से नियंत्रण द्रग्नावज्ञों को भेजने से सम्बद्ध किसी भी आपरदाही पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और मुख्य नियवक, आयात-नियर्यत को आयातक के नाम में गमी आयात लाइसेंस नियवित करने के लिए कहा जा सकता है। यदि आयातक गलती करता है तो एक हालत में उसके सामने को मूल्य नियवक, आयात-नियर्यत को कानी सूची में रखने के लिए गिरावण की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आयातक को आयात नियंत्रण आविष्कार का सामिन करने वाले प्रधिनियम के अत्यर्गत जुर्माना/ग़ज़ा किया जा सकता है। आयातक द्वारा प्रतिपूर्ति कियाविधि का विकल्प लेने के मामने में उन न बेदा की 8 फोटो प्रतियों विन मंत्रालय द्वारा अपनी संविदा के लिए अनुमोदन प्राप्त करने समय भेजनी चाहिए।

पात्र स्वीकृत देशों में भुगतान

5(12) आयातक द्वारा उनके आवेदन पत्र में यथा संकेतित संभरक के नाम में नात्र स्वीकृत देश में संभरक के बैंक के लिए साक्ष पत्र खोलने के लिए प्रविष्ट करने हुए एक प्राधिकार पत्र (अनुबन्ध-6 के रूप से) विन मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (छठव्यू. ई-3 अनुभाग) द्वारा स्वाला जाएगा। उपर्युक्त प्राधिकार पत्र की प्रति के साथ संविदा की प्रतियां भी हेंग में भारत के राज्यहन्तावास द्वारा उच्च प्राधिकारियों को प्रेषित की जाएंगी।

5(13) पूर्व की किंकारियों में उल्लिखित प्राधिवारपत्र की पावती के बाद आयातक का बैंक उक्त प्राधिकार पत्र के जारी होने की सार्वत्व में 30 दिनों के भीतर ओर वैध आयात साइरेस के महे अपने बैंकर के

भाष्यम से मंत्रक के नाम में एक साथ पत्र खोलगा। हम संबध में सूचना, लेखा लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, य००मी० घ्रो० बैंक विलिंग पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजी जाएगी।

5(14) संभरक को भुगतान किए जाने के बाद संभरक का बैंक संदायता लेखा; एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, विन मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, य००मी० घ्रो० बैंक विलिंग पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजी जाएगी।

5(15) संभरक का बैंक संभरक से माल के उद्गम द्वेष के संबंध में एक प्रमाणपत्र या एक प्रमाण (दो प्रतियों में) इस संबध में प्राप्त करेगा कि वह माल और सभी की प्रधिवालिक के लिए सामांदर्यन के लिए संभल उद्गम द्वेष के नियमों के अनुसार है और उसे सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियवक, विन मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, य००मी० घ्रो० बैंक विलिंग, पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भजेगा।

5(16) आयातक का चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैंक प्रभारों का लाइसर बीजक/माल के दान के मद्दे उनके द्वारा संभरक को किए गए प्रेषणों के एक प्रमाण पत्र को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, विन मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, य००मी० घ्रो० बैंक विलिंग, पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भजे।

आयातकों को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैंक प्रभारों का लाइसर बीजक/माल के दान के मद्दे उनके द्वारा संभरक को किए गए प्रेषण के एक प्रमाण-पत्र को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, विन मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, य००मी० घ्रो० बैंक विलिंग, पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भजे। आयातक को यह भी सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि उसका द्रस्तावेज का एक परकासमय सेट और बीजक की दो प्रतियों के साथ संभरक द्वारा भुगतान की पावती के संबंध में विधिवत पूर्णांगित प्रमाणपत्र और यह 5(14) और 5(15) में उल्लिखित उद्गम प्रमाणपत्र माल के लदान से 15 दिनों के भीतर विन मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, को भेज दिए जाने हैं।

5(17) आयातक द्वारा साक्षपत्र के महे भुगतान आयात साइरेस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति आधार पर किए जाएंगे।

5(18) आयातक: सभी लदान/संभरकों के लिए भुगतान उपर्युक्त उल्लिखित प्राधिकारपत्र के जारी होने से 20 माम की अवधि के भीतर पूर्ण अद्वितीय जाने चाहिए। ऐसे सामनों में जहां लदान/संभरकों के लिए भुगतानों का 20 माम की अवधि के भीतर पूर्ण करने की सभावना न हो तो आयातक को चाहिए कि वह निरपाद रूप से लदान/संभरकों के लिए भुगतान को पूरा करने के लिए उपर्युक्त प्राधिकार सीमा की समाप्ति से कम से कम एक माम पूर्व ही विन मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (छठव्यू. ई-3 अनुभाग) में संभरक स्थापित करें। इस प्रकार के आवेदन के साथ पुनः बैंक आयात लाइसेंस की एक कोटी प्रति भी भेजी जानी चाहिए कि जिसमें मार्ग गई गई अवधि दृढ़ी भी शामिल हो यह यदि इस प्रकार का आवेदन निर्धारित प्रधिष्ठि से पूर्व ही प्राप्त नहीं होता है तो संविदा के अप्रयुक्त स्वेच्छा को अभ्यासित किया गया समझा जाएगा।

5(19) आयातकी ओर से आर्थिक कार्य विभाग की शीघ्र ही प्रति-पूर्ति द्रस्तावेज भेजने में किसी भी दृढ़ि पर गंभीरता पूर्वक विचार विया जाएगा और मुख्य नियवक, आयात-नियर्यत को आयातक के नाम में जारी किए गए सभी लाइसेंसों को स्थगित करने के लिए कहा जा सकता है। यदि आयातक चुक करता रहे तो उसका मामादा भूद्य नियवक, आयात-नियर्यत की कार्नी-सूची में लिखने के लिए भेजा जा सकता है।

5(20) प्रतिपूर्ति द्रस्तावेजों की पावती के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियवक, विन मंत्रालय, नीदरलैंड पूजीगत बैंक को पात्र स्वीकृत

देशों से संभरकों का भुगतान की गई धनराशि की प्रतिपूति के लिए आवेदन करेगा नीदरलैंड वूर्जियत बैंक प्रतिपूति की तारीख की नीदरलैंड में प्रबन्धित मशा दर पर नीदरलैंड, गिल्डर में समतुल्य धनराशि की प्रतिपूति करेगा।

खण्ड 6—विविध

6(1) आयातक को चाहिए कि वह लाइसेंस के उपयोग की स्थिति को दर्शाति हुए अनुबंध-7 के रूप में एक वैभासिक रिपोर्ट वित्त मंत्रालय, आर्थिक काय विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुबंध) को भेजें।

6(2) इसे जान लेना जाहिए कि लाइसेंसाधारी और संभरकों के बीच यदि कोई क्षणज्ञ उठता है तो भारत नरकार इसकी जिम्मेदार नहीं होती। संभरकों भुगतान प्रणाली किए जाने से पूर्व ही उसके डारा पूर्ण की जाने वाली शर्त आयातक द्वारा साफ रूप से अनुबंध-2 में बता दी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो भागड़े के निपटान से संबंधित एक अवस्था भी संविदा में शामिल की जाए।

6(3) लाइसेंसधारी आयात लाइसेंस या इस संबंधित किसी एक या सभी मामलों पर तथा उच सामान्य प्रयोजन केंटिंग के अंतर्गत सभी प्रकार के आमारों को पूरा करने के संबंध में राखकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों, अनुदेशों और आदेशों का तुरंत पालन करेगा।

6(4) उपर्युक्त केंटिंग में दी गई नैनों का उल्लंघन या प्रतिक्रिया करने पर आयात तथा नियोत (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबंध-1

नीदरलैंडस द्वारा द्विविध विकास अट्टे के अन्तर्गत माल और सेवाओं की प्रधिप्राप्ति के लिए भाग वर्ग

क. सामान्य

1. मे सार्व-दर्शन द्विविध अट्टे के अंतर्गत माल और सेवाओं की प्रधिप्राप्ति को शासित करते हैं जो कि शासकीय नीदरलैंड विकास सहायता कार्यक्रम का एक भाग है। ये अट्टे विकासान्निधि देशों के लिए उपलब्ध हैं। पात्र स्वीकृत देशों की सूची परिषिष्ठ 'क' के रूप में संलग्न है। इस सूची में प्राप्तकर्ता देश शामिल है। नीदरलैंडस की सरकार पात्र स्वीकृत देशों से अंतर्गत की कमी को पूरा करने के लिए पात्र स्वीकृत देशों से वाहन और वीमा कीमतों सहित माल और सेवाओं के सीमित संभरण हैं लिए अविकल्प आधार पर सहमत हो सकती है।

2. नीदरलैंडस की सरकार को इसके लिए अवश्य ही संयुक्त हो प्राना चाहिये कि अट्टे से प्राप्त लाभ का उपयोग, अर्थ अवस्था, कार्यक्रमता अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निपत्तकर्ता और पात्र स्वीकृत देशों के बीच बेना किसी भेद-भाव को ध्यान में रखते हुए और इन सार्व-दर्शनों में बताई अधिप्राप्ति क्रिया-विधियों के अनुमार किया जाना है।

3. केंटिंग 16 और 17 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर ऐसे ही भी प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिये जिससे यह पला जलता हो गा यह परिणाम निकलना हो कि किसी एक विशेष देश के एक विशेष प्रबन्धक को या संभरकों का पक्ष लिया जा रहा है।

4. माल और सेवाओं की प्रधिप्राप्ति के लिए अट्टी द्वारा अपनाए जाने वाले उच्चण के नियम और नियंत्रण इन सार्व-दर्शनों के साथ परिषिष्ठ 'क' के रूप में संलग्न कर दिए गए हैं।

5. ऐसे मामले में जहाँ अट्टी पर अधिप्राप्ति का सीधा प्रभाव नहीं इतना तो वह ऐसी अवस्थाएं करेगा जिसे वह मुमिलकर करने के लिए आवश्यक है कि खरीदवार इन सार्व-दर्शनों का अनुपालन करता है।

6(1) अट्टी निम्नलिखित मामलों को छोड़कर श्रीप्रबारिक अंतर्राष्ट्रीय बोली के साध्यम से माल और मेशाए प्राप्त करेगा।

(क) जहाँ नीदरलैंडस परम्परागत या आयातों के लिए केवल एकमात्र स्वीकृत है;

(ख) जहाँ आयातों का मूल्य दी एक एस 1.25 मिलियन मे कम है;

(ग) जहाँ इस प्रकार की किया विधि लागू नहीं होती या उपयुक्त नहीं है। इस मामले में नीदरलैंडस भरकार और अट्टी देश के बीच करार किसी अन्य उचित किया विधि से संभरकों को उनकी बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने से पूर्व ही पूरा कर दिया जाना चाहिये। इस प्रकार का करार राजकीय नीदरलैंडस राजद्रुतावास के साध्यम से अट्टी द्वारा दी जाने वाली सभी समदू जानकारी के आधार पर किया जाना है।

6(2) जहाँ भारतीय आयातकों और विदेशी संभरकों के बीच कायम बताना संबंध और नीदरलैंडस और या विकासशील देशों में उपलब्ध और प्रसिद्धता संभरणों के प्रबन्धर के प्रकाश में अट्टी समझता है कि भाया के बत नीदरलैंडस से ही प्रभारी किए जाने चाहिये तो अरीदार, केवल नीदरलैंडस के लिए बोली की सीमित रखने के लिए या नीदरलैंडस और साथ ही साथ पात्र स्वीकृत देशों से बोलियों प्राप्त करने के लिए विकल रखेगा। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 31-33 के साथ मार्ग-दर्शन का अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 34-38 के साथ अनुच्छेद 30 लागू है।

7. मे मार्ग-दर्शन और साथ ही साथ उद्गम के नियम और पात्र स्वीकृत देशों की सुची नीदरलैंडस की सरकार के संशोधनाधीन हैं।

(क) श्रीप्रबारिक बुली अंतर्राष्ट्रीय बोली के लिए क्रियाविधि

8. बोली के लिए आमंत्रन जारी करते समय अट्टी (या अट्टी की ओर से अरीदार) निम्नलिखित दो प्रकाशनों में से कम से कम एक बोली का विज्ञापन देगा:

भारतीय व्यापार परिका

भारतीय नियंत्रि सेवा बुलेटिन

आयातक भारतीय व्यापार परिका या भारतीय सेवा बुलेटिन मे यथा क्रियाविधि निविदा नोटिस की तीन प्रतियों भारत स्थित नीदरलैंडस के राजद्रुतावास को भेजेगा।

9. प्रतियोगिता को व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी अलग-अलग सविताये जिनके लिए जब कमी संभव हो बोलियों आमंत्रित की जाती है वह इतनी जड़ी होनी चाहिये कि अंतर्राष्ट्रीय आधार पर बोलियों को आकर्षित कर सके। इसी तरफ यह कि यदि तकनीकी और प्रशासनिक दूषित से एक परियोजना को विशेष प्रकार की संविदाओं में विभाजित करना संभव हो और इस प्रकार के विभाजन से अट्टी को लाभ हो और या इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली और भी विभाजन जाए तो परियोजना विभाजित की जानी चाहिये। अभियान्त्रिक, उपकरण और निर्माण कार्य (सामान्यतः टर्न की कान्डेक्ट के रूप में जाने जाते हैं) के लिए एकल संविदाओं की बांधा की जा सकती है यदि वे उपलब्ध तकनीकी एवं आर्थिक संविदाओं के भीतर अट्टी देश के लिए संपूर्ण साम अपेण करती हैं।

10. विशेष रूप से सिविल कार्यों की संविदाओं के लिए श्रीप्रबारिक पूर्व योग्यता की बांधा की जा सकती है। यदि पूर्व-योग्यता की बांधा की जाती है तो यह इन बातों की ध्यान में रखते हुए पूर्णतः संतोष-जनन निष्पादन की क्षमता पर आधारित होनी चाहिये (1) इसी प्रकार के कार्य में कार्य का पूर्व अनुभव (2) कार्यकार, उपकरण एवं संयंत्र के संबंध में इसकी क्षमता और (3) इसकी आर्थिक स्थिति और संविधान। पूर्व-योग्यता

किया विधि का विवाहन कंडिका 8 में उल्लिखित किया विधि के अनुसार किया जाएगा। पूर्वयोग्यता के लिए विचार किए जाने वाले इच्छुक ठेकेवारों के लिए संक्षिप्त विशिष्टिकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। जब पूर्वयोग्यता लागू हो जाती है तो वे सभी फर्म जो पूर्वयोग्यता की शर्तों को पूरा करती हैं बोली के लिए अनुमत होंगी।

11. बोली के दस्तावेज उन भाषाओं में से किसी एक भाषा में तैयार किए जाएंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय पहचानवार में साधारणतया प्रयोग की जाती है और जब तक कानूनी तौर पर रोक नहीं लगा विया आता हम बात का उल्लेख करेंगे उक्त भाषा दस्तावेज के मूल पाठ में लागू रहेगी।

12. विशिष्टिकरण में किए जाने वाले कार्य संभरण किए जाने वाले माल और सेवाओं सहा सुरुदीय या संस्थापन की जगह के लिए जहाँ तक संभव ही साक और मुस्लिम रूप से बताया जाएगा। इंहें विशिष्टिकरण के विषय के अनुकूल होती, जहाँ के अनुकूल नहीं होती तो उसका मूल पाठ लागू होगा। विशिष्टिकरण में मूल्यांकन के मिहान और बोलियों की सुनाना का उल्लेख करेगा जो नव लेखों में लिए जाएंगे जब मूल्यांकन किए जाएं हैं और बोलियों की तुलना की जाती है। विशिष्टिकरण में हम प्रकार से निया जाना चाहिये जिसमें कि स्वतन्त्र और मौर्यां अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को स्वीकृति एवं प्रोत्साहन मिल सके।

किसी प्रकार को अन्तरिक्ष आनकारी, स्पष्टीकरण गतियों में सुधार और विशिष्टिकरणों में परिवर्तन तथा बोली के लिए आमतण से उनको शोध ही अवगत करा विया जाएगा जिन्होंने मूल बोली दस्तावेजों के लिए अनुग्रह किया था।

13. यदि हम प्रकार के राष्ट्रीय मानकों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार की उपकरण या मान होने आवश्यक हों, तो विशिष्टिकरण में यह बताया जाएगा कि वे माल जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत मानकों को पूरा करते हैं जिनमें उल्लिखित मानकों के अलावा उनके बराबर या अच्छी किसी की मान की गई ही हों तो वे भी स्वीकार किए जायेंगे।

14. यदि विशेष फालतु पुर्जों की अपेक्षा की जाती है या यह निष्चय किया जाता है कि कुछ अनिवार्य गुणकाता को बनाए रखने के लिए एक विशेष मात्रा के मानकीकरण की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन और धनाया पर आधारित होने और उनमें केवल तभी पंजीकृत मार्क नाम, सूची संख्या या विशेष विनियोगिता के उत्पाद निर्धारित होने चाहिये। अन्तिम मामले में विशिष्टिकरण में विकल्प उन सामान के प्रस्तावों को स्वीकृत ही जाएगी जिनमें मिलती-जुलती विशिष्टताएँ हैं जिनका निष्पादन और बालिटी कम से कम उन विशिष्टिकरण स्तर के बराबर है।

15. बोली के लिए निमंत्रण में वाक्य स्वीकृत वेणों का उल्लेख किया जाएगा और उदाहरण के लागू नियमों को बताया जाएगा।

16. कोटेजन की जांच पात्र स्वीकृत देशों के संभरकों के बीच पूर्णतः बाबूरी की शर्तों के आधार पर की जाएगी (इसमें माल और उपकरण के लिए सीमांतर्क ट्रेटिक और अन्य करों और इसी प्रकार के प्रभावी करों की निःशुल्क कीमतों पर कोटेजन के मूल्यांकन भी शामिल हैं) लेकिन अग्री देश माल और सेवाओं के संभरण के लिए बोली के मूल्यांकन और मिलान करने के लिए जिसमें परिवहन कीमतें शामिल नहीं हैं, स्थानीय माल और सेवाओं के लिए और उन अन्य पात्र स्वीकृत देशों के उपादों के लिए वरीयता की गृजाहान देने के लिए जो गंट हैं। या जो हम प्रकार के वी स्वाभित फरना चाहते हैं उनके लिए अन्य पात्र स्वीकृत देशों में उत्पन्न होने वाले माल और सेवाओं के लिए प्राधिकृत हैं। वरीयता की यह गृजाहान अनुमत मूल्यांकित विवेशी बोली के साथ बीमाभाजा पर 15 प्रतिशत या बोलीकार के देश में सीमांतर्क करों के वर्तमान स्तर इनमें जो भी कम हो से अधिक नहीं होगे।

17. विशेष मामलों में, अग्री, नीदरलैण्ड्स सरकार और अग्री देश के बीच आपसी परामर्श, करके, कंडिका 16 में उल्लिखित वरीयता की गृजाहान के अतिरिक्त गॉट के अनुकूल स्थानीय और क्षेत्रीय विनियोगिकताओं के लिए वरीयता की सीमित गृजाहान को प्रदान कर सकता है। वरीयता के स्तर का निर्धारण करने समय राष्ट्रीय दर्जा या क्षेत्रीय स्वास्थ्य और प्रबंध और शेणी देश के पंजीकरण या इन विनियोगिकता एककों के अंतर्गत आर्थिक वर्ग जैसे तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

18. बोली दस्तावेज में कोई भी महमन वरीयताएँ प्रवर्णित की जाएंगी और बोली के मूल्यांकन और तुलना में जिस तरीके से उन्हें लागू किया जाएगा उसे भी बताया जाएगा।

19. बोलीकारों को पर्याप्त समय दिया जाएगा जिसमें वे अपनी बोलियों प्रस्तुत करें।

20. बोलियों को प्राप्त करने और बोली को खोलने के लिए अन्तिम तारीख समय और स्थान बोली के लिए विवेदकों में धोखित किया जाएगा और सभी बोलियों निर्धारित समय पर जनता के बामने बोली जाएंगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाली बोलियों को बिना खोले ही लौटा दिया जाएगा। बोलीकार का नाम प्रत्येक बोली या आवेदित या स्वीकृत यदि कार्ड विन्हारी बोली हो तो उनका कुर मूल ऊपर आवाज में पढ़ा जाएगा और उनका रिकार्ड रख लिया जाएगा।

21. किसी बोलीकार को बोलियों खुलने के बाद अपनी बोली में परिवर्तन करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। केवल बोली के मूल में परिवर्तन से विभ स्पष्टीकरण स्वीकृत किए जा सकते हैं। अग्री किसी भी बोलीकार को अपनी बोली में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है किन्तु किसी भी बोलीकार की बोली के मूल में या अपनी बोली के मूल में परिवर्तन के लिए नहीं कहेगा।

22. कानून द्वारा यथाप्रयोक्तिकों छोड़कर जांच से सम्बद्ध कोई भी सूचना, स्पष्टीकरण और बोली के मूल्यांकन तथा परिनिर्णय से नवां विफारित बोलियों के सार्वजनिक रूप से खुलने के बाद सफल बोली कार के लिए संविदा के परिनिर्णय को धोखित करने से पूर्व किसी भी उम व्यक्ति को नहीं भेजी जाएगी जो अग्री की ओर से या नीदरलैण्ड्स की सरकार की ओर से इन कियाविभिन्नों में आपचारिक रूप से संबद्ध नहीं है।

23. बोलियों के खुलने के बाद अरीदादार हम बात का सुनिश्चय करने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या बोलियों के परिकलन में सहाय्य गरिमा की गई है, क्या बोलियों/बोली दस्तावेज की आवश्यकताओं के पूर्णतः अनुकूल तो है, क्या अपेक्षित गारन्टीयों और जमानतों का व्यवस्था की गई है, क्या दस्तावेज सही रूप से हस्ताक्षरित कर दिया गए हैं और क्या दस्तावेज अन्यथा रूप से सही है? यदि कोई बोली वास्तविक रूप से विशिष्टिकरण के अनुकूल नहीं होती है या उसमें अस्वीकृत शर्तें हैं या अन्यथा रूप से वास्तव में बोली दस्तावेज के अनुकूल नहीं हैं तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। नव आर्थिक दृष्टि से विलूप्त निर्धारण के साथ तकनीकी विवेदण किया जाएगा जिससे प्रत्येक अनुकूल बोली का मूल्यांकन किया जा सके और बोलियों को मिलान के लिए समर्थ बनाया जा सके।

24. बोली के लिए निमंत्रण में बताया जाए कि अरीदादार को ऐसी सभी बोलियों को रद करने का प्रधिकार है जब कोई बोली विशिष्टिकरण के प्रयोजन के अनुकूल नहीं है और जब प्रतियोगिता के प्रभाव का प्रमाण मिलता है या निम्न बोलियों उस पूर्व अनुमति द्वारा राशि की कीमत से अधिक होती है तो इस तरह कोई कारेवाई को उचित बनाने के लिए पर्याप्त है। यदि सभी बोलियों रद कर दी जाती हैं तो अग्री नीदरलैण्ड्स सरकार के साथ परामर्श करने के बाबत ऐसी स्थितियों के कारणों से और निम्न बोली और अनुमानित कीमत में अंतर के कारणों से अग्री की संविदाएँ जिससे परियोजना की प्रनुभावित कीमत में कमी हो सकती है।

है उन्हें स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि परिवर्तन परियोग्यता के स्वरूप को वास्तविक रूप में नहीं बदलते। जहाँ परिवर्तन वास्तविक है वहाँ पुनः बोली उचित हो सकती है। इसे तब बार नीदरलैण्डस की वरकार द्वारा अनुमोदित करना होगा।

25. बोलियों के मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में बताए गए नियम और शर्तों के अनुसार और बोलियों को प्रनुसार करने को अनुत्तम तारीख से पूर्व इससे सम्बद्ध किसी भी आयोगीन के अनुसार हीने चाहिए। न्यूनतम मूल्यांकित बोली की स्पष्टी करने के प्रयोजनार्थ कीमत से मिल तथ्यों जैसे निर्माण कार्य या अन्य कार्य को पूरा करने के लिए समय उपकरण की कार्य-क्षमता और विषयमनीयता, इसकी मुपुर्दी को समय और सेवा और फालतू पुर्जों की उपलब्धता को भी ध्यान में लिया जाएगा और जहाँ तक संभव हो सकेगा मुद्रा में व्यक्त किया जाएगा वे मुद्रा जिनमें बोली कीमत का भुगतान किया जाएगा उनका मूल्यांकन बोली के मिलान के प्रयोजनार्थ सरकारी साधन द्वारा प्रकाशित मुद्रा की दरों के आधार पर और बोली की अनुत्तम तारीख को इस प्रकार के सौंदर्य के लिए लागू वरों के आधार पर किया जाएगा।

26. संविदा का परिनियंत्रण उस बोलीकार के लिए किया जाएगा जिसकी बोली पूर्व की कंडिकाओं में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मूल्यांकित बोली निर्विचित की गई हो।

27. अनुरोध करने पर नीदरलैण्डस की सरकार को अधिग्रापित के सभी पहलुओं पर अपनी और निकारिश प्रदान करने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा। संविदा का परिनियंत्रण होने के बाद नीदरलैण्डस की सरकार को अग्रण के उपयोग के मूल्यांकन के लिए सभी सम्बद्ध दस्तावेज और अन्य आवश्यक जानकारी (उनकी प्रतियों सहित) प्रदान की जाएगी।

(ग) औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली से भिन्न अधिग्रापित की क्रियाविधि

28. कंडिका 29 और 30 में उल्लिखित मामलों में कंडिका 31-39 में उल्लिखित अधिग्रापित के नियम कंडिका 6 के अनुसार लागू हो सकते हैं।

29. मानकीकरण :

जहाँ खरीदार के पास प्रपत्ते उपकरण के उचित मानकीकरण की बाताएँ रखने के लिए विषयस्थीत कारण हैं।

30. योग्य संभरकों को सीमित संख्या :

उन मामलों में जहाँ विषयाधीन अधिग्रापित की प्रकृति के कारण योग्य संभरकों की मंज्या सीमित है और खरीदार की माकिट जानकारी ऐसी है कि उससे आशा की जा सकती है कि योग्य संभरकों के बारे में जानें।

31. औपचारिक चुनिश्या अंतर्राष्ट्रीय बोली :

सामान्य चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय बोली के अंतर्गत खरीदार उन सीमित मंज्यों के पूर्ण योग्य संभरकों से बोलियों आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत हैं जो विषयाधीन अधिग्रापित की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य समझे जाते हैं।

ऐसे मामलों में अन्य को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किसी भी सम्भावित योग्य संभरक को छोड़ नहीं दिया गया है। जब और जैसे ही वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) भारत सरकार, से पाव स्नोत वेशों के सम्बन्धित संभरकों के बारे में जानकारी मार्गी जाएगी। सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी जिसमें कि वे उचित आधार पर भाग लेने में समर्थ हो सकें।

32. संभरकों का चुनाव केवल उनकी योग्यताओं के आधार पर किया जाता है और जहाँ तक समझ हो वे नीदरलैण्डस सहित अनेक पाव स्नोत वेशों से खुने जाते हैं।

33. कंडिका 8 में उल्लिखित से भिन्न औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय बोली की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से लागू की जानी हैं।

34. औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिग्रापित :

यदि औपचारिक प्रतियोगिता बोली की क्रियाविधियों के माध्यम से अधिग्रापित नहीं होती है तो वह संतोषजनक आणिंधिक नीति के अनुसार और पाव स्नोत वेशों के बीच बिना किसी भेद भाव के प्राप्त करनी चाहिए।

35. आयातक को अनोपचारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिग्रापित के इच्छित उपयोग का विस्तृत और समायोजित प्रचार करना चाहिए। पाव स्नोत वेशों के संभरक जब भी ऐसी सूचना मार्गे, तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार उनकी व्यायोचित आधार पर भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए सभी आवश्यक सूचना देंगी।

36. दरों और प्रस्तावों की तैयारी के लिए अनुभित समय शामिल की गई संविदाओं के स्वरूप द्वारा प्रतियोगिता की अनुभित देने के लिए समय और वितरण दोनों की अनुसूचियां पर्याप्त रूपी होंगी।

37. कुछ विशेष मामलों में नीदरलैण्डस सरकार मूल्य भाव के से प्राप्त किए गए थे इसके पूर्ण और महित विक्रय किए गए माल, शामिल किए गए संभरकों और प्राप्त मूल्य वरों के संबंध में विकेताओं से सूचनाएं मांग सकती है।

38. औपचारिक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय बोली के लिए पूर्ण संबंध सीमा तक व्यायोचित मार्ग-दर्शन लागू होना चाहिए।

39. एक माल संभरक :

निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में केता को किसी एक माल संभरक से सीधे ही क्रय करने की अनुमति भी जाती हैः—

- (1) एक वाणिज्यिक आयातक द्वारा यह अधिग्रापित जिसमें वह पंजीकृत व्यापार चिन्हित नाम वाली पर्याप्त वस्तु शामिल होती है जो आयातक द्वारा पुनः विक्री के लिए हो, जिसके लिए आयातक संभरक का नियमित प्राधिकृत वितरक या व्यापारी हो और जिसके लिए संभरक एकमात्र वितरक या विनियोगिता हो।
- (2) एक वाणिज्यिक आयातक द्वारा वह अधिग्रापित जिसमें वह पर्याप्त वस्तु शामिल है जो विनियोग संसाधन या संयोजन और उस अन्तिम उत्पाद के पुनः विक्रय के लिए अधिग्रापित की जाती है जिसके लिए आयातक संभरक का नियमित रूप से प्राधिकृत वितरक या व्यापारी हो और जिसके लिए संभरक एकमात्र वितरक या विनियोगिता हो।
- (3) पुर्जों की विनियोगशीलता का सुनिश्चय करने लिए या विशेष डिजाइन या तकनीकी आवश्यकताओं के कारण अधिग्रापित केवल एक ही स्नोत से पूर्ण की जा सकती है।
- (4) केता वह नियमित हो जिसका साझ-सामान और कच्ची सामग्री का फार्मूला कच्ची सामग्री की उस विशेष किस्म के जिस सबों-सम उपयोग के लिए बनाया गया हो जो केवल एक ही स्नोत से प्राप्त की जा सकती है।
- (5) यदि संभरक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय बोली के अधीन मूल रूप में प्राप्त की गई अधिग्रापित की बढ़ाना या बढ़ाना चाहता हो वहाँ तक कि सम्पूर्ण अधिग्रापित मूल अधिग्रापित के मुकाबले में छोटी हो, केवल कुछ ही असरवरों पर पूर्ण की जाती हो और जब मूल अधिग्रापित से संबंधित नियमण कार्य उस समय भी बदल रहे हों या मूल अधिग्रापित पूर्ण करने के घोड़े ही समय बाव पूर्ण की जाती हो।

(6) यदि सौदे का मूल्य रु० एक० एवं १.२५ मिलियन से कम हो।

४. परामर्शकों के उपयोग के लिए मार्ग-वर्णन

40. परामर्श बेने वालों नियोजित संस्थाएँ इस उद्देश्य के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए कि उनका परामर्श डिजाइन, विशिष्टिकरण और उनके द्वारा तैयार किए गए बोली के दस्तावेज राष्ट्रीय वाणिज्यक या आधिकारिक पक्षपात्र से मुक्त हों और वे प्रतियोगिता के आधार का आंतुपात्र कर सकती हों। स्वानीय परामर्शदाती संस्था पर विचार करने समय राष्ट्रीय स्वामित्व का स्तर प्रबंध और कार्यक्रम तथा पंजीकरण जैसी बातों पर उचित ध्यान देना चाहिए।

41. परामर्शदाती संस्थाओं के चयन के लिए आधिकारिक प्रतियोगिता बोनी क्रियाविधियों की प्रावश्यकता नहीं है। लेकिन, चयन की प्रक्रिया में अपीलों को उन प्रत्याशित संस्थाओं की वयोंचित संख्या पर विचार करना चाहिए जिनसे कई पात्र स्वीकृति में मर्मांश और स्वतंत्र सेवाएँ प्राप्ति करने की आशा की जा सकती हो। यह सूची निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्वनुग्रह पर आधारित होगी—

1. कार्य की समान किसीमें संस्था का पहला अनुभव,
2. कर्मचारियों, साज-समान और संयंत्र के संबंध में इस संस्था की अपेक्षा
3. इसकी वित्तीय स्थिति और सबलता

यह बांछनीय है कि प्रस्तावों के लिए निमंत्रण भेजने से पहले अपील प्रत्याशित संस्थाओं की सूची नीदरलैंड्स सरकार को प्रस्तुत करे। नीदरलैंड्स सरकार को परामर्शी के चयन को अस्वीकार करने का अधिकार है। इसके प्रतिक्रिया वह नीदरलैंड्स में परामर्शदाती क्षेत्र में अपनी जानकारी के आधार पर यह मुझाव दे सकती है कि इस सूची में वृद्धि की जाती है।

उ. शिक्षायात्रे

42. खरीदार बोली के संबंध में बोलियों को प्रस्तुत करने और संविधानों के प्रदान करने के संबंध में उपलब्ध होने वाली शिक्षायात्रों को सुनने और उनकी जांच करने की व्यवस्था करेगा।

43. आधिकारिक बोली क्रियाविधि के अंतर्गत की गई खरीद के मामले में बोली समाप्त होने की तिथि से पूर्व किए गए प्रतिबंध पर्यवस्तु विशिष्टिकरण या आमदान की प्रतिबंध प्रवधि के संबंध में विषयवस्तु की किसी भी शिक्षायत का समाधान बोलियों के छुलने से पूर्व ही किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो नीदरलैंड्स सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ही उचित अवधि के लिए बोली के लिए अन्तिम तिथि स्थिति की जाए।

44. जब शिक्षायत संबंध संभरकों में से किसी एक के द्वारा की गई है तो शिक्षायत के विषय से संबंधित और इस पर की गई कार्रवाई में संबंधित दस्तावेज नीदरलैंड्स सरकार द्वारा और अपीली द्वारा जांच के लिए उपलब्ध होंगे।

परिचालक 'क'

विकासशील देशों की संयुक्त विपक्षीय छूट के लिए पात्र घोषित देशों की सूची

क. नीदरलैंड्स :

विकासशील साहाय्य

ख. अफ्रीका :

उत्तरी साहाय्य

प्रलंगीरिया

सीविया अरब गणराज्य

मोरक्को

तूनीसिया

सिस्त्र

विकासशील साहाय्य

बोल्टस्वाना

बुर्झिंड

केमीरन

केप ब्रिटीश ब्रिटिश समूह

मध्य अफ्रीका गणराज्य

चाइ

कोमोरो ब्रिटिश

कानोगो (जनवादी गणतन्त्र)	त्रिमीवाद एट टोबागो
जैरी गणराज्य	बेल इंडीज (आ)
वहोमी	विक्षिप्त
इथोपिया	अर्जेन्टीना
गेरेन	ओनीविया
गैनिया	ब्राजील
घाना	चिली
गिनी	कोलम्बिया
गिनी बिसाऊ	इक्वादोर
ग्राइबेरी कोल्ट	फालैंक ब्रिटिश समूह
कीनिया	गुयाना
लिथोथो	गिनी (फ)
लाइबेरिया	पराग्वे
मालागासी गणराज्य	पीर
मलाक्की	सुरीनाम
माली	युक्सेन्ड्रे
मरिलेनिया	ब्रेज़ीलेना
मॉरिशस	एशिया मध्य पूर्वी
नाइजीर	बेह्रीन
माइजेरिया	ईरान
रियूनियन	ईराक
रुग्रान्डा	इजराइल
सैनेगाल	जोर्जिन
सिच्लाइज	कुबैत
सियारा लिङ्गोन	मेक्सिनान
सीमालिया	ओमन
टर फार और इमाम	करतार
सेट ड्रेनेन और डिपेंडेंसीज	सऊदी अरब
सूडान	यमन (जनवादी ग्राजातन्त्र गणराज्य)
स्वाजीनैड	सीरिया (प्ररब गणराज्य)
तन्जानिया	यूनिट अरब अमीरात
टोगो	यमन (प्ररब गणराज्य)
उगान्डा	विक्स एशिया
अपर बोलाटा	अफगानिस्तान
जामिया	बंगला देश
अमेरिका उत्तरी एवं मध्य	भूटान
बहूग	वर्मा
बारबेंड्स	भारत
बरम्डा	मालदिव
कोस्टारिका	नेपाल
क्युआ	पाकिस्तान
डामिनियन गणराज्य	श्री लंका
ई-१ सल्लोडोर	सुडर पूर्व
गुडेलोप	ब्रुनी
ग्वाटेमाला	खेमर गणराज्य
हेती	हांग कांग
होन्दुराज (ज)	इन्डोनेशिया
होन्डरस (ज)	कोरिया (गणराज्य)
जमेका	कोरिया (जनवादी ग्राजातन्त्र गणराज्य)
मार्टिनिक	लाओस
मेकिस्को	मेको
नीदरलैंड्स अन्टलीज	मालेशिया
निकारागुआ	फिलीपिन्स
पनामा	सिंगापुर
सेंट ऐरी मिक्युलोन	याइलैण्ड

तिमोर	प्रेसेफिक द्वीप समूह (या. एस)
वियतनाम (गणराज्य)	पापूआ न्यू गिनी
वियतनाम (प्रजातन्त्र गणराज्य)	सोलोमन द्वीप समूह
सामुद्रिक	टोंगा
फिजी	बालिज और फुतुना
गिलबर्ट एवं एलिस द्वीप समूह	पश्चिमी सामोआ
फेन्न औलिनेशिया	यूरोप
स्थू केलैडोनिया	टर्की
न्यू हैंबराइंड ज (ब्र एव फ)	पूर्तीगाल

परिचय 'ब'

उद्गम के नियम

1. उद्गम के इन नियमों की विषयाधीन महें पात्र स्वीकृत देशों में उत्पादित माल और सेवाएं होंगी।
2. माल के मामले में नीदरलैंड्स से उद्गम का निर्धारण इस क्षेत्र में उत्पादित विधान के अधीन होगा जोकि यूरोपीय समुदाय में लागू है।
3. पैरा 2 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण नीदरलैंड्स के वाणिज्य मंडल द्वारा जारी किए गए उद्गम के प्रमाणपत्र के साथ भेजा जाएगा :
4. माल के मामले में, विकासशील देशों के उद्गम का निर्धारण उद्गम नियम के अधीन होगा जो अधिमान्यता सामान्य प्रणाली की रूपरेखा में यूरोपीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई हो।
5. पैरा 4 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण विकासशील देशों के प्रशासकीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रपत्र ए (जो अधिमान्यता की सामान्य प्रणाली के उपयोग में लाया जाता है) उद्गम के प्रमाण-पत्र द्वारा भेजा जाएगा ।
6. सेवाओं के मामले में (प्रथम, मार्ग दर्शन का पैरा 1) उद्गम का निर्धारण नीदरलैंड सरकार और अृण लेने वाले देशों के बीच आपसी परामर्श से तदर्थे आधार पर किया जाएगा ।
7. ऐसे मामलों में जहां उद्गम के नियमों से वास्तव में कोई समस्या पैदा हो जाती है या अृण लेने वाले देश को गम्भीर आर्थिक घाटा हो जाता है (उदाहरणार्थ बहुत से सम्भावों सम्भरणों पर जबर्दस्त प्रतिबंध) तो इन नियमों से छुकारा पाने की स्वीकृति दी जा सकती है किन्तु वह केवल नीदरलैंड सरकार एवं अृण लेने वाले देश के बीच आपसी परामर्श के बावधी जा सकती है ।

अनुबन्ध 2

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता और / या जहां आवश्यक हो परियोजना अधिकारी का नाम व पता ।
- (ख) संभरक का नाम और पता । यदि संभरक पात्र स्वीकृत देश के हैं तो उस मामले में निम्नलिखित सूचनाएं भी भेजी जानी चाहिए
- (1) राष्ट्रिकता
 - (2) पात्र स्वीकृत देशों के द्वारा रखे गए शेयरों का प्रतिशत ।

- (ग) (1) आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक
(2) मूल्य
- (घ) (1) नीदरलैंड/पात्र स्वीकृत देश में संभरक के बैंक का नाम और पता

* (2) भारत में आयातक का बैंक यह वीं बैंक होगा जिसने बैंक गारंटी दी है ।

** (3) भारत में आयातक का बैंक जो कि आयातक के लिए पोतलदान वस्तावेज रिहा करने के पहले भारत के सेवों में हु जमा करने के लिए उत्तरवायी होगा ।

(ङ) उच्च गिल्डरस में या पात्र स्वीकृत देश की मुद्रा में संविदा आदेश का मूल्य

(च) अधिग्रन्ति की विधि क्या यह सीधे बारीव पर आधारित है या आप-चार्टिक खुले अतर्वादीय बोर्डी पर या चयन फार्मला अतर्वादीय बोर्डी के आधार पर, जिस मामले में यह संकेत किया जाना चाहिए कि क्या संविदा यदि कोई हो तो उन कारणों के साथ न्यूनतम तकनीकी उपयुक्त प्रस्ताव के आधार पर की गई है ।

(छ) आयात किये जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण

(ज) माल का उद्गम-यदि कोई हो तो वैर पात्र स्वीकृत देशों से आयातित संधटकों का प्रतिशत

(झ) सुपुर्वगी को पूरा करने की संभावित तिथि

(ञ) भुगतान की शर्तें और संभावित वह तिथि जिस दिन इस संविदा के अंतर्गत भुगतान के लिए पड़ेगी ।

(ट) पोतलदान दस्तावेजों की विस्तृत सूची जैसे प्रवरतण बिल, बीजक, उद्गम प्रमाणपत्र प्रावि जिसे विकास शील देशों के लिये नीदरलैंड पूंजी निवेश बैंक या पात्र स्वीकृत देश में संभरकों के बैंक को चाहिए कि संभरकों को भुगतान करने से पहले अपेक्षित प्रत्येक वस्तावेज की प्रतियों के साथ मांग करें ।

(ठ) यदि संविदा में शामिल हैं तो भारतीय एजेंट का वह कमीशन (ठीक-ठीक धनराशि संकेतित की जानी है) जिसे प्रधिकारी पत्र जारी करने समय संविदा के मूल्य में से घटाना पड़ेगा । इस प्रकार का कमीशन का भुगतान भारतीय एजेंटों को रूपये में आयातकों द्वारा सीधे ही किया जायेगा ।

(ड) वह मूल्य जिसके लिये प्राधिकार पत्र अपेक्षित है ।

(इ) बैंक गारंटी की संख्या, दिनांक और मूल्य इस में उस संविधि का भी संकेत हो जिस तक वह बंधे हैं ।

(ण) यदि कोई हो तो किसेव अनुवेश ।

*निजी शेव के लिए

**सार्वजनिक शेव के लिए

अनुबन्ध 3

संविदा प्रमाणपत्र संविदा के व्यापे

भारतीय आयात लाइसेंस की संख्या.....

1. संविदा की संख्या और दिनांक.....

2. बारीवदार.....को संभारित किए जाने वाले माल एवं सेवाओं के व्यापे.....

(यदि बहुत सी मर्दों का संभरण किया जाता है प्रमाणपत्र में विस्तृत सूची लगाई जानी चाहिए)

उद्देश्यपत्र को चुकाई जाने विषय कुल संविदा कीभत (लागत-बीमा-भाड़ा, लागत एवं भाड़ा या जहाज पर निःशुल्क का संकेत कीजिए) भी एफ आई..... खदि माल का संभरण किया जाना है तो निम्नलिखित खण्डों की पूर्ति अवश्य की जानी चाहिए ।

4. नीदरलैण्डस में उत्पन्न नहीं किए गए माल का जहाज पर निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत कित्तु वह उस माल की खरीद से संभरक द्वारा सीधे ही विदेशों से की गई है अर्थात् विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित सामग्री या संघटकों का प्रतिशत ।

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य

(ख) मर्दों का विवरण एवं संक्षिप्त विशिष्टिकरण

5. यदि सेवाओं का संभरण किया जाना है तो निम्नलिखित खण्ड की भी पूर्ति की जानी चाहिए ।

6. किए जाने वाले किसी काम का अनुमानित मूल्य या

(क) आपकी फर्म (साइट इन्जीनियर भार आदि)

(ख) स्थानीय संभारक

द्वारा खरीदार के देश में निष्पादित की गई सेवा का उल्लेख कीजिए ।

7. उपर्युक्त कंडिका 4 और 5 के सम्बन्ध में क्या आवश्यक अर्हक टिप्पणियां

8. मैं घोषणा करता हूं कि संभरक द्वारा या नीचे उल्लिखित द्वारा नीदरलैण्डस में नियुक्त किया गया हूं और इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने का पुनर्व्यवधिकार है । एतद द्वारा बचत देता हूं कि उपर्युक्त कंडिका 4 और 5 में उल्लिखित माल एवं सेवाओं से भिन्न और किसी भी ऐसे माल या सेवा का इस संविदा के निष्पादन में संभरक द्वारा नहीं किया जाएगा जो नीदरलैण्डस मूल के नहीं है ।

हस्ताक्षरित

ओहदा

संभरक का नाम और पता

.....

दिनांक

नीदरलैण्डस वाणिज्यिक मंडल

प्रमाणित

अनुबंध-4

गारन्टी बॉड

(इच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अंतर्गत माल के आयात से संबंधित प्रक्रिया के अंतर्गत बैंकों द्वारा भेजा जाना है)

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति के बदले (इसके बाद इसे "सरकार" कहा गया) इच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अंतर्गत जारी की गई शर्तों के अनुसार तथा ऊपर उल्लिखित करार के मद्दे आयातक के नाम में आयात के अनुमरण में दिनांक को जारी किया गया लाइसेंस सं० का पालन करते हुए

के द्वारा (बाद में इसे "आयातक" कहा गया) के आयात के लिए इच गिल्डर में भुगतान के लिए राजी होते हुए आयातक के अनुरोध पर हम

(बैंक) विकासशाल देशों के लिए नीदरलैण्ड इन्वेस्टमेंट बैंक, दि हेग द्वारा भुगतान की गई धनराशि को जमा करने के लिए परिवर्तन की चाल परिवर्तित दर पर जो इस मंवंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना के अनुसार परिक्रित किया जाता है, इच संभरकों को किए गए भुगतान की नारीख को सरकारी नेखे में क्रेडिट के लिए समतुल्य रूपए

के भुगतान का तारीख तक पहले 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर पर और उसमें अधिक अवधि के लिए 15% वार्षिक दर पर [जैसा कि सार्वजनिक सूचना 46-आईटीसी (पी एन)/76 दिनांक 16-6-76 में निर्धारित है] गणना किए गए व्याज के साथ भुगतान के परामर्श की पावरी की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर विधि के साथ भारत सरकार को क्रेडिट के लिए और उस क्रेडिट के अंतर्गत उपयुक्त नेखा शीर्ष के लिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा नेखा शीर्ष के विपरीत सकेतिक है, व्यवस्था करने का भार नेत्रे हैं, विकासशाल देशों के लिए नीदरलैण्ड इन्वेस्टमेंट बैंक, दि हेग द्वारा प्राप्त आयात प्रलेखों का परकार्य सेट आयातक को केवल तभी लौटाया जाएगा जबकि ऊपर के अपेक्षित जमा रूपये पूरे कर लिए गए हों ।

2. हम दि..... (बैंक) सरकार जहां और जैसा भी, समय समय पर निदेश में, आयातक द्वारा समय समय पर सरकार को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की राशि चाहे वह बकाया हो या भुगतान करने योग्य या उस पर कोई भी अंश जो आयातक द्वारा थोड़े समय के लिए बकाया और देय रह गया है, जिसमें संभरकों को भुगतान करने की तारीख से पहले 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर (देवें पूर्वोक्त मार्वजनिक सूचना)..... गणना किया हुआ, व्याज भी आमिल है, ऐसे राशि जोरु.) से अधिक नहीं है, आयातकों द्वारा भुगतान करने में देर होगी, तो उसको भी क्षति से सरकार को दूर रखेंगे और उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे । आयातक द्वारा उल्लिखित भुगतान करने में किसी प्रकार की देर होते पर अथवा उसकी ओर से और सरकार को भुगतान किए जाने योग्य राशि के मंवंध में जो राशि हमारे..... (बैंकों) द्वारा दी जानी है, उस संबंध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय हमारे ऊपर (बैंक), अंतिम और अनिवार्य होगा ।

3. हम..... (बैंक) आगे इस बात पर सहमत है कि संविदा के अंतर्गत मिली जली दर में परिवर्तन होने पर आयात के मूल्य में वृद्धि होने से या अधूरे माल छुड़ाने की स्थिति में उसके मूल्य में वृद्धि होने की स्थिति में जैसा कि उपर्युक्त कंडिका] में बताया गया है, जब से परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के अनुपात में बैंक गारन्टी बॉड की धनराशि को समयोजित कर लिया जाएगा ।

4. हम..... (बैंक) आगे इस बात पर सहमत है कि इम गारन्टी में जो कुछ दिया गया है, वे उल्लिखित करार/संविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होगा और उसे नव तक कार्यान्वयन रखा जाएगा जब तक सरकार के अंतर्गत या इस गारंटी में आगे वाला सारा वकाया पूर्णरूपेण चुकता न कर दिया गया हो और इसकी नारी मांगे पूरी न हो गई हों या उन्मुक्त न हो गई हो ।

5. इसमें उल्लिखित गारंटी पर आयातक या दिन..... (बैंक) के संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारंटी प्रमाणित किए विना आयातक और दि..... (बैंक) पर लागू होने योग्य किसी भी शक्ति को किसी समय या समय-समय पर के लिए स्थगित करे । उपर्युक्त मामले के संदर्भ में या किसी कारणवश थोड़े समय के लिये आयात को या किसी अन्य स्थान जो दिया गया हो, इस गारन्टी के अंतर्गत सरकार द्वारा किसी प्रकार की स्वतंत्रता बरती जाने पर यह अपनी जिम्मेदारी के उन्मुक्त नहीं होगी, लेकिन इस व्यवस्था के लिए नियम या सरकार की ओर से दी गई छूट या आयातक पर दिए गए किसी तरह का अनुग्रह हो या और कोई मालाला या बात चाहे जो भी हो, जो जमानतों से संबंधित हो..... (बैंक) पर इस प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए ऊपर कथित उन्मुक्त का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

6. मन्त्र में हम..... (बैंक) यह भार नेते हैं कि सरकार द्वारा लिखित रूप में परामर्श पाए विना मार्काकाल में इसकी गारन्टी को रद नहीं करेंगे ।

7. हम (बैंक) सार्वजनिक सूचना सं० 15-आईटीसी (पीएन)/72 दिनांक 28-1-1972 तथा सार्वजनिक सूचना सं० 108 आईटीसी(पीएन)/72, दिनांक 21 जुलाई, 1972 तथा इसके बाद समय समय पर जारी की जाने वाली ऐसी ही सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार अतिरिक्त निशेप करने का भी वचन देते हैं।

8. उस गारंटी के अंतर्गत रुपए (इसमें व्याज तथा अन्य प्रभार भी शामिल है, इसे गारंटी की धनराशि के 1% से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं की जाती) तक सीमित रखने की हमारी जिम्मेदारी है और यह गारंटी दिन मास 19 तक लागू रखी जाएगी। जब तक इस गारंटी के अंतर्गत 6 मास के भीतर लिखित रूप में मार्गे पूरी नहीं कर ली जाती, और जब तक उसके बाद तक दूसरे 6 मास के भीतर जो तक होगी और उनकी मार्गों के लिए मुकदमा या कार्यवाही लागू न हो जाए, इस गारंटी के अंतर्गत सरकार के सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे और हम लोग इसके अन्दर निहित सारी जिम्मेदारियों से मुक्त और उन्मुक्त कर दिए जाएंगे।

..... दिन या दिनांक
वाले (बैंक)

श्री (नाम और ओहदा) के द्वारा
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत
हस्ताक्षर

यह तारीख उस तारीख में एक मास और जोड़ कर गिनी जाएगी जिस तारीख तक संभरकों को सभी भुगतान पूरे कर देने की संभावना है।

टिप्पणी:— स्टाम्प पेपर का मूल्य जिसमें यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर न्याय निर्णित किया जाना है।

अनुबंध—5

संख्या एफ/4 () डब्ल्यू ई-3/7

चित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली,

दिनांक

सेवा में,

विकासशील देशों के लिए दि नीदरलैंडस इन्वेस्टमेंट बैंक,
दि हैग,
नीदरलैंडस
..... लाख नीदरलैंडस गिर्डर्स के क्रूण के
लिए समझौता,
प्रिय महोदयगण,

प्राधिकारपत्र सं०
भारत को आपके बैंक द्वारा दिए गए क्रूण में से भारत के सर्वश्री और हालैंड के सर्वश्री
के बीच वित्त युक्त किए जाने वाले सौदे के संबंध में अपने आज के आवेदनपत्र के प्रसंगत में हम एत द्वारा निवेदन करते हैं और उपर्युक्त संविदा की शर्तों के अनुसार
एन०एफ०एल० (डच गिल्डर) मात्र की धनराशि हालैंड में संभरक को चुकाने के लिए आपको बिना शर्त और बिना परिवर्तन के प्राधिकृत करते हैं। यह निवेदन किया जाता है कि डच संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए बाज, पोतलदान और अन्य दस्तावेज को सीधे भेज दिए जाएं।

(आयातक के बैंक)

संभरकों को विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड पूंजी निवेश बैंक को उस जिने के जिसमें निर्यातिक स्थित है, नीदरलैंड व्यापार मंडल द्वारा जारी किए गए/प्रमाणित किए गए प्रमाणपत्र की इस संबंध में दो प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक है/है कि प्राधिकारपत्र के अंतर्गत आने वाले माल नीदरलैंड मूल के हैं।

कृपया नामे डालने की सूचना भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (आर्थिक सहयोग लेखा शाखा) जीवनदीप विलिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को अग्रसारित करें। यह प्राधिकारपत्र तक वैध होगा।

कृते भारत का राष्ट्रपति
()

प्रतिलिपि (आयातक के बैंक को)

उन्हें केवल यह सुनिश्चय करने के पश्चात ही आयातक को दस्तावेजों का अप्रकार्य सेट रिहा करना चाहिए कि आयातक ने निम्नलिखित धनराशि जमा कर दी है:—

(1) मुख्य नियन्त्रक, आयात-नियर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-1976 में यहां निर्धारित और सरकार द्वारा समय समय पर मुख्य नियन्त्रक, आयात-नियर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से अधिसूचित तरीके से गणना की जाने वाली विनियम की चालू मिश्रित दर पर डच गिल्डर में संभरक को समतुल्य रूपए का भुगतान;

(2) उपर्युक्त मद (1) द्वारा द्वारा की जाने वाली अपेक्षित धनराशि पर सार्वजनिक सूचना सं० 46-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 16-6-1976 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9% की दर पर और 30 दिनों से अधिक होने पर 15% की दर पर गणना किया हुआ व्याज, जिसकी गणना विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड इन्वेस्टमेंट बैंक, एन०वी० दि हैग द्वारा संभरक को वास्तविक भुगतान की तिथि से भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली या भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में आयातक द्वारा समतुल्य रूपए के वास्तविक भुगतान की तिथि तक की जाएगी।

अनुबंध—6

संख्या-एफ-4 () डब्ल्यू ई-3/

वाणिज्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली]

विषय:—सामान्य प्रयोजन डच क्रेडिट के अन्तर्गत की गई संविदा प्रतिपूर्ति

प्रिय महोदय,

सर्वश्री

..... ने
(भारतीय आयातक)

रुपए) रुपए) के मूल्य के लिए सामान्य प्रयोजन डच

क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंस संख्या
दिनांक के मद्दे लागत बीमा-भाड़ा/लागत

एवं भाड़ की
 (.....) धनराशि के लिए
 के संभरण के लिए सर्वश्री
 (विदेशी मंभरक)

के साथ संविदा की है। संविदा की एक प्रति संलग्न है।

2. ऊपर के रुपए की धनराशि में से भारतीय एजेंट के कमीशन के रूप में धनराशि भारतीय मुद्रा में प्रदा की जानी है। विदेशी मुद्रा में संभरक को प्रदा की जाने वाली धनराशि प्रथमतः मुक्त विदेशी मुद्रा खोतों में से प्रध्युम्न की जाएगी जिसकी बाद में धनराशि तक इच्छा सामान्य प्रयोजन क्रेडिट में से प्रति पूर्ति की जानी है।

2. आपको उनके बैंकरों प्रथात् सर्वश्री

के माध्यम से सर्वश्री के नाम में इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिनों की प्रबलिक के भीतर और वैष्णवी आयात लाइसेंस के मद्दे, सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक, यू०सी०ओ० बैंक विलिंग, पार्लियार्मेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचना देते हुए एक साझा-पत्र खोलने के लिए प्राप्तिकृत किया जाता है।

4. मुद्रा विनियम नियंत्रण भैन्नमल के खण्ड 7 पैरा 10 के अनुसार आपको यह सुनिश्चय कर लेता चाहिए कि साझा-पत्र की समाप्ति तिथि सम्पन्नित आयात लाइसेंस में यथा उल्लिखित पोत लदान के लिए अन्तिम तिथि के बीचारी (45) दिनों से ज्यादा नहीं है।

5. साझा-पत्र में यह भी प्राप्तिकृत होगा कि सर्वश्री

(विदेशी *संभरक)

अपरकाम्य पोतलदान वस्तावेजों का एक सेट और बीजक की दो प्रतियाँ जो इच्छा संभरक द्वारा इस प्रमाण पत्र पर द्वारा पूछाकित हो कि भूगतान उनके द्वारा प्राप्त ही गया है, तीसे ही सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक, विस्त मंत्रालय आधिकार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक विलिंग, संसद् मार्ग, नई दिल्ली को भेजेगा।

जिस जिला में नियंत्रक है उस जिले के नीवरलैंड्स व्यापार मण्डल से साझा-पत्र के अन्तर्गत आने वाले माल के नीवरलैंड्स मूल के होने के संबंध में जारी किए गए/प्राप्तिकृत किए गए इस साझा-पत्र* के अन्तर्गत आने वाले माल उद्यगम के संबंध में उल्लिखित समर्थ प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र की दो प्रतियाँ भी वे प्राप्त करेंगे और नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करेंगे।

6. आपको, यदि कोई हो तो बैंक खाचों को छोड़कर बीजक/माल के पोतलदान के मद्दे आपके द्वारा सर्वश्री को किए गए प्रेषण का एक प्रमाणपत्र भी सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक, विस्त मंत्रालय, आधिकार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक विलिंग, संसद् मार्ग, नई दिल्ली को भेजना होगा।

7. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

() ()

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

संविदा की प्रति के साथ प्रति इनको प्रेषित :—

भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा विनियम नियंत्रण विभाग, बम्बई-1

2. प्रति सम्भरकित को भी सूचनार्थ प्रेषित :—

(1)
 (भारतीय आयातक)
 यह सुनिश्चय कर लिया जाए कि सर्वश्री
 (विदेशी बैंकर)

ने नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, विस्त मंत्रालय, आधिकार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक विलिंग, संसद् मार्ग, नई दिल्ली को भूगतान बीजक सहित पोतलदान और अन्य वस्तावेजों (अप्रकाम्य) का एक सेट बीजक की दो प्रतियाँ जिस पर सम्भरक द्वारा यह प्रमाणपत्र विद्यित पूछाकित हो कि उसके द्वारा भूगतान प्राप्त ही गया है और माल के उद्यगम के बारे में प्रमाणपत्र की दो प्रतियाँ नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, विस्त मंत्रालय, आधिकार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक विलिंग, संसद् मार्ग, नई दिल्ली को भेज दी जाए।

(2) सर्वश्री
 (विदेशी बैंक)

आप से यह अनुरोध है कि प्रत्येक आयाती पर भूगतान बीजक सहित पोतलदान और अन्य वस्तावेजों (अप्रकाम्य) का एक सेट बीजक की दो प्रतियाँ जिस पर सम्भरक द्वारा यह प्रमाणपत्र विद्यित पूछाकित हो कि उस के द्वारा भूगतान प्राप्त ही गया है और माल के उद्यगम के बारे में प्रमाणपत्र की दो प्रतियाँ नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, विस्त मंत्रालय, आधिकार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक विलिंग, संसद् मार्ग, नई दिल्ली को भेज दी जाए।

(3) नियंत्रक, सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा विस्त मंत्रालय, आधिकार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक विलिंग, संसद् मार्ग, नई दिल्ली।

प्रनुबन्ध—7

इच्छा (सामान्य उद्योग) क्रेडिट के अन्तर्गत उपयोग के संबंध में बैमासिक रिपोर्ट को प्रदर्शित करने वाला विवरण

1. आयातक का नाम
2. आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक
3. आयात लाइसेंस का मूल्य
4. इच्छा गए आदेश का मूल्य
5. प्राधिकारात्मक की संख्या और दिनांक
6. प्राधिकार पत्र की धनराशि
7. प्राधिकार पत्र की वैधता तारीख
8. बैमासिक के दौरान उपयोग की गई धनराशि इच्छा गिल्डर
9. उपयोग की गई कुल धनराशि इच्छा गिल्डर
10. सरकारी आते में जमा की गई कुल धनराशि रुपए
11. आगामी बैमासिकों के दौरान किया जाने वाला भूगतान
12. अध्यर्थण, यदि कोई हो

का० अ० शेषाद्रि, मुक्त नियंत्रक, आयात नियंत्रित

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 17—ITC(PN)/79

New Delhi, the 9th March, 1979

Subject : Terms and conditions for licensing of private sector and public sector imports under the Dutch General Purpose Credit for 1978-79.

File No. IPC/39/13/76.—The terms and conditions governing the issuance of import licences financed under the Dutch General Purpose Credits for 1978-79 as given in Appendices I & II to this Public Notice are notified for information.

Appendix I to Department of Commerce Public Notice No. 17—ITC(PN)/79 dated 9-3-1979

CONDITIONS FOR LICENSING PUBLIC SECTOR IMPORTS UNDER THE DUTCH GENERAL PURPOSE CREDIT.

Section I—General :

I(1) The Dutch General Purpose Credit for 1978-79 extended by the Nederlandse Investeringbank Voor ontwikkelingslanden N. V. is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and commodities and services incidental thereto which are to be financed under the Credit can be imported from Netherlands and all countries enumerated in the list at Appendix-A of the "Guidelines for Procurement of Goods and Services under Bilateral Development Loans by the Netherlands" (Annex. I) which will be the "eligible source countries" under the credit. The terminal date of disbursements in respect of the credit would be 31-12-1981.

I(2) Components to the extent of 10 per cent in respect of chemicals and 20 per cent in respect of other imports from non-eligible source countries can, however, be considered for being financed under the Credit.

I(3) Limited supplies of goods and services from non-eligible source countries to supplement the supplies from eligible source countries in excess of the limit indicated in Section I(2) may also be considered for financing under the credit. For this, specific approval of the Government of Netherlands will be necessary.

Section II—Issue of Import Licence :

II(1) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the Licensee should approach the licensing authority concerned, within the validity period of the licence, who shall consult the Department of Economic Affairs, (W.E.III Section) in the matter.

II(2) Firm order on CIF/C&F basis must be placed on the overseas suppliers in the Netherlands or the countries mentioned in the Annex. I and sent to the Department of Economic Affairs (W.E.III Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. If firm orders cannot be finalised within the time limit of 4 months the licensee should submit to the Chief Controller of Imports and Exports or other licensing authorities, as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period, furnishing justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such requests for extension in the ordering period will be considered on the merits of each case by the licensing authorities who may grant extension upto a further period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of import licence, such proposal should invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs, (W.E. III Section), Ministry of Finance.

II(3) The licence will bear the superscription 'Dutch General Purpose Credit' and indicate the Public Notice number under which here licensing conditions are issued. The licence code for the first and second suffix will be "S"/"N.N". This licence code will be mentioned in all the shipping documents as well as in the "S" form required to be furnished to the Reserve Bank at the time of rupee deposit.

II(4) As soon as the importer receives the import licence, he should send a report to that effect to the Ministry of

Finance, Department of Economic Affairs, (W.E.III Section) along with the following information :—

- (i) No. and Date of Imports Licence ;
- (ii) Value ;
- (iii) Exchange rate if any, indicated on Import Licence ;
- (iv) Date by which copies of contract are expected to be furnished to Department of Economic Affairs.

Section III—Finalisation of Contract :

III(1) The minimum value of contract eligible for financing under the credit is D.Fl. 25,000.

III(2) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract will be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

III(3) The contract for the import of goods and services from the Netherlands and eligible source countries should be finalised keeping in view the Guidelines for (Procurement of Goods and Services, as detailed in Annex. I).

III(4) Goods and services should be procured through Formal Open International Bidding except in the following cases :—

- (a) where the Netherlands is the traditional or the only source for imports ; or
- (b) where the value of imports is less than DFl. 1.25 million; or
- (c) where such a procedure is inapplicable or inappropriate. In this case, agreement between the Netherlands Government and the Government of India on another more expedient procedure must be reached before the contract for the supplies could be finalised.

III(5) It would also not be necessary to resort to Formal Open International Bidding in the following types of cases :—

- (a) where the purchaser has convincing reasons for maintaining a reasonable standardisation of his equipment.
- (b) in cases where, because of the nature of the procurement in question, the number of qualified suppliers is limited and the market knowledge of the purchaser is such that he can be expected to know the qualified suppliers.
- (c) where in the light of the existing relationship subsisting between the Indian importers and the foreign suppliers and the scope of supplies available and identified in the Netherlands and/or the developing countries, the borrower considers that imports should be effected from the Netherlands only.

In such cases the procurement formula of paragraphs 31 to 39 of the Guidelines for procurement of goods and services (Annex. I) may be followed.

III(6) The purchaser may purchase directly from a single supplier in one of the following cases :

- (i) procurement by a commercial importer involves a registered brand name commodity which is for resale by the importer, for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the sole distributor or manufacturer ;
- (ii) procurement by a commercial importer involves a commodity which is procured for manufacture, processing or assembly and resale of the end product

- for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the manufacturer ;
- (iii) in order to assure interchangeability of parts or because of special design or technical requirements the procurement can only be made from one source ;
 - (iv) the importer is a manufacturer whose equipment and raw material formulae are designed for best utilisation with a specific type of raw material which can only be obtained from one source ;
 - (v) the importer wishes to extend or repeat a procurement originally made under formal international bidding provided that the complementary procurement is small in relation to the original procurement, takes place on a few occasions only and while the construction work related to the original procurement is still under way or shortly after the original procurement is made ;
 - (vi) the value of a transaction is less than Dfl. 1.25 million.

III(7) Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consultant firms. However before invitations for proposals are sent out by the Indian firms to the consultant firms, a list of such prospective firms should be furnished to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section). The list in turn will be submitted to the Government of Netherlands who may approve the same or reject the choice of a consultant and may on the basis of their knowledge of the consultancy sector in Netherlands suggest that this list is extended.

III(8) Where the goods are proposed to be procured on the basis of Formal Open International Bidding, the importer should forward three copies of the tender notices as soon as these are advertised in the Indian Trade Journal or the Indian Export Service Bulletin, to the Embassy of the Netherlands in India, New Delhi, under intimation to Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section), New Delhi.

III(9) The term "Firm Orders" referred to in Section II(2) means purchase order placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

III(10) The CIF/C&F value of the contract should be expressed in Dutch Guilders in case of contracts concluded with the Dutch suppliers and in the respective currency in case of contracts concluded with the suppliers in eligible source countries.

III(11) The contract must provide for payment on each basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the overseas suppliers.

III(12) The amount of Indian Agent's Commission included in the value of the contract should be specifically indicated. Any payment on this account, should be made in Indian rupees to the Agent in India. No remittance of foreign exchange will be permitted for this purpose. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

III(13) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

III(14) The following provisions should be specifically incorporated in the contract :

- (i) "the contract is subject to the approval of Government of India (if the value of the contract is Dutch Guilders 50,000 or below) and subject to the approval of both the Government of India and the Government of Netherlands (if the value of the contract exceeds Dutch Guilders 50,000).

(ii) This contract will be governed by the payment procedures laid down under the licensing condition for the Dutch General Purpose Credit and will become effective after the Government of India's approval to this effect has been received."

- (iii) "The goods are of Dutch origin/manufacture" (in case of suppliers in Netherlands)

or

"The goods are of.....origin/manufacture" (in case of suppliers in eligible source countries).

- (iv) "For the goods to be imported from Netherlands, the suppliers will have to produce to the Netherlands Investment Bank, a certificate in duplicate issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce of the district in which the supplier is established to the effect that the goods are of Netherlands origin. This certificate can be furnished along with the other shipping documents at the time of receiving payment. A specimen of the certificate is at Annex. III."

In the case of supplier in eligible source countries the suppliers will have to produce to the Netherlands Investment Bank proof of origin of goods in accordance with the Rules of Origin appended to the "Guidelines for Procurement of Goods and Services (Annex. D)."

III(15). For any customary performance guarantee, where required, the suppliers should be asked to furnish a bank guarantee/warranty.

Section IV—Approval of contract by Government of India/Netherlands Investment Bank.

IV(1) Immediately after the contract is concluded, the importer should furnish 5 photostat or certified copies of the contract/supply orders accompanied by a photostat copy of the Import Licence to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W.E. III Section). In case of contracts concluded with suppliers in eligible source countries, 9 copies of the same should be furnished. The importer is also required to furnish the information as per details in Annex. II.

IV(2) When the supply contract is based on formal open International bidding or formal selective International bidding, the following information should also be furnished :—

- (i) Name of the publication in which tender notice was advertised;
- (ii) Name of the parties who quoted against the tender enquiry;
- (iii) The reason for selecting a particular offer indicating whether it was the lowest technically suitable bid.

IV(3) If the contract documents, the request for issue of letter of authorisation and the import licence are found to be in order, the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) will forward copies of the contract to the Dutch authorities through the Embassy of India at The Hague for approval.

IV(4)(a) In respect of contracts valued at DG 50,000 or below, approval of Dutch authorities is not required. The approval of the Government of India will be communicated to the Indian importers while forwarding the copies of their contracts/supply orders to the Dutch Authorities.

(b) For contracts of value exceeding DG. 50,000, as soon as the approval of the Dutch authorities to the financing of the contract under Dutch Credit is received, the importer will be informed that their contract has become effective.

Section V—Payment to the Suppliers :

(A) Payment to the Suppliers in Netherlands

V(1) A Letter of Authority to the Netherlands Investment Bank for Developing Countries, The Hague (in the form at Annex. IV) authorising payment to the suppliers against

shipping documents will be issued and forwarded along with the copies of contract etc., to the Dutch authorities through the Embassy of India at The Hague.

V(2) The validity of the Letter of Authority will be determined keeping in view the delivery schedule indicated in the contract. In no case will the Letter of Authority be made valid beyond the validity of the import licence.

V(3) Since the payments to the suppliers under the credit are generally made by the Dutch Bank against the production of shipping documents, the grace period facility will not be applicable to imports financed under this credit.

V(4) In case the shipment/payments to the suppliers are not completed within the validity period of the Letter of Authority, the Importer should approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section) for suitable extension of the Letter of Authority well before the expiry period of the Letter of Authority. Such a request should be accompanied with a photostat copy of the revaluated Import Licence, if the period of extension sought for is beyond the validity of the original Import Licence.

V(5) If the request for extension in the period of validity of the Letter of Authority is not received within a period of six months from the validity date of the Letter of Authority the un-utilised balance in the Letter of Authority will be deemed to have been surrendered and the Letter of Authority will stand lapsed automatically.

V(6) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Netherlands Investment Bank to the concerned importer's bank in India, which would be a branch of any of the nationalised bank who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the importer has deposited:

(i) the rupee equivalent of the payments to the suppliers in Dutch Guilders at the prevailing composite rate of exchange to be calculated in the manner as prescribed in Chief Controller of Imports & Exports's Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17-1-1976 and as may be notified by the Government from time to time through Public Notices of the C.C.I. & E. or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India;

(ii) interest calculated at the rate of 9% per annum for the first 30 days and at 15 per cent for the period in excess of 30 days in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976 on the amount, required to be deposited vide item (i) above, reckoned from the date of actual payment to the supplier by the Netherlands Investment Bank for Developing Countries N.V., The Hague, to the date of actual deposit of the rupee equivalent by the importer in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or Reserve Bank of India, New Delhi.

V(7) It shall be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licence should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

V(8) Public Sector importers (including Departments of the Central Government) should make the requisite rupee deposit only through Authorised Dealers in foreign exchange and also get the Exchange Control Copy of the Licence endorsed by them as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)/68 dated the 30th August, 1968. The requisite 'S' form will be sent by the concerned bank to the Reserve Bank of India, Bombay.

V(9) The moneys specified in Section V(6) should be deposited only with the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi, or the Reserve Bank of India, New Delhi to the credit of the Central Government Account under the head of account.—

"K—Deposits and advances—Deposit not bearing interest
—843—Civil deposits—Deposits for purchases etc.
abroad—Purchases etc. under Dutch General Purpose Credit 1978-79".

V(10) The advice of rupee deposits referred to above, should be sent to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi by enclosing original receipted treasury challan in the proforma prescribed under Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974, No. 103-ITC(PN)/76, dated 12-10-1976. The information in regard to letter of Authority No., amount of foreign currency for which rupee deposit is made, date of payment of the Dutch supplier, amount of interest and period for which it is calculated should invariably be indicated in the challan form.

(B) Payment to the suppliers in Eligible Source Countries.

V(11) A Letter of Authority (in form at Annex. V) to the Importers' Bank, as indicated by the Importer in his application authorising opening of a Letter of Credit on the suppliers' bank in the eligible source country in favour of the supplier will be issued by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W.E. III Section). Copies of the contract along with a copy of the said Letter of Authority will be forwarded to the Dutch authorities also through the Embassy of India at The Hague.

V(12) On receipt of the Letter of Authority mentioned in the preceding paragraph, the Importer's Bank will open a Letter of Credit in favour of the supplier through his banker within a period of 30 days from the date of issue of the said Letter of Authority and against a valid import licence. An intimation to this effect shall be forwarded to the Controller of Aid Accounts and Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

V(13) After the payment to the supplier is made the supplier's bank shall forward to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping documents and two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by the latter.

V(14) The supplier's bank will also obtain from supplier and furnish to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, a certificate or proof (in duplicate) in regard to the origin of the goods being in accordance with the Rules of origin appended to the "Guideline for Procurement of Goods and Services."

V(15) The importer should forward to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, a certificate of remittance made by them to the supplier against the invoice/shipment of goods excluding bank charges, if any. This certificate should be obtained from the bank through which the Letter of Credit is opened. The importer should also ensure that one set of non-negotiable shipping documents and two copies of invoice with a certificate duly endorsed thereon in regard to receipt of payment by supplier and certificate of origin, referred to in Section V(13) and V(14) are forwarded to Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Controller of Aid Accounts & Audit within 15 days of the shipment of goods.

V(16) Payment against the Letter of Credit will be made by the importer on the strength of the Exchange Control Copy of the Import Licence.

V(17) Normally all shipments/payments to the Supplier should be completed within a period of 20 months from the date of issue of the Letter of Authority referred to above. In case the shipments/payments to the suppliers are not likely to be completed within the period of 20 months, the Importer should invariably approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W.E. III Section) at least a month before the expiry of this limit for completing the shipments/payments to the suppliers. This request should be accompanied with a photostat copy of the revaluated Import Licence covering the period of extension sought for. If such a request is not received before the stipulated period, the un-utilised balances of the contract will be deemed as having been surrendered.

V(18) : Any omission on the part of the importer to send the reimbursement documents promptly to the Department of Economic Affairs will be viewed seriously and the C.C.I.&E. may be asked to suspend all import licences issued in the favour of the importer. In case the importer persists in his default, his case may be recommended to the C.C.I.&E. for being blacklisted. The importer will, in addition, be liable to penalties/punishments under the law governing Import Control etc.

V(19) : On receipt of the reimbursement documents, Controller of Aid Accounts and Audit in the Ministry of Finance, will make a request to the Netherlands Investment Bank for reimbursement of the amount paid to the supplier in the eligible source countries. The Netherlands Investment Bank will reimburse the equivalent amount in Netherlands guilders at the rate of exchange prevailing in the Netherlands on the date of such reimbursement.

Section VI : Miscellaneous

VI(1) : The importer should furnish a quarterly report, as in Annexure VI, showing the utilisation status of the licence to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W.E. III Section).

VI(2) : It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the supplier. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment could be effected to him must be clearly spelt out by the importer in Annex. II. If necessary, a provision dealing with settlement of disputes may be included in the contract itself.

VI(3) : The licensee shall promptly comply with any directions, instructions, or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to import licence and for meeting all obligations under Dutch General Purpose Credit.

VI(4) : Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

ANNEX I

Guidelines for Procurement of goods and services under bilateral development loans by the Netherlands

A. General

1. These guidelines govern procurement of goods and services under bilateral loans which form part of the official Netherlands Development Aid Programme. These loans are used in respect of developing countries. A list of eligible source countries is attached as Appendix A. The recipient country is included in this list. The Netherlands Government may agree, on an individual basis, to limited supplies of goods and services from non-eligible source countries to supplement the supplies from eligible source countries, with transportation and insurance costs included.

2. The Netherlands Government must be satisfied that the proceeds from the loans are to be used with due care being given to economy, efficiency, fairness in international competition and non-discrimination among eligible source countries in accordance with the procurement procedures set out in these guidelines.

3. Except in the cases mentioned in paragraphs 16 and 17, no practices shall be allowed, which could lead to, or result in a particular supplier or the suppliers of a particular country being favoured.

4. The rules of origin and control to be observed by the borrower in the procurement of goods and services, are attached to these guidelines as Appendix B.

5. Where the borrower does not effect direct procurement, he shall make such arrangements as are necessary to ensure that the purchaser complies with these guidelines.

6. (1) The borrower shall obtain goods and services through formal open international bidding except in the following cases :

- (a) where the Netherlands is the traditional or the only source for imports ;

(b) where the value of imports is less than Dfl. 1.25 million ; or

(c) where such a procedure is inapplicable or inappropriate. In this case, agreement between the Netherlands Government and the borrower on another more expedient procedure must be reached before suppliers are invited to submit their bids, such agreement to be reached on the basis of all relevant information to be supplied by the borrower through the Royal Netherlands Embassy.

6. (2) Where in the light of the existing relationship subsisting between the Indian importers and the foreign suppliers and the scope of supplies available and identified in the Netherlands and/or the developing countries, the borrower considers that imports should be effected from the Netherlands only, the borrower shall have the option to confine bids to the Netherlands only or obtain bids from the Netherlands as well as the eligible source countries. In such cases article 30 of the Guidelines along with articles 31-33 or article 30 along with articles 34-38 are applicable.

7. These guidelines, together with the Rules of Origin and the list of eligible source countries, are subject to amendment by the Netherlands Government.

B. Procedures for Formal Open International Bidding

8. At the time invitations to bid are issued, the borrower (or the purchaser on the borrower's behalf) shall advertise the bidding in at least one of the following two publications :

Indian Trade Journal

Indian Export Service Bulletin.

The importer shall send three copies of the tender notices as advertised in the Indian Trade Journal or the Indian Export Service Bulletin, to the Embassy of the Netherlands in India.

9. In order to foster widespread competition individual be of a size large enough to attract bids on an international contracts for which bids are invited should, whenever feasible, be of a size large enough to attract bids on an international basis. On the other hand, if it is possible from a technical and administrative point of view to divide a project into contracts of a specialized nature and such division is likely to be advantageous to the borrower and/or to allow broader international competitive bidding the project should be divided. Single contracts for engineering, equipment and construction work (commonly known as "Turn-key contracts") may be desirable if they offer overall advantages to the borrower country within the technical and economic facilities available.

10. Formal prequalification may be desirable, in particular for civil works contracts. If prequalification is used, it shall be based entirely upon ability to perform satisfactorily, taking into account (i) the firm's previous experience in similar types of work, (ii) its potential with regard to personnel, equipment and plant, and (iii) its financial position and integrity. Advertisement of the prequalification procedure shall be carried out in accordance with the procedure described in paragraph 8. Condensed specifications shall be made available to contractors desiring to be considered for pre-qualification. When prequalification is applied, all firms which fulfil the conditions for prequalification shall be permitted to bid.

11. Bidding documents shall be prepared in one of the languages customarily used in international transactions and shall unless prohibited by law specify that the text of the documents in that language is governing.

12. Specifications shall set forth as clearly and precisely as possible the work to be carried out, the goods and services to be supplied and the place of delivery or installation. Drawings shall be consistent with the text of the specifications; where they are not, the text shall govern. The specifications shall state the principles of evaluations and comparison of bids, which will be taken into account when evaluations are made and bids are compared. The specification shall be worded in such a way as to permit and encourage free and full international competition.

Any additional information, clarification or correction of errors and alterations of specifications and invitations to bid shall be communicated promptly to those who requested the original bidding documents.

13. If national standards are cited to which equipment or material must comply, the specifications shall state that goods meeting other internationally accepted standards, which demand an equal or better quality than the standards mentioned, will also be accepted.

14. Specifications shall be based on performance and potential and should only prescribe registered brand names, catalogue numbers or products of a particular manufacturer if particular spare parts are required or if it has been decided that a certain amount of standardization is necessary to maintain certain essential quality factors. In the last case the specifications shall permit offers of alternative goods which have similar characteristics and whose performance and quality are of a level at least equal to those specified.

15. Invitations to bid shall list the eligible source countries and shall set out the rules of origin applicable.

16. Quotations shall be examined on the basis of strict equality of conditions among suppliers from eligible source countries (including the evaluation of quotations for material and equipment at prices free of customs tariffs and other duties and taxes of like effect). The borrower country, however, is authorized, in the evaluation and comparison of bids to supply goods and services, excluding transport costs, to extend a margin of preference to local goods and services and to products from other eligible source countries which are members of the same regional economic group, consistent with GATT, or which intend to establish such a group, over goods and services originating in other eligible source countries. This margin of reference shall not exceed 15 per cent on the CIF price of the lowest evaluated foreign per cent on the CIF price of the lowest evaluated foreign country, whichever is the lowest.

17. In special cases, the borrower may, after mutual consultation between the Netherlands Government and the borrowing country, extend a limited margin of preference to local and regional manufacturers, consistent with GATT, in addition to the margin of preference, mentioned in paragraph 16. In assessing the level of preference, due attention should be given to factors like the degree of national or regional ownership and management and the registration in the borrower country or the regional economic group of these manufacturing firms.

18. Bidding documents shall set out any preferences agreed upon and specify the manner in which they will be applied in the evaluation and comparison of bids.

19. Bidders shall be given adequate time in which to submit their bids.

20. The date, hour and place for latest receipt of bids and for the bid opening shall be announced in the invitation to bid and all bids shall be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time shall be returned unopened. The name of the bidder and total amount of each bid and of any alternative bids if they have been requested or permitted shall be read aloud and recorded.

21. No bidder shall be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The borrower may ask any bidder for a clarification of his bid but shall not ask any bidder to change the substance or price of his bid.

22. Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning awards shall be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures on the side of either the borrower or the Netherlands Government before the announcement of the award of a contract to the successful bidder.

23. After the opening of the bids, the purchaser shall examine the bids in order to ascertain whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the requirements of the bidding documents, whether the required guarantees and sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the

specifications or contains inadmissible reservations or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it shall be rejected. A technical analysis together with a detailed assessment in monetary terms shall then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

24. Invitations to bid may state that the purchaser reserves the right to reject all bids when none are responsive to the intent of the specifications, when there is evidence of lack of competition, or when the low bids exceed the cost previously estimated by an amount sufficient to justify such action. If all bids are rejected, the borrower may, after consultation with the Netherlands Government, enter into negotiations with one or more of the lowest bidders to ascertain the causes for such events and the reasons for the difference between the low bid and the cost estimates. Negotiated contracts reflecting changes in the specifications, leading to economies in the estimated cost of the project, may be acceptable, provided the changes do not substantially alter the nature of the project. Where changes are substantial, rebidding may be appropriate. This shall at all times be approved by the Netherlands Government.

25. Evaluations of bids shall be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents and in any modifications thereto prior to the closing date for submission of bids. For the purpose of determining the lowest evaluated bid, commercial factors other than price, such as the time of completion of construction or other work, the efficiency and reliability of the equipment, the time of its delivery and the availability of service and spare parts, shall also be taken into consideration and shall, to the largest possible extent, be expressed in monetary terms. The currencies in which bid prices would have to be paid shall be valued, for bid comparison purposes only, on the basis of rates of exchange published by an official source and applicable to similar transactions at the closing date of the bidding.

26. The award of a contract shall be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid, taking into account the factors mentioned in the preceding paragraphs.

27. The Netherlands Government shall, upon request, be given adequate opportunity to present its comments and recommendations on all phases of procurement. After the award of contract, the Netherlands Government shall be provided with (copies of) all relevant documents and other information necessary for the evaluation of the use of the loan.

C. Procurement Procedures other than Formal Open International Bidding.

28. In the cases mentioned in paragraphs 29 and 30, the procurement formulae of paragraphs 31-39 may be applied in accordance with paragraph 6.

29. Standardization

Where the purchaser has convincing reasons for maintaining a reasonable standardization of his equipment.

30. Limited Number of Qualified Suppliers :

In cases where, because of the nature of the procurement in question, the number of qualified suppliers is limited and the market knowledge of the purchaser is such that he can be expected to know the qualified suppliers.

Formal Selective International Bidding

31. Under formal selective international bidding the purchaser is authorized to invite bids from only a limited number of (pre) qualified suppliers known to be able to meet the special requirements of the procurement in question.

In such cases the borrower should ascertain that no potential qualified suppliers have been excluded. The Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Government of India shall provide all necessary information as and when asked for by potential suppliers of eligible source countries to enable them to participate on an equitable basis.

32. The suppliers are to be selected exclusively on the basis of their qualifications and are, as far as possible, to be chosen from several eligible source countries including the Netherlands.

33. All provisions of formal international bidding, other than those of paragraph 8, are to be fully applied.

Informal International Competitive Procurement

34. If procurement is not through the formal competitive bidding procedure, it should be made in accordance with good commercial practice and without discrimination among eligible source countries.

35. The importer should give wide and timely publicity to the intended use of informal international competitive procurement. The Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs), Government of India shall provide all information necessary to permit suppliers of eligible source countries to participate on an equitable basis as and when such information is asked for.

36. The time allowed for the preparation of quotations and offers shall be governed by the nature of the contracts involved. Both lead time and delivery schedules shall be long enough to allow meaningful international competition.

37. The Netherlands Government may require the purchaser in particular cases to supply information on the purchases made, including full details concerning how quotations were obtained, the suppliers who are involved and the quotations received.

38. The guidelines for formal open international bidding should be applied to the fullest possible extent as appropriate.

Single Supplier

39. The purchaser is permitted to purchase directly from a single supplier in one of the following cases :

- (i) procurement by a commercial importer involves a registered brand name commodity which is for resale by the importer, for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the sole distributor or manufacturer;
- (ii) procurement by a commercial importer involves a commodity which is procured for manufacture, processing or assembly and resale of the end product for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the manufacturer;
- (iii) in order to assure interchangeability of parts or because of special design or technical requirements the procurement can only be made from one source;
- (iv) the purchaser is a manufacturer whose equipment and raw material formulas are designed for best utilization with a specific type of raw material which can only be obtained from one source;
- (v) the purchaser wishes to extend or repeat a procurement originally made under formal international bidding provided that the complementary procurement is small in relation to the original procurement, takes place on a few occasions only and while the construction work related to the original procurement is still under way or shortly after the original procurement is made;
- (vi) the value of a transaction is less than Dfl. 1.25 million.

D. Guidelines for the Use of Consultants

40. Consultant firms employed should be independent in the sense that their advice and the designs, specifications and bid documents prepared by them should be free of national, commercial or industrial bias, and can be compiled with on a competitive basis. In considering local consultant firms, due attention should be given to factors like the degree of national ownership, management and personnel and registration.

41. Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consultant firms. However, in the process of selection, borrowers should consider a reasonable number of prospective firms, which can be expected to render competent and independent services from several eligible source countries. This list shall be based on prequalification, taking into account :

- (i) the firm's previous experience in similar types of work;
- (ii) its potential with regard to personnel, equipment and plant; and
- (iii) its financial position and integrity.

It is desirable that, before invitations for proposals are sent out, the borrower submits the list of prospective firms to the Netherlands Government. The Netherlands Government reserves the right to reject the choice of a consultant, and may, further more, on the basis of her knowledge of the consultancy sector in the Netherlands, suggest that this list is extended.

E. Grievances

42. The borrower shall make provision for the hearing and investigation of complaints arising in connection with the invitations to bid, the submission of bids and the award of contracts.

43. In the case of purchases conducted under formal international bidding procedures complaints of any substance, regarding restrictive commodity specification or other restrictive terms of the invitation, made prior to the bid closing date, shall be resolved before the opening of bids. If necessary and only after consultation with the Netherlands Government, the bid closing date may be postponed for an appropriate period.

44. When a complaint has been made by one of the suppliers concerned, the documentation relating to the substance of the complaint and action taken thereon shall be available for examination by the Netherlands Government, as well as by the borrower.

APPENDIX A

List of eligible source countries for United Bilateral Loans to developing countries

A. Netherlands

B. Africa

North of Sahara

Algeria
Ibrian Arab Rep.

Morocco

Tunisia

Egypt

South of Sahara

Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo (People's Rep. of)
Zaire Rep.
Dahomey
Ethiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea Bissau
Ivory Coast
Kenya

Lesotho	Asia
Liberia	Middle East
Malagasy Republic	Bahrein
Malawi	Iran
Mali	Iraq
Mauritania	Israel
Manuritius	Jordan
Nigar	Kuwait
Negeria	Lebanon
Reunion	Oman
Rwanda	Qatar
Senegal	Saudi Arabia
Seychelles	Yemen (People's DR)
Sierra Leone	Syrian (Arab Rep.)
Somalia	Unit. Arab Emirates
Terr. Afars and Issas	Yemen (Arab Rep.)
St. Helena and dependencies	
Sudan	
Swaziland	
Tanzania	South
Togo	Afghanistan
Uganda	Bangladesh
Upper Volta	Bhutan
Zambia	Burma
	India
America	Maldives
North and Central	Nepal
Bahamas	Pakistan
Barbados	Sri Lanka
Bermuda	
Costa Rica	
Cuba	Far East
Dominican Republic	Brunei
El Salvador	Khmer Rep.
Guadeloupe	Hong Kong
Guatemala	Indonesia
Haiti	Korea (Rep. of)
Honduras	Korea (People's Dem. Rep. of)
Honduras (Br.)	Laos
Jamaica	Macao
Martinique	Malaysia
Mexico	Philippines
Netherlands Antilles	Singapore
Nicaragua	Thailand
Panama	Timor
St. Pierre et Miquelon	Vietnam (Rep. of)
Trinidad et Tobago	Vietnam (Dem. Rep. of)
West Indies (Br.)	
South	Oceania
Argentina	Fiji
Bolivia	Gilbert & Ellice Islands
Brazil	French Polynesia
Chile	New Caledonia
Colombia	New Hebrides (Br. & Fr.)
Ecuador	Pacific Islands (US)
Falkland Islands	Papua New Guinea
Guyana	Solomon Islands
Guiana (Fr.)	Tonga
Paraguay	Wallis and Futuna
Pern	Western Samoa
Surinam	
Uruguay	
Venezuela	Europe
	Turkey
	Portugal

APPENDIX 'B'

Rules of Origin

1. The subject items of these rules of origin shall be goods and services produced in the eligible source countries.
2. In the case of goods, assessment of the Netherlands origin shall be subject to the legislation in this field which prevails in the European Community.
3. Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 2 shall be furnished by means of a certificate of origin, issued by a Chamber of Commerce in the Netherlands.
4. In the case of goods, assessment of origin in developing countries shall be subject to the rules of origin which are established by the European Community in the framework of the General System of Preferences.
5. Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 4 shall be furnished by means of a Certificate of Origin, Form A (as in use by the General System of Preferences), issued by an official authority in the developing country.
6. In the case of services (cf. paragraph 1 of the Guidelines), origin shall be assessed, on an ad hoc basis, in mutual consultation between the Netherlands Government and the borrower country.
7. In cases where the Rules of Origin cause substantial problems or serious economic damage to the borrower country (e.g. an over-tight restriction of the number of potential suppliers), deviations from these rules may be permitted, but only after mutual consultation between the Netherlands Government and the borrower country.

ANNEXURE II

- (a) Name and address of the Indian importers and/or Project authority where necessary.
- (b) Name and address of the supplier. In case of suppliers in Eligible Source Countries, the following information should also be furnished—
 - (i) Nationality.
 - (ii) Percentage of the shares held by national of the eligible source countries.
- (c) (i) No. and date of Import Licence.
(ii) Value.
- (d) (i) Name and address of the Supplier's Bank in the Netherlands/Eligible Source Country.
*(ii) The Importers' Bank in India (which will be the bank that has furnished the Bank Guarantee).
**(iii) The importers' Bank in India which will be responsible to make rupee deposits in Government account before releasing shipping documents to the importer.
- (e) Value of the contract order in Dutch Guilders or the currency of the Eligible Source Country.
- (f) Method of Procurement whether it is based on direct purchase or Formal Open International Bidding or Selective Formal International Bidding, in which case it should be indicated whether the contract has been entered into on the basis of the lowest technically suitable offer, with reasons, if any.
- (g) Short description of goods to be imported.
- (h) Origin of goods—percentage of imported components from non-eligible source countries, if any.

*for Private Sector.

**for Public Sector.

- (i) Expected date of completion of deliveries.
- (j) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (k) Detailed list of shipping documents, like Bill of Lading, Invoices, Certificate of Origin, etc., which the Netherlands Investment Bank for Developing Countries or the Suppliers' Bank in Eligible Source Country should demand from the suppliers before making payment, together with the number of copies of each document required.
- (l) Indian Agent's commission, if any, included in the contract (exact amount to be indicated), which will have to be deducted from the contract value while issuing a Letter of Authority. Such commission will be payable by the Importers direct to the Agents in rupees.
- (m) Value of which the Letter of Authority is requested.
- (n) Number, date and value of bank Guarantee, indicating the period upto which it is valid.
- (o) Special instructions, if any.

**ANNEXURE III
DUTCH CREDIT
CONTRACT CERTIFICATE**

Particulars of contract

Indian Import Licence No.....

1. Number and Date of the Contract.....
 2. Description of goods or services to be supplied to the purchaser.....
(If a number of items are to be supplied, a detailed list should be appended to this certificate).
 3. Total contract price payable by purchaser (state CIF, C&F or FOB) Dfl.....
- IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION MUST BE COMPLETED.**
4. Estimated % of the FOB value of the goods not originating in the Netherlands but purchased by the supplier direct from abroad, i.e. % of imported raw material or components used in manufacture.
 - (a) % FOB value.....
 - (b) Description of items and brief specification.....
 5. **IF SERVICES ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION SHOULD ALSO BE COMPLETED.**
 6. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by
 - (a) Your firm (site engineers charges, etc.).....
 - (b) Local supplier.....
 7. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 4 & 5 above.....
 8. I hereby declare that I am employed in the Netherlands by the Supplier named below and have the authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of Netherlands origin will be supplied by the supplier other than those specified in paragraphs 4 & 5 above.

Signed.....

Position hold.....

Name and address of supplier.....

Date.....

Certified

Netherlands Chamber of Commerce . . . District

ANNEXURE IV

No. F. 14()-WE.III/

GOVERNMENT OF INDIA

(Bharat Sarkar)

MINISTRY OF FINANCE

(Vitta Mantralaya)

(Department of Economic Affairs)

(Arthik Karya Vibhag)

New Delhi, the

To

The Netherlands Investment bank for Developing Countries,

The Hague, Netherlands.

Agreement for the loan of

million Netherlands Guilders—

Request for direct payment.

Dear Sirs,

LETTER OF AUTHORITY NO.

With reference to our application of today's date as to the financing of the transaction between M/s. _____

& _____, India and M/s. _____

Holland, out of the loan made by your Bank to India, we hereby request and authorise you unconditionally and irrevocably to pay in accordance with the terms and conditions of the above mentioned contract to the supplier in Holland the amount of N. fl. _____ (Dutch Guilders _____).

It is requested that the invoices, shipping and other documents presented by the Dutch supplier be despatched direct to the _____.

(Importer's Banker).

The suppliers will also be required to furnish to the Netherlands Investment Bank for Developing Countries a certificate in duplicate issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce of the district in which the exporter is established regarding the Netherlands origin of the goods covered under the Letter of Authority.

Kindly forward the debt advice to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid (Accounts) Branch, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi. This letter of Authority will remain valid upto _____.

For the President of India,

Copy to _____

(Importer's Bank).

They should release the negotiable set of documents to the importer only after ensuring that the importer has deposited :

- (i) the rupee equivalent of the payments to the suppliers in Dutch Guilders at the prevailing composite rate of exchange to be calculated in the manner as prescribed in Chief Controller of Imports & Exports's Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17th January, 1976 and as may be notified by the Government from time to time through Public Notices of the C.C.I.&E. or through exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India ;
- (ii) interest calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and at 15 per cent for the period in excess of 30 days in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76, dated 16th June, 1976 on the amount required to be deposited vide item

(i) above, reckoned from the date of actual payment to the supplier by the Netherlands Investment Bank for Developing Countries N.V., The Hague, to the date of actual deposit of the rupee equivalent by the importer in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or Reserve Bank of India, New Delhi.

ANNEXURE V

No. F. 14()-W.E.III/

GOVERNMENT OF INDIA

(Bharat Sarkar)

MINISTRY OF FINANCE

(Vitta Mantralaya)

(Department of Economic Affairs)

(Arthik Karya Vibhag)

New Delhi, the

To

Subject :—Contract entered under General Purpose Dutch Credit—Reimbursement.

Dear Sirs,

Messrs. _____

(Indian importer)

have entered into a contract with Messrs. _____

(Foreign supplier)

for the supply of _____

for the amount of _____ (_____)

_____) C.I.F./C.&F. against Licence No. _____ dated _____ issued under the Dutch General Purpose Credit for the value of Rs. _____ (Rupees _____).

A copy of the contract is enclosed.

2. Out of the above amount of _____ an amount of _____ is to be paid as Indian Agents' Commission in Indian currency. The sum to be paid to the supplier in foreign currency which will be financed initially out of the free foreign exchange resources, to be reimbursed later out of the Dutch General Purpose Credit, therefore, amounts to _____.

3. You are authorised to open a letter of credit in favour of Messrs. _____ through their bankers, viz., Messrs. _____

within a period of thirty days from date of this letter and against a valid Import Licence, under intimation to the Controller of Aid Accounts & Audit, UCO bank Building, Parliament Street, New Delhi.

4. In terms of para 10 Section VII of the Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of the expiry of the Letter of Credit is not later than forty-five (45) days after the final date for shipment as stated in the relative import licence.

5. The letter of credit will also provide that Messrs. _____

(foreign banker)

will forward directly to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping documents and two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the Dutch Supplier that the payment has been received by the latter.

They will also obtain from the suppliers and furnish to the Controller of Aid Accounts & Audit a certificate in duplicate issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce of the district in which the exporter is established regarding the Netherlands origin of the goods covered under the letter of Credit/*issued by the appropriate competent authority in regard to the origin of the goods covered under the letter of Credit.

6. You are also required to forward to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi a certificate of remittance made by you to M/s.

against the invoice/shipment of goods, excluding Bank charges, if any.

7. Receipt of this letter may please be acknowledged.

*To be deleted if not applicable.

Yours faithfully,

Copy with a copy of the contract forwarded to :—

Reserve Bank of India, Exchange Control Department, Bombay-1.

2. Copy also forwarded for information to :—

(i) _____
(Indian importer)

It may be ensured that M/s. _____
(foreign banker)

forward one set of shipping and other documents (non-negotiable) alongwith payment advice, two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by him, and two copies of certificate in regard to origin of goods to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

(ii) M/s. _____
(foreign bank)

It is requested that on each payment, one set of shipping and other documents (non-negotiable), alongwith payment advice, two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by him and two copies of certificate in regard to origin of goods may be forwarded direct to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

(iii) Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

ANNEXURE VI

STATEMENT SHOWING QUARTERLY REPORT ON UTILISATION UNDER DUTCH (G.P.) CREDIT

1. Name of Importer.
2. No. and date of Import Licence.
3. Value of Import Licence.
4. Value of orders placed.
5. Letter of Authority No. and date.
6. Amount of Letter of Authority.
7. Date of Validity of Letter of Authority.
8. Amount utilised during the Quarter. D.G.
9. Total amount utilised. D.G.
10. Total Amount deposited into Government Account. Rs.

11 Payment yet to be made during the subsequent quarters

(2) Surrender, if any.

K. V. SHARMA, Controller of Imports and Exports.

APPENDIX II

II TO DEPARTMENT OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 17—ITC(PN)/79

Dated, the 9th March, 1979

CONDITIONS FOR LICENSING PRIVATE SECTOR IMPORTS UNDER THE DUTCH GENERAL PURPOSE

CREDIT

Section I—General :

I(1) The Dutch General Purpose Credit for 1977-78 extended by the Netherlands Investeringen bank Voor Outwikkellingslanden N. V. is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and commodities and services incidental thereto which are to be financed under the credit can be imported from Netherlands and all countries enumerated in the list at Appendix-A of the "Guidelines for Procurement of Goods and Services under Bilateral Development Loans by the Netherlands" (Annex—I) which will be the "eligible source countries" under the credit. The terminal date of disbursements in both the credit agreements viz. Dfl. 120 million and Dfl. 54 million would be 31st December, 1980.

I(2) Components to the extent of 10 per cent in respect of chemicals and 20 per cent in respect of other imports from non-eligible source countries can, however, be considered for being financed under the credit. Specific requests in this regard, if any, should be made to the Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs), W.E. III Section before finalizing the contract.

I(3) Limited supplies of goods and services from non-eligible source countries to supplement the supplies from eligible source countries in excess of the limit indicated in Section I(2) may also be considered for financing under the credit. For this, specific approval of the Government of Netherlands will be necessary.

Section II—Issue of Import Licence :

II(1) The import licence will be issued on C.I.F. basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the Licensee should approach the licensing Authority concerned within the validity period of the licence who shall consult the Department of Economic Affairs, (W.E. III Section) in the matter.

II(2) Firm order on CIF/C&F basis must be placed on the overseas suppliers in the Netherlands or the countries mentioned in the Annexure I and sent to the Department of Economic Affairs, (W.E. III Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. If firm orders cannot be finalised within the time limit of 4 months the licensee should submit to the Chief Controller of Imports and Exports or other licensing authorities, as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period furnishing justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such requests for extension in the ordering period will be considered on the merits of each case by the licensing authorities who may grant extension upto a further period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of import licence, such proposal should invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (W.E. III Section), Ministry of Finance.

II(3) The licence will bear the superscription 'Dutch General Purpose Credit' and indicate the public notice number under which these licensing conditions are issued. The licence code for the first and second suffix will be "S"/"N". This licence code will be mentioned in all the shipping documents as well as in the "S" form required to be furnished to the Reserve Bank at the time of rupee deposit.

II(4) As soon as the importer receives the import licence, he should send a report to that effect to the Ministry of

Finance, Department of Economic Affairs, (W.E. III Section) along with the following information :

- (i) No. and Date of Import Licence ;
- (ii) Value ;
- (iii) Exchange rate, if any, indicated on Import Licence;
- (iv) Date by which copies of contract are expected to be furnished to Department of Economic Affairs.

Section III—Finalisation of Credit :

III(1) The minimum value of contract eligible for financing under credit is Dfl. 25,000.

III(2) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract will be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

III(3) The contract for the import of goods and services from the Netherlands and eligible source countries should be finalised keeping in view the Guidelines for Procurement of Goods and Services as detailed in Annexure-I.

III(4) Goods and services should be procured through Formal Open International Bidding except in the following cases :

- (a) where the Netherlands is the traditional or the only source for imports ; or
- (b) where the value of imports is less than Dfl. 1.25 million ; or
- (c) where such a procedure is inapplicable or inappropriate. In this case, agreement between the Netherlands Government and the Government of India on another more expedient procedure must be reached before the contract for the supplies could be finalised.

III(5) It would also not be necessary to resort to Formal Open International Bidding in the following type of cases:

- (a) where the purchaser has convincing reasons for maintaining a reasonable standardisation of his equipment,
- (b) in cases where, because of the nature of the Procurement in question, the number of qualified suppliers is limited and the market knowledge of the purchaser is such that he can be expected to know the qualified suppliers,
- (c) where in the light of the existing relationship subsisting between the Indian importers and the foreign suppliers and the scope of supplies available and identified in the Netherlands and/or the developing countries, the borrower considers that imports should be effected from the Netherlands only.

In such cases the procurement formula of paragraphs 31 to 39 of the Guidelines for procurement of Goods and Services (Annexure I) may be followed.

III(6) The purchaser may purchase directly from a single supplier in one of the following cases :

- (i) procurement by a commercial importer involves a registered brand name commodity which is for resale by the importer, for which the importer is a regularly authorised distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the sole distributor or manufacturer ;
- (ii) procurement by a commercial importer involves a commodity which is procured for manufacture, processing or assembly and resale of the end product for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the manufacturer ;

(iii) in order to assure inter-changeability of parts, or because of special design or technical requirements the procurement can only be made from one source ;

- (iv) the importer is a manufacturer whose equipment and raw material formulae are designed for best utilisation with a specific type of raw material which can only be obtained from one source ;
- (v) the importer wishes to extend or repeat a procurement originally made under formal international bidding provided that the complementary procurement is small in relation to the original procurement, takes place on a few occasions only and while the construction work related to the original procurement is still under way or shortly after the original procurement is made ;
- (vi) the value of a transaction is less than Dfl. 1.25 million.

III(7) Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consultant firms. However, before invitations for proposals are sent out by the Indian firms to the consultants firms, a list of such prospective firms should be furnished to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section). The list in turn will be submitted to the Government of Netherlands who may prove the same or reject the choice of a consultant and may on the basis of their knowledge of the consultancy sector in Netherlands suggest that this list is extended.

III(8) Where the goods are proposed to be procured on the basis of Formal Open International Bidding, the importer should forward three copies of the tender notices as soon as these are advertised in the Indian Trade Journal or the Indian Export Service Bulletin to the Embassy of the Netherlands in India, New Delhi under intimation to Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W.E. III Section), New Delhi.

III(9) The term "Firm orders" referred to in Section II (2) means purchase order placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

III(10) The CIF/C&F value of the contract should be expressed in Dutch Guilders in case of contracts concluded with the Dutch suppliers and in the respective currency in case of contracts concluded with the suppliers in eligible source countries.

III(11) The contract must provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the overseas suppliers.

III(12) The amount of Indian Agent's Commission included in the value of the contract should be specifically indicated. Any payment on this account should be made in Indian rupees to the Agent in India. No remittance of foreign exchange will be permitted for this purpose. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

III(13) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

III(14) The following provisions should be specifically incorporated in the contract :

- (i) "the contract is subject to the approval of Government of India (if the value of the contract is Dutch Guilders 50,000 or below) and subject to the approval of both the Government of India and the Government of Netherlands (if the value of the contract exceed Dutch Guilders 50,000);
- (ii) This contract will be governed by the payment procedures laid down under the licensing conditions for the Dutch General Purpose Credit and will become effective after the Government of India's approval to this effect has been received."

- (iii) "The goods are of Dutch origin/manufacture" (in case of suppliers in Netherlands).
or
"The goods are of _____ origin/manufacture" (in case of suppliers in eligible source countries).

- (iv) For the goods to be imported from Netherlands the suppliers will have to produce to the Netherlands Investment Bank, a certificate in duplicate issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce of the district in which the supplier is established to the effect that the goods are of Netherlands origin. This certificate can be furnished along with the other shipping documents at the time of receiving payment. A specimen of the certificate is at Annex III.

In the case of supplier in eligible source countries the suppliers will have to produce to the N.I.O./proof of origin of goods in accordance with the Rules of Origin appended to the "Guidelines for Procurement of Goods and Services" (Annex I).

III (15) For any customary performance guarantee, where required, the suppliers should be asked to furnish a bank guarantee/warranty.

Section IV—Approval of contract by Government of India I NTO.

IV (1) (a) Immediately after the contract is concluded, the importer should furnish 5 photostat or certified copies of the contract/supply orders accompanied by a photostat copy of the Import Licence to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE. III Section). In case of contracts concluded with suppliers in eligible source countries 8 copies of the same should be furnished.

The importer is also required to furnish the information as per details in Annex II.

(b) In case of contracts concluded with Dutch Suppliers, the importer should furnish a bank guarantee from an approved scheduled bank, in the form prescribed (Annex IV) duly adjudicated by the Collector of Stamps. The Bank Guarantee should be for an amount representing the rupee equivalent of the amount of contract for which letter of Authority is sought plus interest and other charges. The rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue and Banking as prevailing on the date of issue of import licence.

(2) When the supply contract is based on formal open international bidding or formal selective International bidding, the following information should also be furnished :

- (i) Name of the publication in which tender notice was advertised;
- (ii) Name of the parties who quoted against the tender enquiry;
- (iii) The reason for selecting a particular offer indicating whether it was the lowest technically suitable bid.

(3) If the contract documents, the request for issue of letter of authorisation, the import licence and Bank Guarantee are found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, will forward copies of the contract to the Dutch authorities through the Embassy of India at The Hague for approval.

(4) In respect of contracts valued at DG 50,000 or below approval of Dutch authorities is not required. The approval of the Government of India will be communicated to the Indian importers while forwarding the copies of their contracts/supply orders to the Dutch Authorities. For contracts of value exceeding DG 50,000, as soon as the approval of the Dutch authorities to the financing of the contract under Dutch Credit is received, the importer will be informed that their contract has become effective.

Section V—Payment to the Suppliers :

(A) Payment to the Suppliers in Netherlands.

V(1): A letter of Authority to the Netherlands Investment Bank for Developing Countries, The Hague (in the form at Annex V) authorising payment to the suppliers against

shipping documents will be issued and forwarded along with the copies of contract etc. to the Dutch authorities through the Embassy of India at The Hague.

V (2): The validity of the letter of authority will be determined keeping in view the delivery schedule indicated in the contract. In no case will be letter of authority be made valid beyond the validity of the import licence.

V (3): Since the payments to the suppliers under the credit are generally made by the Dutch Bank against the production of shipping documents the grace period facility will not be applicable to imports financed under this credit.

V (4): In case the shipment/payments to the suppliers are not completed within the validity period of the Letter of Authority, the Importer should approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W.E. III Section) for suitable extension of the Letter of Authority well before the expiry period of the Letter of Authority. Such a request should be accompanied with a photostat copy of the revalidated Import Licence, if the period of extension sought for is beyond the validity of the original Import Licence and a letter from the bank extending the validity of Bank Guarantee.

V (5): If the request for extension in the period of validity of the Letter of Authority is not received within a period of six months from the validity date of the Letter of Authority, the un-utilised balance in the Letter of Authority will be deemed to have been surrendered and the Letter of Authority will stand lapsed automatically.

V (6): The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the N.I.O. to the concerned importer's bank in India who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the importer has deposited :

(i) the rupee equivalent of the payments to the suppliers in Dutch Guilders at the prevailing composite rate of exchange to be calculated in the manner as prescribed in Chief Controller of Imports & Exports's Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17th January, 1976 and as may be notified by the Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India;

(ii) interest calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and at 15 per cent for the period in excess of 30 days in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16th June, 1976 on the amount required to be deposited vide item (i) above, reckoned from the date of actual payment to the supplier by the Netherlands Investment Bank for Developing Countries N.V., The Hague, to the date of actual deposit of the rupee equivalent by the importer in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or Reserve Bank of India, New Delhi.

V (7): It shall be the responsibility of the Indian bank concerned, to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

V (8): The importers should make the requisite rupee deposit only through Authorised Dealers in foreign exchange and also get the Exchange Control Copy of the Licence endorsed by them as required in Public Notice No. 184-ITC (PN)/68 dated the 30th August, 1968. The requisite 'S' Form will be sent by the concerned bank to the Reserve Bank of India, Bombay.

V (9): The moneys specified in Section V(6) should be deposited only with the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi, or the Reserve Bank of India, New Delhi for credit to the Central Government Account under the head of account —

"K—Deposits and advances—Deposit not bearing interest
—843—Civil deposits—Deposits for purchases etc. abroad—Purchases etc. under Dutch General Purpose Credit 1978-79".

V (10) : The advice of the rupee deposits referred to above, should be sent to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi by enclosing original received treasury challan in the proforma prescribed under Public Notice No. 74-ITCPN/74 dated 31st May, 1974 No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The information in regard to letter of Authority No. amount of foreign currency for which rupee deposit is made, date of payment to the Dutch supplier, amount of interest and period for which it is calculated should invariably be indicated in the challan form.

RE-IMBURSEMENT PROCEDURE

V (11) : In case of import licences where the value is below Rs. 1 lakh, the importer will have the option to adopt the Re-imbursement Procedure provided no payments are required to be withheld for performance etc. Under this system the importers will not be required to furnish the Bank Guarantee but their contract will have to indicate that the mode of payment will be by re-imbursement system. The importer will have to open a Letter of Credit on receipt of the approval of their contract by the Government of India. For this purpose a letter of Authority (Annex VI) to the importer's Bank, as indicated by the importer, authorising opening a Letter of Credit on the suppliers' bank in Netherlands will be issued by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section). Payments against the Letter of Credit will be made by the importer on the strength of the Exchange Control Copy of the Import Licence. Normally all shipments/payments to the suppliers should be completed within a period of 20 months from the date of issue of this said Letter of Authority. In case the shipments/payments to the suppliers are not likely to be completed within the period of twenty months, the Importer should invariably approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, W.E. III Section at least a month before the expiry of this stipulated period for the extension of the time limit for completing the shipments/payments to the Suppliers. This request should be accompanied with a photostat copy of the revalidated Import Licence covering the period of extension sought for. If such a request is not received before the stipulated period, the un-utilized balances of their contract will be deemed as having been surrendered. The importer will furnish to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Parliament Street, New Delhi-1, within 15 days of the shipment of goods a certificate from his Bank of payment made to the supplier and also two copies of the invoice bearing a certificate from the Dutch supplier to the effect that "he received a sum of _____ Dutch Guilders amounting to 100 per cent of the invoice value or shipment of goods." He will also ensure that two copies of the certificate in regard to origin of Goods referred to in Section III (14)(iv) are furnished by the supplier to the Controller of Aid Accounts and Audit within the stipulated period of 15 days of the shipment of goods. Any omission on the part of the importers to send the re-imbursement documents promptly to the Department of Economic Affairs will be viewed seriously and the C.C.I.&E. may be asked to suspend all import licences in the name of the importer. In case the importer persists in his default his case may be recommended to the C.C.I.&E. for being blacklisted. The importer will in addition be liable to penalties/punishment under the law governing Import Control etc. In case the importer decides to adopt the reimbursement procedure, he should furnish 9 photostat/certified copies of the contract while seeking approval of his contract by Ministry of Finance.

B. Payment to the suppliers in Eligible Source Countries.

V (12) : A Letter of Authority (in form at Annex VI) to the Importers' Bank, as indicated by the Importer in his application authorising opening of a Letter of Credit on the suppliers' bank in the eligible source country in favour of the supplier will be issued by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section). Copies of the contract along with a copy of the said Letter of Authority will be forwarded to the Dutch authorities also through the Embassy of India at The Hague.

V (13) : On receipt of the Letter of Authority mentioned in the preceding paragraphs, the Importer's Bank will open a Letter of Credit in favour of the supplier through his banker within a period of 30 days from the date of issue of the said Letter of Authority and against a valid import licence. An intimation to this effect shall be forwarded to the Controller of Aid Accounts & Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

V (14) : After the payment to the supplier is made the supplier's bank shall forward to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping documents and two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by the latter.

V (15) : The supplier's bank will also obtain from supplier and furnish to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi a certificate or proof (in duplicate) in regard to the origin of the goods being in accordance with the Rules of origin appended to the Guidelines for Procurement of Goods and Services.

V (16) : The importer should forward to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, a certificate of remittance made by them to the supplier against the invoice/shipment of goods excluding bank charges, if any. This certificate should be obtained from the bank through which the Letter of Credit is opened. The importer should also ensure that one set of non-negotiable shipping documents, two copies of invoice with a certificate duly endorsed thereon in regard to receipt of payment by supplier and certificate of origin referred in Sections V (14) and V (15) are forwarded to Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Controller of Aid Accounts & Audit within 15 days of the shipment of goods.

V (17) : Payment against the Letter of Credit will be made by the importer on the strength of the Exchange Control Copy of the Import Licence.

V (18) : Normally all shipments/payments to the supplier should be completed within a period of 20 months from the date of issue of the Letter of Authority referred to above. In case the shipments/payments to the suppliers are not likely to be completed within the period of 20 months, the Importer should invariably approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section) at least a month before the expiry of this limit for completing the shipments/payments to the Suppliers. This request should be accompanied with a photostat copy of the revalidated Import Licence covering the period of extension sought for. If such a request is not received before the stipulated period, the un-utilised balances of the contract will be deemed as having been surrendered.

V (19) : Any omission on the part of the importer to send the reimbursement documents promptly to the Department of Economic Affairs will be viewed seriously and the C.C.I.&E. may be asked to suspend all import licences issued in the favour of the importer. In case the importer persists in his default, his case may be recommended to the C.C.I.&E. for being black listed. The importer will in addition be liable to penalties/punishments under the law governing Import Control etc.

V (20) : On receipt of the reimbursement documents, Controller of Aid Accounts and Audit, in the Ministry of Finance, will make a request to the Netherlands Investment Bank for reimbursement of the amount paid to the supplier in the eligible source countries. The Netherlands Investment Bank will reimburse the equivalent amount in Netherlands guilders at the rate of exchange prevailing in the Netherlands on the date of such reimbursement.

Section VI : Miscellaneous :

VI(1) : The importer should furnish a quarterly report, as in Annex VII, showing the utilisation status of the licence to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section).

(2) It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the supplier. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment could be effected to him must be clearly spelt out by the importer in Annex II. If necessary, a provision dealing with settlement of disputes may be included in the contract itself.

(3) The licensee shall promptly comply with any directions, instructions, or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to import licence and for meeting all obligations under Dutch General Purpose Credit.

(4) Any breach/violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

ANNEXURE I

Guidelines for Procurement of good and services under bilateral development loans by the Netherlands.

A. General

1. These guidelines govern procurement of goods and services under bilateral loans which form part of the official Netherlands Development Aid Programme. These loans are untied in respect of developing countries. A list of eligible source countries is attached as Appendix A. The recipient country is included in this list. The Netherlands Government may agree, on an individual basis, to limited supplies of goods and services from non-eligible source countries to supplement the supplies from eligible source countries, with transportation and insurance costs included.

2. The Netherlands Government must be satisfied that the proceeds from the loans are to be used with due care being given to economy, efficiency, fairness in international competition and non-discrimination among eligible source countries, in accordance with the procurement procedures set out in these guidelines.

3. Except in the cases mentioned in paragraphs 16 and 17, no practices shall be allowed, which could lead to, or result in a particular supplier or the suppliers of a particular country being favoured.

4. The rules of origin and control to be observed by the borrower in the procurement of goods and services, are attached to these guidelines as Appendix B.

5. Where the borrower does not effect direct procurement he shall make such arrangements as are necessary to ensure that the purchaser complies with these guidelines.

6. (1) The borrower shall obtain goods and services through formal open international bidding except in the following cases :

- (a) where the Netherlands is the traditional or the only source for imports ;
- (b) where the value of imports is less than Dfl. 1.25 million; or
- (c) where such a procedure is inapplicable or inappropriate. In this case, agreement between the Netherlands Government and the borrower on another more expedient procedure must be reached before suppliers are invited to submit their bids, such agreement to be reached on the basis of all relevant information to be supplied by the borrower through the Royal Netherlands Embassy.

6. (2) Where in the light of the existing relationship subsisting between the Indian importers and the foreign suppliers and the scope of supplies available and identified in the Netherlands and/or the developing countries, the borrower considers that imports should be effected from the Netherlands only, the borrower shall have the option to confine bids to the Netherlands only or obtain bids from the Netherlands as well as the eligible source countries. In such cases article 30 of the Guidelines along with articles 31-33 or article 30 along with articles 34-38 are applicable.

7. These guidelines, together with the Rules of Origin and the list of eligible source countries, are subject to amendment by the Netherlands Government.

B Procedures for Formal Open International Bidding

8. At the time invitations to bid are issued, the borrower (or the purchaser on the borrower's behalf) shall advertise the bidding in at least one of the following two publications :

Indian Trade Journal Indian Export Service Bulletin

The importer shall send three copies of the tender notices as advertised in the Indian Trade Journal or the Indian Export Service Bulletin, to the Embassy of the Netherlands in India.

9. In order to foster widespread competition, individual contracts for which bids are invited should whenever feasible, be of a size large enough to attract bids on an international basis. On the other hand, if it is possible from a technical and administrative point of view to divide a project into contracts of a specialized nature and such division is likely to be advantageous to the borrower and/or to allow broader international competitive bidding the project should be divided. Single contracts for engineering, equipment and construction work (commonly known as "Turnkey contracts") may be desirable if they offer overall advantages to the borrower country within the technical and economic facilities available.

10. Formal prequalification may be desirable, in particular for civil works contracts. If prequalification is used, it shall be based entirely upon ability to perform satisfactorily, taking into account (i) the firm's previous experience in similar types of work, (ii) its potential with regard to personnel, equipment and plant, and (iii) its financial position and integrity. Advertisement of the prequalification procedure shall be carried out in accordance with the procedure described in paragraph 8. Condensed specifications shall be made available to contractors desiring to be considered for prequalification. When prequalification is applied, all firms which fulfil the conditions for prequalification shall be permitted to bid.

11. Bidding documents shall be prepared in one of the languages customarily used in international transactions and shall unless prohibited by law specify that the text of the documents in that language is governing.

12. Specifications shall set forth as clearly and precisely as possible the work to be carried out, the goods and services to be supplied and the place of delivery or installation. Drawings shall be consistent with the text of the specifications; where they are not, the text shall govern. The specifications shall state the principles of evaluations and comparison of bids, which will be taken into account when evaluations are made and bids are compared. The specifications shall be worded in such a way as to permit and encourage free and full international competition.

Any additional information, clarification or correction of errors and alterations of specifications and invitations to bid shall be communicated promptly to those who requested the original bidding documents.

13. If national standards are cited to which equipment or material must comply, the specifications shall state that goods meeting other internationally accepted standards, which demand an equal or better quality than the standards, mentioned, will also be accepted.

14. Specifications shall be based on performance and potential and should only prescribe registered brand names, catalogue numbers or products of a particular manufacturer if particular spare parts are required or if it has been decided that a certain amount of standardization is necessary to maintain certain essential quality factors. In the last case the specifications shall permit offers of alternative goods which have similar characteristics and whose performance and quality are of a level at least equal to those specified.

15. Invitations to bid shall list the eligible source countries and shall set out the rules of origin applicable.

16. Quotations shall be examined on the basis of strict equality of conditions among suppliers from eligible source countries (including the evaluation of quotations for material and equipment at prices free of customs tariffs and other duties and taxes of like effect). The borrower country, however, is authorized, in the evaluation and comparison of bids to supply goods and services, excluding transport costs, to extend a margin of preference to local goods and services and to products from other eligible source countries which are members of the same regional economic group, consistent with GATT, or which intend to establish such a group, over goods and services originating in other eligible source

countries. This margin of preference shall not exceed 15 per cent on the CIF price of the lowest evaluated foreign bid or the existing level of customs duties of the bidder's country, whichever is the lowest.

17. In special cases, the borrower may, after mutual consultation between the Netherlands Government and the borrowing country, extend a limited margin of preference to local and regional manufacturers, consistent with GATT, in addition to the margin of preference, mentioned in paragraph 16. In assessing the level of preference, due attention should be given to factors like the degree of national or regional ownership and management and the registration in the borrower country or the regional economic group of these manufacturing firms.

18. Bidding documents shall set out any preferences agreed upon and specify the manner in which they will be applied in the evaluation and comparison of bids.

19. Bidders shall be given adequate time in which to submit their bids.

20. The date, hour and place for latest receipt of bids and for the bid opening shall be announced in the invitations to bid and all bids shall be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time shall be returned unopened. The name of the bidder and total amount of each bid and of any alternative bids if they have been requested or permitted shall be read aloud and recorded.

21. No bidder shall be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The borrower may ask any bidder for a clarification of his bid but shall not ask any bidder to change the substance or price of his bid.

22. Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning awards shall be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures on the side of either the borrower or the Netherlands Government before the announcement of the award of a contract to the successful bidder.

23. After the opening of the bids, the purchaser shall examine the bids in order to ascertain whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the requirements of the bidding documents, whether the required guarantees and sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications or contains inadmissible reservations or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it shall be rejected. A technical analysis together with a detailed assessment in monetary terms shall then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

24. Invitations to bid may state that the purchaser reserves the right to reject all bids when none are responsive to the intent of the specifications, when there is evidence of lack of competition, or when the low bids exceed the cost previously estimated by an amount sufficient to justify such action. If all bids are rejected, the borrower may, after consultation with the Netherlands Government, enter into negotiations with one or more of the lowest bidders to ascertain the causes for such events and the reasons for the difference between the low bid and the cost estimates. Negotiated contracts reflecting changes in the specifications, leading to economies in the estimated cost of the project, may be acceptable, provided the changes do not substantially alter the nature of the project. Where changes are substantial, rebidding may be appropriate. This shall at all times be approved by the Netherlands Government.

25. Evaluations of bids shall be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents and in any modifications thereto prior to the closing date for submission of bids. For the purpose of determining the lowest evaluated bid, commercial factors other than price, such as the time of completion of construction or other work, the efficiency and reliability of the equipment, the time of its

delivery and the availability of service and spare parts, shall also be taken into consideration and shall, to the largest possible extent, be expressed in monetary terms. The currencies in which bid prices would have to be paid shall be valued, for bid comparison purposes only, on the basis of rates of exchange published by an official source and applicable to similar transactions at the closing date of the bidding.

26. The award of a contract shall be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid, taking into account the factors mentioned in the preceding paragraphs.

27. The Netherlands Government shall, upon request, be given adequate opportunity to present its comments and recommendations on all phases of procurement. After the award of contract, the Netherlands Government shall be provided with (copies of) all relevant documents and other information necessary for the evaluation of the use of the loan.

C. Procurement Procedures other than Formal Open International Bidding.

28. In the cases mentioned in paragraphs 29 and 30, the procurement formulae of paragraphs 31—39 may be applied in accordance with paragraph 6.

29. Standardization

Where the purchaser has convincing reasons for maintaining a reasonable standardization of his equipment.

30. Limited Number of Qualified Suppliers :

In cases where, because of the nature of the procurement in question, the number of qualified suppliers is limited and the market knowledge of the purchaser is such that he can be expected to know the qualified suppliers.

Formal Selective International Bidding

31. Under formal selective international bidding the purchaser is authorized to invite bids from only a limited number of (pre) qualified suppliers known to be able to meet the special requirements of the procurement in question.

In such cases the borrower should ascertain that no potential qualified suppliers have been excluded. The Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Government of India shall provide all necessary information as and when asked for by potential suppliers of eligible source countries to enable them to participate on an equitable basis.

32. The suppliers are to be selected exclusively on the basis of their qualifications and are, as far as possible, to be chosen from several eligible source countries including the Netherlands.

33. All provisions of formal international bidding, other than those of paragraph 8, are to be fully applied.

Informal International Competitive Procurement

34. If procurement is not through the formal competitive bidding procedures, it should be made in accordance with good commercial practice and without discrimination among eligible source countries.

35. The importer should give wide and timely publicity to the intended use of informal international competitive procurement. The Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs), Government of India shall provide all information necessary to permit suppliers of eligible source countries to participate on an equitable basis as and when such information is asked for.

36. The time allowed for the preparation of quotations and offers shall be governed by the nature of the contracts involved. Both lead time and delivery schedules shall be long enough to allow meaningful international competition.

37. The Netherlands Government may require the purchaser in particular cases to supply information on the purchases made, including full details concerning how quotations were obtained, the suppliers who are involved and the quotations received.

38. The guidelines for formal open international bidding should be applied to the fullest possible extent as appropriate.

Single Supplier.

39. The purchaser is permitted to purchase directly from a single supplier in one of the following cases :

- (i) procurement by a commercial importer involves a registered brand name commodity which is for resale by the importer, for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the sole distributor or manufacturer ;
- (ii) procurement by a commercial importer involves a commodity which is procured for manufacture, processing or assembly and resale of the end product for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the manufacturer ;
- (iii) in order to assure interchangeability of parts or because of special design or technical requirements the procurement can only be made from one source;
- (iv) the purchaser is a manufacturer whose equipment and raw material formulate are designed for best utilization with a specific type of raw material which can only be obtained from one source ;
- (v) the purchaser wishes to extend or repeat a procurement originally made under formal international bidding provided that the complementary procurement is small in relation to the original procurement takes place on a few occasions only and while the construction work related to the original procurement is still under way or shortly after the original procurement is made ;
- (vi) the value of a transaction is less than Dfl. 1.25 million.

D. Guidelines for the Use of Consultants

40. Consultant firms employed should be independent in the sense that their advice and the designs, specifications and bid documents prepared by them should be free of national, commercial or industrial bias, and can be complied with on a competitive basis. In considering local consultant firms, due attention should be given to factors like the degree of national ownership, management and personnel and registration.

41. Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consultant firms. However, in the process of selection, borrowers should consider a reasonable number of prospective firms, which can be expected to render competent and independent services from several eligible source countries. This list shall be based on prequalification, taking into account :

- (i) the firm's previous experience in similar types of work ;
- (ii) its potential with regard to personnel, equipment and plant ; and
- (iii) its financial position and integrity.

It is desirable that, before invitations for proposals are sent out, the borrower submits the list of prospective firms to the Netherlands Government. The Netherlands Government reserves the right to reject the choice of a consultant, and may, further more, on the basis of her knowledge of the consultancy sector in the Netherlands, suggest that this list is extended.

E. Grievances

42. The borrower shall make provision for the hearing and investigation of complaints arising in connection with the invitations to bid, the submission of bids and the award of contracts.

43. In the case of purchase, conducted under formal international bidding procedures complaints of any substance, regarding restrictive commodity specification or other restrictive terms of the invitation, made prior to the bid closing date, shall be resolved before the opening of bids. If necessary and only after consultation with the Netherlands Government, the bid closing date may be postponed for an appropriate period.

44. When a complaint has been made by one of the suppliers concerned, the documentation relating to the substance of the complaint and action taken thereon shall be available for examination by the Netherlands Government, as well as by the borrower.

APPENDIX-A

List of eligible source countries for united bilateral loans to developing countries.

A. Netherlands

B. Africa

North of Sahara

Algeria

Libyan Arab Rep.

Morocco

Tunisia

Egypt

South of Shara

Botswana

Burundi

Cameroon

Cape Verde Islands

Central African Rep.

Chad

Comoro Islands

Congo (People's Rep. of)

Zaire Rep.

Dahomacy

Ethiopia

Gabon

Gambia

Ghana

Gulnea

Guinea Bissau

Ivory Coast

Kenya

Lesotho

Liberia

Malagasy Republic

Malawi

Mali

Mauritania

Mauritius

Niger

Negeria

Reunion

Rwanda

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalia

Terr. Afars and Issas

St. Helena and dependencies

Sudan

Swaziland

Tanzania

Togo

Uganda

Upper Volta

Zambia

America**North and Central**

Bahamas

Barbades

Barbados

Bermuda

Costa Rica

Cuba

Dominican Republic

El Salvador

Guadeloupe

Guatemala

Haiti
Honduras
Honduras (Br.)
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre et Miquelon
Trinidad et Tobago
West Indies (Br.)

South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Falkland Islands
Guyana
Guiana (Fr.)
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay
Venezuela

Asia

Middle East
Bahrain
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Kuwait
Lebanon
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Yemen (People's DR)
Syrian (Arab. Rep.)
Unit. Arab Emirates
Yemen (Arab. Rep.)

South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Maldives
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

Far East

Brunei
Khmer Rep.
Hong Kong
Indonesia
Korea (Rep. of)
Korea (People's Dem. Rep. of)
Laos
Macao
Malaysia
Philippines
Singapore
Thailand
Timor
Vietnam (Rep. of)
Vietnam (Dem. Rep. of)

Oceania

Fiji
Gilbert & Ellice Islands
French Polynesia
New Caledonia
New Hebrides (Br. & Fr.)

Pacific Islands (US)
Papua New Guinea
Solomon Islands
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

Europe

Turkey
Portugal

APPENDIX 'B'

Rules of Origin

1. The subject items of these rules of origin shall be goods and services produced in the eligible source countries.

2. In the case of goods assessment of the Netherlands origin shall be subject to the legislation in this field which prevails in the European Community.

3. Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 2 shall be furnished by means of a certificate of origin, issued by a Chamber of Commerce in the Netherlands.

4. In the case of goods, assessment of origin in developing countries shall be subject to the rules of origin which are established by the European Community in the framework of the General System of Preferences.

5. Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 4 shall be furnished by means of Certificate of Origin, Form A (as in use by the General System of Preferences), issued by an official authority in the developing country.

6. In the case of services (cf. paragraph 1 of the Guidelines), origin shall be assessed, on an ad hoc basis, in mutual consultation between the Netherlands Government and the borrower country.

7. In cases where the Rules of Origin cause substantial problems of serious economic damage to the borrower country (e. g. an over-tight restriction of the number of potential suppliers), deviations from these rules may be permitted, but only after mutual consultation between the Netherlands Government and the borrower country.

ANNEXURE II

(a) Name and address of the Indian importer and/or Project authority where necessary.

(b) Name and address of the supplier. In case of suppliers in Eligible Source Countries, the following information should also be furnished :—

(i) Nationality.

(ii) Percentage of the shares held by national of the eligible source countries.

(c) (i) No. and date of Import Licence

(ii) Value.

(d) (i) Name and address of the Supplier's Bank in the Netherlands/Eligible Source Country.

*(ii) The Importers' Bank in India (which will be the bank that has furnished the Bank Guarantee).

**(iii) The importers' Bank in India which will be responsible to make rupee deposits in Government account before releasing shipping documents to the importer.

(e) Value of the contract order in Dutch Guilders or the currency of the Eligible Source Country.

(f) Method of Procurement whether it is based on direct purchase or Formal Open International Bidding or Selective Formal International Bidding, in which case it should be

*For Private Sector.

**For Public Sector.

Indicated whether the contract has been entered into on the basis of the lowest technically suitable offer, with reasons, if any.

- (g) Short description of goods to be imported.
- (h) Origin of Goods—percentage of imported components from non-eligible source countries, if any.
- (i) Expected date of completion of deliveries.
- (j) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (k) Detailed list of shipping documents, like Bill of Lading, Invoices, Certificate of Origin, etc., which the Netherlands Investment bank for Developing Countries or the Suppliers' Bank in Eligible Source Country should demand from the suppliers before making payment, together with the number of copies of each document required.
- (l) Indian Agent's commission, if any, included in the contract (exact amount to be indicated) which will have to be deducted from the contract value while issuing a Letter of Authority. Such commission will be payable by the Importers direct to the Agents in rupees.
- (m) Value of which the Letter of Authority is requested.
- (n) Number, date and value of Bank Guarantee, indicating the period upto which it is valid.
- (o) Special instructions, if any.

ANNEXURE III

DUTCH CREDIT CONTRACT CERTIFICATE

Particulars of contract

- Indian Import Licence No.
1. Number and Date of the Contract.....
2. Description of goods or services to be supplied to the purchaser
- (If a number of items are to be supplied, a detailed list should be appended to this certificate).
3. Total contract price payable by purchaser (state CIF, C&F or FOB) Dfl.....

If goods are to be supplied the following section must be completed

4. Estimated per cent of the FOB value of the goods not originating in the Netherlands but purchased by the supplier direct from abroad, i.e. per cent of imported raw material or components used in manufacture.

- (a) per cent FOB value.....
- (b) Description of items and brief specification.....
5. If Services are to be supplied the following section should also be completed.
6. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by (a) Your firm (site engineers charges, etc.).....
(b) Local supplier.....
7. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 4 & 5 above.....

8. I hereby declare that I am employed in the Netherlands by the Supplier named below and have the authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of Netherlands origin will be supplied by the supplier other than those specified in paragraphs 4 & 5 above.

Signed:.....
Position hold:.....

Name and address of supplier.....

Date.....

Certified

Netherlands Chamber of Commerce.....District

ANNEXURE IV

GUARANTEE BOND

(To be furnished by Banks under the procedure for the import of goods under the Dutch General Purpose Credit).

To

The President of India.

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Dutch Guilders for the import of _____ by _____ (hereinafter called the Importers) against the import licence number _____ issued under the terms and conditions of the Dutch General Purpose Credit and in pursuance of Import in favour of the Importer against the above-mentioned agreement, we _____ (Bank) at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amounts of the disbursements made by the Netherlands Investmentbank for Developing Countries, The Hague, nominated by the importer converted at the prevailing composite rate of exchange calculated as per Public Notices issued by the Government in the matter from time to time within ten days of the receipt of advice of payments for credit to the Government account, in the manner and against the appropriate Head of Account as indicated by Government of India under the said Credit together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof (as prescribed in Public Notice No. 46-ITC (PN)/76, dated 16-6-1976) reckoned from the date of payment to the Dutch supplier to the date of payment of rupee equivalent for Credit to the Government Account. The negotiable set of import documents received from the Netherlands Investmentbank for Developing Countries. The Hague will be released to the importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We the _____ (Bank) also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the Importer of any sum that may be due and payable from time to time by the Importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct such sums not exceeding Rs. _____ or any part thereof for the time being due and payable by the Importer, together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof (vide Public Notice ibid) reckoned from the date of payment to the Dutch Supplier to the date of actual deposit of the rupee equivalent into Government account. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us _____ (Bank), shall be final and binding on us _____ (Bank).

3. We _____ (Bank) further agree that in case of increase in the value of import or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange mentioned in para 1 above, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place in proportion to this change.

4. We _____ (Bank), further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by change in the constitution of the Importer or the _____(Bank), and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the importer and the _____(Bank), shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise by the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given to the Importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the Importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the _____(Bank) from its such liability.

6. We _____(Bank), lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency, except with previous consent of the Government, in writing.

7. We _____(Bank), hereby undertake to make additional deposits in terms of Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 and such other Public Notices that may be issued from time to time hereafter.

8. Our liability under this guarantee is restricted to Rs. _____(plus interest and other charges, if any, not expected to exceed one per cent of the guarantee amount) and this guarantee shall remain in force till the _____day* of _____(month), 19_____. Unless claims under this guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter i.e. upto _____, all Government's rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Date the _____ day of _____
For _____(Bank).

Accepted for and on behalf of
the President of India by

Shri _____
(Name & designation)

Signature _____

*This date shall be arrived at by adding one month to the date by which all payments to the Suppliers are expected to be finalised.

Note.—The value of the stamped paper on which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Sections 31 of the Indian Stamps Act.

ANNEXURE V

N F. 14 ()-WE.III

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)

(Department of Economic Affairs)
(Arthik Karya Vibhag)
New Delhi,

To

The Netherlands Investmentbank for Developing Countries, The Hague, Netherlands.

Agreement for the loan of _____ million Netherlands Guilders—Request for direct payment.

Dear Sirs,

LETTER OF AUTHORITY NO.

With reference to our application of today's date as to the financing of the transaction between M/s.

&....., India and M/s.

....., Holland, out of the loan made by your Bank to India, we hereby request and authorise you

unconditionally and irrevocably to pay in accordance with the terms of conditions of the above mentioned contract to the supplier in Holland the amount of N. fl....
.....(Dutch Guilders)

It is requested that the invoices, shipping and other documents presented by the Dutch supplier be despatched direct to the
(Importer's Banker).

The suppliers will also be required to furnish to the Netherlands Investmentbank for Developing Countries a certificate in duplicate issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce of the district in which the exporter is established regarding the Netherlands origin of the goods covered under the Letter of Authority.

Kindly forward the debt advice to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid (Accounts) Branch, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi. This letter of Authority will remain valid upto

For the President of India,

Copy to
(Importer's Bank).

They should release the negotiable set of documents to the importer only after ensuring that the importer has deposited :—

- (i) the rupee equivalent of the payments to the suppliers in Dutch Guilders at the prevailing composite rate of exchange to be calculated in the manner as prescribed in Chief Controller of Imports & Export's Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17-1-1976 and as may be notified by the Government from time to time through Public Notices of the C.C.I.E., or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India ;
- (ii) interest calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and at 15 per cent for the period in excess of 30 days in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976 on the amount required to be deposited vide item (i) above, reckoned from the date of actual payment to the supplier by the Netherlands Investment Bank for Developing Countries N.V., The Hague, to the date of actual deposit of the rupee equivalent by the importer in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or Reserve Bank of India, New Delhi.

ANNEXURE VI

No. F. 14()-WE.III/

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)

MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)

(Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag))

New Delhi, the.....

Subject:—Contract entered under General Purpose Dutch Credit—Reimbursement.

Dear Sirs,

Messrs.

(Indian importer)

have entered into a contract with Messrs.

(Foreign supplier)

for the supply of

for the amount of (.....)

.....) C.I.F. C. & F. against Licence No.
..... dated issued under
the Dutch General Purpose Credit for the value of Rs
..... (Rupees
.....
.....
.....
.....).

A copy of the contract is enclosed.

2. Out of the above amount of an amount of is to be paid as Indian Agents' Commission in Indian currency. The sum to be paid to the supplier in foreign currency which will be financed initially out of the free foreign exchange resources, to be reimbursed later out of the Dutch General Purpose Credit, therefore, amounts to

3. You are authorised to open a letter of credit in favour
of Messrs.

.....through their bankers, viz. within a period of thirty days from date of this letter and against a valid Import Licence, under intimation to the Controller of Aid Accounts & Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

4. In terms of para 10 Section VII of the Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of the expiry of the Letter of Credit is not later than forty-five (45) days after the final date for shipment as stated in the relative import licence.

5. The letter of credit will also provide that Messrs.....

(foreign banker)

(Foreign Counter)
will forward directly to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping documents and two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the Dutch Supplier that the payment has been received by the latter.

They will also obtain from the suppliers and furnish to the Controller of Aid Accounts & Audit a certificate in duplicate issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce of the district in which the exporter is established regarding the Netherlands origin of the goods covered under the Letter of Credit [*] issued by the appropriate competent authority in regard to the origin of the goods covered under the Letter of Credit.

6. You are also required to forward to the Controller of Ald Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, a certificate of remittance made by you to M[s].

against the invoice|shipment of goods, excluding Bank charges, if any.

7. Receipt of this letter may please be acknowledged.

*To be deleted if not applicable.

Yours faithfully,

Copy with a copy of the contract forwarded to :—
Reserve Bank of India, Exchange Control Department,
Bombay-1.

2. Copy also forwarded for information to :—

(i)

It may be ensured that M/s
(foreign banker)

forward one set of shipping and other documents (non-negotiable) alongwith payment advice, two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by him, and two copies of certificate in regard to origin of goods to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building Parliament Street, New Delhi.

(ii) M|s.
(foreign bank)

It is requested that on each payment, one set of shipping and other documents (non-negotiable) alongwith payment advice, two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by him and two copies of certificate in regard to origin of goods may be forwarded direct to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

(iii) Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

ANNEX. VII

**STATEMENT SHOWING QUARTERLY REPORT ON
UTILISATION UNDER DUTCH (G.P.) CREDIT**

1. Name of Importer.
 2. No. and date of Import Licence.
 3. Value of Import Licence.
 4. Value of orders placed.
 5. Letter of Authority No. and date.
 6. Amount of Letter of Authority.
 7. Date of Validity of Letter of Authority.
 8. Amount utilised during the Quarter. D.G.
 9. Total amount utilised. D.G.
 10. Total Amount deposited into Government Account. Rs.
 11. Payment yet to be made during the subsequent quarters.
 12. Surrenders if any.

**K. V. SESHA DRI, Chief Controller of
Imports & Exports**

